₹ 20

www.kewalsach.com

निर्भीकता हमारी पहचान

मई 2026

# केवल सच

हिन्दी मासिक पत्रिका

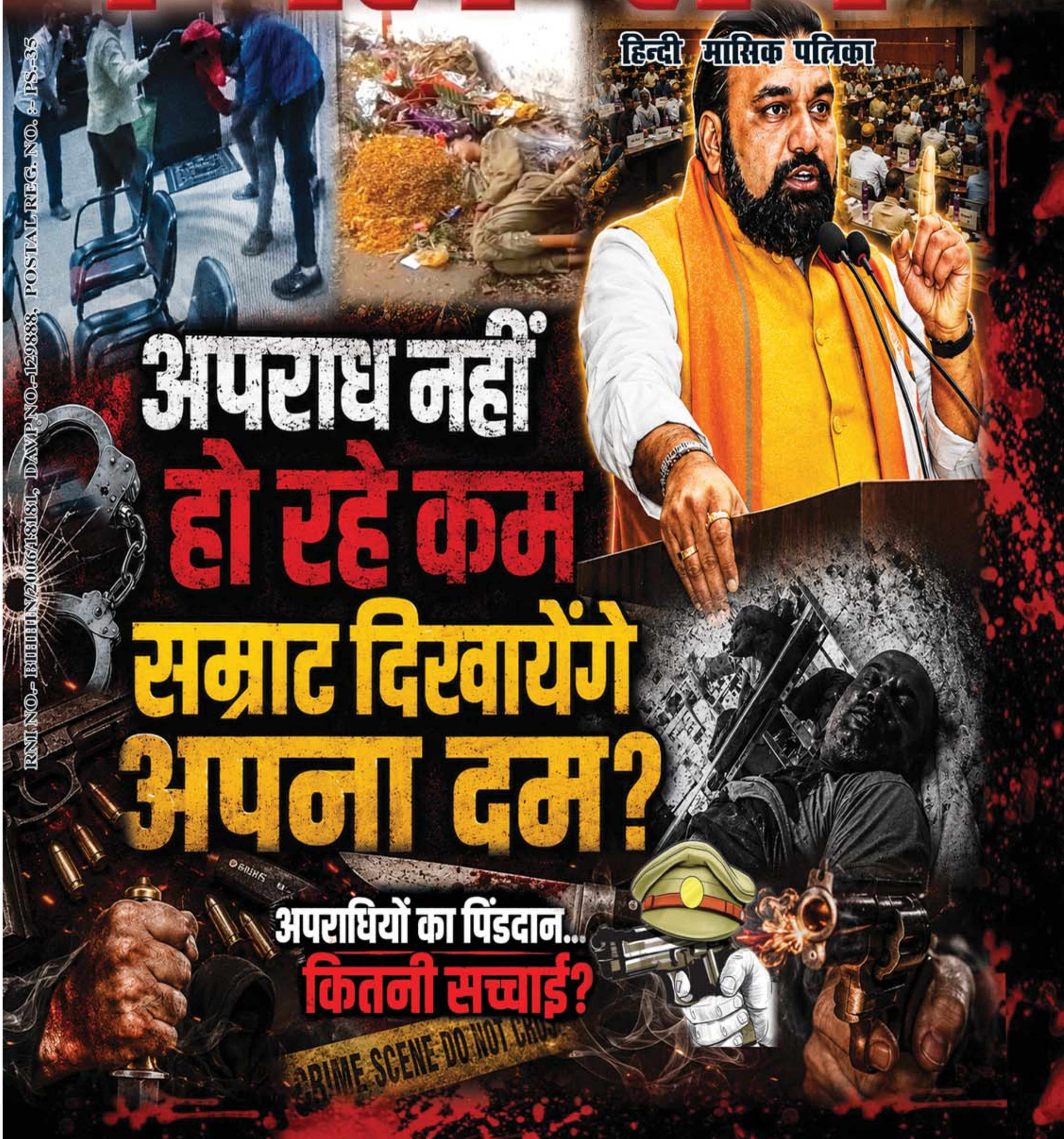


## अपराध नहीं हो रहे कम समृाट दिखायेंगे अपना दम?

### अपराधियों का पिंडदान... कितनी सच्चाई?

RNI NO.- BIHHIN/2006/18181, DAVP NO-129888, POSTAL REG. NO. :- PS.-35

# जन-जन की आवाज है केवल सच

निर्भीक हमारी पहचान
केवल सच
हिन्दी मासिक पत्रिका

Kewalsachlive.in
वेब पोर्टल न्यूज
24 घंटे आपके साथ

Kewalsach news
Kewalsach news
Mob.: 9431073769, 9308815605
खबर वहीं,
जो केवल सच हो

केवल सच TIMES

## आत्म-निर्भर बनने वाले युवाओं को सपोर्ट करें

### आपका छोटा सहयोग, हमें मजबूती प्रदान करेगा

BHIM UPI
G Pay paytm

www.kewalsach.com www.kewalsachlive.in

-: सम्पर्क करें :-

पूर्वी अशोक नगर, रोड नं.-14, मकान संख्या-28/14,
कंकड़बाग, पटना ( बिहार )-800020, मो०:-9431073769, 9308815605

# जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएँ

एस.एन. कृष्णन
01 मई 1932

अनुष्का शर्मा
01 मई 1988

अशोक गहलोत
03 मई 1951

उमा भारती
03 मई 1959

तृष्णा कृष्णन
04 मई 1983

सनी लियोनी
13 मई 1981

जरीन खान
14 मई 1980

माधुरी दिक्षित
15 मई 1967

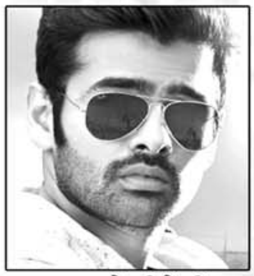
राम पेथीनेनी
15 मई 1988

सोनल चौहान
16 मई 1987

स्व.पंकज उदास
17 मई 1951

चार्मी कौर
17 मई 1987

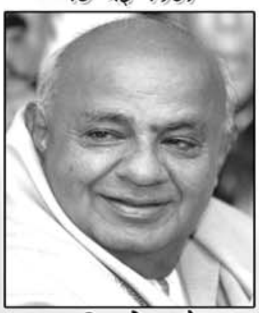
एच.डी. देवगौड़ा
18 मई 1933

एनटीआर जूनियर
20 मई 1983

महबूबा मुफ्ती
22 मई 1959

करण जोहर
25 मई 1972

नितिन गडकरी
27 मई 1957

रवि शास्त्री
27 मई 1962

पंकज कपूर
29 मई 1954

परेश रावल
30 मई 1950

निर्भीकता हमारी पहचान www.kewalsach.com

# केवल सच

हिन्दी मासिक पत्रिका

Regd. Office :-
East Ashok, Nagar, House
No.-28/14, Road No.-14,
kankarbagh, Patna- 8000 20
(Bihar) Mob.-09431073769
E-mail :- kewalsach@gmail.com

Corporate Office:-
Vaishnavi Enclave,
Second Floor, Flat No. 2B,
Near-firing range,
Bariatu Road, Ranchi- 834001
E-mail :- editor.kstimes@rediffmail.com

Delhi Office :-
Sanjay Kumar Sinha,
A-68, 1st Floor, Nageshwar Talla
Shastri Nagar, New Delhi - 110052
Mob.- 09868700991,
09955077308
E-mail:- kewalsach_times@rediffmail.com

Kolkata Office :-
Ajeet Kumar Dube,
131 Chitranjan Avenue,
Near- md. Ali Park,
Kolkata- 700073
(West Bengal)
Mob.- 09433567880
09339740757

## Advertisement Rates Per Issue

**COLOUR**

| AREA | FULL PAGE | HALF PAGE | Qr. PAGE |
|---|---|---|---|
| Cover Page | 5,00,000/- | N/A | N/A |
| Back Page | 1,60,000/- | N/A | N/A |
| Back Inside | 1, 00000/- | 60,000/- | 35000 |
| Back Inner | 90,000/- | 50,000/- | 30000 |
| Middle | 1,50,000/- | N/A | N/A |
| Front Inside | 1, 00000/- | 60,000/- | 40000 |
| Front Inner | 90,000/- | 50,000/- | 30000 |

**B & W**

| AREA | FULL PAGE | HALF PAGE |
|---|---|---|
| Inner Page | 60,000/- | 35,000/- |

1. एक साल के नियमित विज्ञापन पर पत्रिका के वेवसाइट **www.kewalsach.com** के फ्रंट पर भी विज्ञापन निःशुल्क तथा आपका वेवसाइट से सीधा लिंक हो सकता है।
2. एक साल के नियमित विज्ञापन पर 10 प्रतिशत की रियायत।
3. आपके प्रोडक्ट या संगठन के प्रचार-प्रसार हेतु आलेख को उचित स्थान।
4. पत्रिका द्वारा सामाजिक कार्य में आपके संगठन/प्रोडक्ट का बैनर/फ्लैक्स को उचित स्थान देकर आपके संगठन का व्यापक प्रचार-प्रसार।
5. विज्ञापन का भुगतान चेक या आर.टी.जी.एस. से ही मान्य होगा।

**महाप्रबंधक ( विज्ञापन )**

संविधान की शक्ति पर सभी को भरोसा है और इसके द्वारा प्रदत अधिकार ने राजनेताओं को सबसे अधिक पावरफुल बना दिया है जिसकी वजह से अनपढ़ नेता विद्वान पदाधिकारी पर हुकूमत चलाते हुए सायकिल से सीधे स्कॉर्पियो पर पहुंच जाता है। हद तो तब हो जाती है जब 05 साल बाद उनकी संपति 1000 गुणा की स्पीड से बढ़ जाती है। उधार मांग कर चुनाव का नामांकन कराने वाले नेता जी का राजनीति व्यवसाय इतना बढ़ जाता है कि उनको अपने और अपने परिवार के खाते के साथ-साथ नौकर-चाकर के खाते में भी रूपया को रखना पड़ता है, कुछेक लोगों का तो रूपया स्वीस बैंक में जमा है जिसको वापस भारत लाने के लिए मोदी की सरकार को तीन बार लगातार चुना गया लेकिन रूपये के पावर के सामने मोदी भी बौना दिख रहे हैं। केन्द्र हो या राज्य की सरकार उनकी जांच एजेंसी के तमाम प्रयास के बावजूद 0 से 1000 करोड़ + का राजनेता बन जाता है जबकि उनके नामांकन के घोषणा-पत्र में संपत्ति का ब्योरा भी खुद को 05 साल बाद शेयर बाजार को मुंह चिढ़ाने लगता है। आखिरकार सायकिल से स्कार्पियों पर कैसे पहुंचे? कौन सा व्यवसाय राजनीति में किया? कौन देता है इनको इतनी अकूट संपत्ति? कैसे खरीद लेते हैं करोड़ों की कोठिया? बच्चों की शिक्षा विदेश में कैसे संभव? सबकुछ जानते हुए क्यों चुप हो जाता है आयकर विभाग?

— — — — — —

ब्रजेश मिश्र, संपादक

8340360961, 9431073769

# राजनीति का व्यवसाय

# सुपरहिट

**को**रोना का मौत का तांडव आप सभी को अवश्य याद होगा क्योंकि उस समय कोरोना वायरस से बचने के लिए को वैक्सीन और कोविड सिल्ड का इंजेक्शन देश का 60 फिसदी लोगों ने लिया था। आम से लेकर खास, तक की मौत हुई थी लेकिन देश का राजनेता उस मौत के तांडव के वक्त भी खुशहाल जीवन जी रहा था। आम आदमी के आय से टैक्स एवं उसके प्रतिदिन की रोजमर्रा के खर्च पर जीएसटी राजनेताओं को गरीब-लाचार वेवसी से निकाल कर करोड़पति बना देता है। एक राजनेता समाजसेवा के नाम पर राजनीति करके कौन से व्यवसाय करते हैं जिसकी वजह से बैंक से भी अधिक रफ्तार से उसका पैसा 5 साल में 1000 गुणा बढ़ जाता है? केन्द्र हो राज्य की सरकारें और उसके मुखिया किस प्रकार चुनाव के वक्त चुनावी हलफनामें में विकास के कसीदे गढ़कर जनता के बीच रखकर उन्हें मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाने उनपर 05 साल तक शासन करते हैं। सायकिल से सवारी करने वाला मुखिया भी एक टर्म के भीतर लग्जरी गाड़ी का मालिक बन जाता है और झोपड़ी उसका महल में तब्दील हो जाता है। टेंडर, ट्रांस्फर-पोस्टिंग, सदन में सवाल उठाना आदि कई प्रकार के काम के करवाने के लिए स्वयं एवं लाइजनर भी रखते हैं। बिना वेतन (दक्षिणा) का किसी भी दल में बतौर कार्यकर्त्ता कैसे काम करता है कि वह परिवार और पार्टी दोनों को बिना पारिश्रमिक के महीनों का लाखों का खर्चा का वहन कर रहा है। किसी भी राजनीतिक दल के कार्यालय के बाहर लगी लग्जरी गाडियों का काफिला यह प्रमाणित करती है कि जुगाड़ के सहारे राजनीति का व्यवसाय धड़ल्ले से चलता है। आज राजनीति के सक्रिय योद्धा एवं प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अपनी बीबी, बेटी और बेटा के नाम से आउटसोर्सिंग का काम, टेंडर का काम अदला-बदली का काम से करोड़ों की संपत्ति अर्जित करने में सफल हो जाता है। बिना निवेश के लाभ हीं लाभ का खेल को कभी सीबीआई तो कभी आर्थिक अपराध इकाई पर्दाफास करती है पर कुछ दिनों के आई वॉश करके जनता, पत्रकार के आंख में धूल झोंककर फिर से पुराने कार्य में संलिप्त हो जाते हैं। मुखिया, विधायक, विधान पार्षद, लोकसभा एवं राज्यसभा सदस्यता ग्रहण के पहले वह गुदरी के लाल रहते हैं और पद ग्रहण के बाद उनका धन शेयर मॉर्केट की तरह 100 प्रतिशत सेंशस पर पहुंच जाता है। यह उनका रूपया बोलता है अन्यथा अपने ही कार्यकर्त्ता के मोटरसायकिल में 1 ली पेट्रोल भराने में उनकी पैंट गिली हो जाती है। 1947 के लेकर 2026 तक राजनीति का व्यवसाय करने वाले के उपर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती क्योंकि पक्ष एवं विपक्ष को इस मुद्दे पर मौन रहना मजबूरी रहता है। सीबीआई, ईडी, आयकर विभाग के तमाम प्रयास के बावजूद राजेनताओं पर नकेल कसना अंसभव होता जा रहा है, बल्कि राजनीति के सूरमा इन विभागों को भी अपने व्यवसाय का हिस्सेदार या कुछ प्रसेंटेज का साईलेंट पार्टनर बना देता है। राजनीति के व्यसाय में लोकतंत्र के चारो स्तंभ एकतरफा खड़ा होकर अपने मंसूबे को कामयाब कर देते हैं। दीगर बात है कि पिछले 40 साल में राजनेता कभी भूख से नहीं मरा है और भ्रष्टाचार से अपनी 07 पीढ़ी का कमाई का मार्ग को प्रशस्त कर लेते हैं। राजनीति व्यवसाय का ऐसा क्षेत्र है की व्यवसायी एवं उद्योगपति रूपये (गांधी छाप नोट) के दम पर विधान पाषर्द एवं राज्यसभा सदस्य बनने के लिए करोड़ों रूपये खर्च करके वह पद हासिल करते हैं ताकि धंधा भी चलता रहे और सामाजिक एवं प्रशासनिक प्रतिष्ठा भी बढ़ जाये। कई उद्योगपति चंदा से बचने के लिए अपनी पार्टी बनाकर दूसरे से चंदा मांगने का काम भी शुरू कर चुके हैं। पटेल, गांधी एवं लोहिया का दौर समाप्त हो चुका है और समाजसेवा सिर्फ राजनीति के मंच एवं कार्यकत्ताओं के बीच सामाजिक न्याय के लिए महापुरूषों का नाम लिया जाता है। राजनीति व्यवसाय का हनन इस प्रकार हुआ है कि कार्यकर्त्ता बुके और शॉल अपने नेता पर खर्च करते हैं उसका भी मॉर्केटिंग करने से नहीं थकते और एक बुके एवं शॉल से एक दो तबादला करवा लेते हैं का भी दौर चल रहा है। मीडिया भी राजनीति का व्यवसाय को समझकर चाटुकारिता में मशगूल हो चुका है जिसकी वजह से अंदर की महत्वपूर्ण खबरें तब तक बाहर नहीं जब तक हिस्सेदारी में बेइमानी न हो। वोटर (ग्राहक) भी अपने नेता (होलसेलर) को चुनने के लिए रकम वसूलने (अन्य सामग्री) में कोई चूक नहीं करती और यही महत्वपूर्ण कारण है की सेवा भाव से राजनीति करने वाले लोगों को महत्व विहीन बना दिया जाता है। राजनीति में व्यवसाय का जन्म प्रशांत किशोर ने दिया जिसको नेता एवं वोटर दोनों ने स्वीकार किया। इस व्यवसाय में किसी वस्तु को नहीं बेचा जाता बल्कि शब्दों का बाजार होता है। चुनाव में घोषणा पत्र ही प्रोडक्ट बन जाता है और विपक्षी को चारो खाने चित वोटर (ग्राहक) कर देती है। यह अलग बात है कि अपने प्रोडक्ट के जाल में फंसाकर सरकार बनाने वाले अपने प्रोड्क्ट खराब है कहकर एक बार फिर पांच साल के लिए प्रलोभन देती है की इसबार प्रोड्क्ट (घोषणा पत्र) के साथ किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं किया जायेगा। बढ़ती बेरोजगारी को कंट्रोल राजनीति व्यवासाय केन्द्र (राजनीतिक दल) ही करके सबको लाभ पहुंचा रही है अन्यथा राजनीति में इतनी भीड़ नहीं होती। यहां पूंजी निवेश नहीं होता बल्कि परिश्रम और जुगाड़ जगह पर पहुंचाती है।

अप्रैल 2026

आपको केवल सच पत्रिका कैसी लगी तथा इसमें कौन-कौन सी खामियाँ हैं, अपने सुझाव के साथ हमारा मार्गदर्शन करें। आपका पत्र ही हमारा बल है। हम आपके सलाह को संजीवनी बूटी समझेंगे।

केवल सच

राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका

हमारा पता है :-

द्वारा:- ब्रजेश मिश्र

पूर्वी अशोक नगर, रोड़ नं.- 14, मकान संख्या- 14/28

कंकड़बाग, पटना-800020 (बिहार)

फोन:- 9431073769/ 8340360961/ 9955077308

हमारा ई-मेल

kewalsach@gmail.com, editor.kstimes@rediffmail.com

kewalsach_times@rediffmail.com

## खजाना

**ब्रजेश जी,**

''योजना खा गई खजाना'' अप्रैल 2026 अंक का संपादकीय सच में बिहार और झारखंड के चुनाव के अंकगणित पर सवाल खड़ा करता यक्ष प्रश्न है। आपका संपादकीय न सिर्फ सरल है बल्कि जनहित में घट रही समस्याओं पर सरकार से सीधा सवाल है। सत्ता पर काबिज होने के लिए 2024 में झारखंड एवं 2025 में बिहार में रेबड़ी की तरह वोट के लिए पैसे बांटे गये और सरकार बनने के बाद विकास के लिए खजाने में पैसे नहीं है। उपयोगी एवं जनहित में आपका संपादकीय समर्पित रहता है।

**✦नंदन वर्णवाल, लक्ष्मी नगर मेट्रो, नई दिल्ली**

## सम्राट उदय

**ब्रजेश जी,**

मैं केवल सच पत्रिका का नियमित पाठक हूं। बिहार प्रदेश से 20 वर्षों से इसका प्रकाशन हो रहा है, गर्व का विषय है। बिहार में पहली बार भाजपा का मुख्यमंत्री बना है इसपर सटीक आलेख अमित कुमार ने अप्रैल 2026 अंक में ''**बिहार भाजपा में सम्राट उदय**'' आलेख में लिखा है और पूरे विस्तार से पूरे मामले को पाठकों के बीच रखा है। खबर पढ़कर संतुष्ट हूं और ऐसी खबरें पत्रकारिता को मजबूत बनाती है। राजनीति की दमदार खबरें लगातार पढ़ने को मिल रहे हैं, जिससे अच्छी जानकारी प्राप्त होती है।

**✦ मनोरंजन दत्ता, बाबू बाजार, कोलकात्ता**

## भ्रष्टाचार का सम्राट

**मिश्रा जी,**

जीवन के लिए दवा का समुचित व्यवस्था का होना आवश्यक है और **केवल सच**, पत्रिका लगातार भ्रष्टाचार पर खबरों को पाठकों के बीच ला रहा है। अप्रैल 2026 अंक में शशि रंजन सिंह एवं राजीव शुक्ला की संयुक्त खबर ''**DCGI डॉ० राजीव सिंह रघुवंशी दवाओं का नियामक या भ्रष्टाचार का सम्राट?**'' में दवाओं के कारोबार का काला चिट्ठा को खोलकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं और सरकार को भी ऐसे भ्रष्ट लोगों की सूचना पूरे प्रमाण के साथ दे रहे हैं। ऐसे पत्रकार जान जोखिम में डालकर खबर को सार्वजनिक करता है, वह सम्मान का हकदार है। सटीक व प्रमाणित खबर।

**✦ लालबाबू सिन्हा, सेक्टर-04, गुड़गांव, हरियाणा**

## एक से बढ़कर एक

**मिश्रा जी,**

केवल सच, पत्रिका का अप्रैल 2026 अंक वास्तव में संग्रहणीय है। उत्तर प्रदेश की एक पर एक खबरें हैं, जिसमें संजय सक्सेना की खबर ''**योगी का पैदल मार्च**'' महिला आरक्षण का मजबूत करता है तो अजय कुमार की खबर ''**आधी आबादी की योगी कैबिनेट में बढ़ती हिस्सेदारी**'' 2027 के विधान सभा चुनाव की लकीर लिखती दिख रही है तो दूसरी खबर ''**योगी से काफी पीछे खड़ें हैं अखिलेश**'' की सोच पर सटीक प्रहार है। उत्तर प्रदेश की खबरों को काफी प्रमुखता से केवल सच प्रकाशित कर रहा है। केवल सच धीरे-धीरे देश के विभिन्न राज्यों के राजनीति एवं भ्रष्टाचार की खबरों को प्रमुखता से छाप रहा है।

**✦ संजय सिन्हा, अस्सी घाट, बनारस, यूपी**

## वीरांगना

**संपादक जी,**

आपकी पत्रिका केवल सच, ने अप्रैल 2026 अंक में 1857 की क्रांति की अनसुनी आवाज ''**वीरांगना अवंतीबाई लोधी**'' पर डॉ० ब्रम्हानंद राजपूत ने जानकारीप्रद खबर को पाठकों के समक्ष रखा है जो संग्रहणीय है। केवल सच पत्रिका अगर रंगीन पृष्ठों में प्रकाशित होने लगे तो इसकी साख और भी दमदार होगी। आजादी के इस नायिका को आमजनता के बीच लाना सकारात्मक पत्रकारिता का परिचय है। इस अंक की सभी खबरों के साथ-साथ मिथिलेश कुमार, धर्मेद्र सिंह की खबरें भी पठनीय है। कानूनी सलाह और संपादकीय मुझे बहुत अच्छा लगा।

**✦ कैलाश सिंह, शीतलपुर, सारण, बिहार**

## झारखंड

**संपादक जी,**

अप्रैल 2026 अंक में भारती मिश्र की खबर ''**झारखंड सियासत में घमासान, क्या बिखर रहा है गठबंधन**'' में वर्तमान समय में चल रहे राजनीतिक उठापटक के बीच आपसी मनमुटाव बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त से ही गहराता जा रहा है। राजनीति की ऐसी खबरों को और स्थान मिलना चाहिए। गुड्डी साव एवं ओम प्रकाश की खबरें भी पाठकों को सटीक जानकारी देती हैं। अप्रैल अंक में भी **केवल सच** पत्रिका के तीनों पत्रकारों ने एक से बढ़कर एक खबर को लिखकर पाठकों के बीच पहुंचाया है। भ्रष्टाचार की खबर को उजागर करें।

**✦ गौरी शंकर प्रसाद, कटहल मोड़, राँची**

## अन्दर के पन्नों में

**RNI No.- BIHHIN/2006/18181,** **DAVP No.- 129888**

समृद्ध भारत खुशहाल भारत

निर्भीकता हमारी पहचान

# केवल सच

राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका

| वर्षः- 20 | अंकः- 240 | माहः- मई 2026 | मूल्यः- 20/- रू |
|---|---|---|---|

**फाउंडर**

## श्रद्धेय गोपाल मिश्र
## श्रद्धेय सुषमा मिश्र

संपादक

## ब्रजेश मिश्र

9431073769 8340360961

**editor.kstimes@rediffmail.com**

kewalsach@gmail.com

**प्रधान संपादक**

| | |
|---|---|
| अरूण कुमार बंका (एडमिन) | 7782053204 |
| सुरजीत तिवारी | 9431222619 |
| निलेन्दु कुमार झा | 9431810505, 8210878854 |
| सच्चिदानन्द मिश्र | 9934899917 |
| डॉ० शशि कुमार | 9507773579 |

**संपादकीय सलाहकार**

| | |
|---|---|
| अमिताभ रंजन मिश्र | 9430888060, 8873004350 |
| अमोद कुमार | 9431075402 |

**महाप्रबंधक**

| | |
|---|---|
| त्रिलोकी नाथ प्रसाद | 9308815605, 9122003000 |

triloki.kewalsach@gmail.com

**महाप्रबंधक (विज्ञापन)**

| | |
|---|---|
| पूनम जयसवाल | 9430000482, 9798874154 |
| मनीष कुमार कमलिया | 9934964551, 8809888819 |
| गीतांजलि | 9279599313, 8294636307 |

**उप-संपादक**

| | |
|---|---|
| प्रसुन्न पुष्कर | 9430826922, 7004808186 |
| ब्रजेश सहाय | 7488696914 |
| ललन कुमार | 7979909054, 9334813587 |

**राजनीतिक संपादक**

| | |
|---|---|
| सुमित रंजन पाण्डेय | 7992210078 |
| संतोष कुमार यादव | 8210487516 |

**संयुक्त संपादक**

| | |
|---|---|
| अमित कुमार 'गुड्डू' | 9905244479, 7979075212 |
| राजीव कुमार शुक्ला | 9430049782, 7488290565 |
| काशीनाथ गिरी | 9905048751, 9431644829 |
| कुमार अनिकेत | 9431914317 |

**सहायक संपादक**

| | |
|---|---|
| शशि रंजन सिंह | 8210772610, 9431253179 |
| मिथिलेश कुमार | 9934021022, 9431410833 |
| नवेन्दु कुमार मिश्र | 9570029800, 9199732994 |

**समाचार प्रबंधक**

| | |
|---|---|
| सुधीर कुमार मिश्र | 9608010907 |

**ब्यूरो-इन-चीफ**

| | |
|---|---|
| संकेत कुमार झा | 9386901616, 7762089203 |

**विधि सलाहकार**

| | |
|---|---|
| शिवानन्द गिरि | 9308454485 |

**चीफ क्राइम ब्यूरो**

| | |
|---|---|
| सैयद मो० अकील | 9905101976, 8521711976 |

**साज-सज्जा प्रबंधक**

| | |
|---|---|
| अमित कुमार | 9905244479 |

amit.kewalsach@gmail.com

**कार्यालय संवाददाता**

| | |
|---|---|
| सोनू यादव | 8002647553, 9060359115 |

**प्रसार प्रतिनिधि**

| | |
|---|---|
| कुणाल कुमार | 9905203164 |

**बिहार प्रदेश जिला ब्यूरो**

| | | |
|---|---|---|
| पटना (श०) :- | श्रीधर पाण्डेय | 9470709185 |
| (म०) :- | | |
| (ग्रा०) :- | मुकेश कुमार | 9473038020 |
| बाढ़ :- | | |
| भोजपुर :- | गुड्डू कुमार सिंह | 8789291547 |
| बक्सर :- | बिन्ध्याचल सिंह | 8935909034 |
| कैमूर :- | | |
| रोहतास :- | | |
| :- | | |
| गया (श०) :- | | |
| (ग्रा०) :- | | |
| औरंगाबाद :- | | |
| जहानाबाद :- | नवीन कुमार रौशन | 9934039939 |
| अरवल :- | संतोष कुमार मिश्रा | 9934248543 |
| नालन्दा :- | | |
| :- | | |
| नवादा :- | अमित कुमार | 9162664468 |
| :- | | |
| मुंगेर :- | | |
| लखीसराय :- | | |
| शेखपुरा :- | | |
| बेगूसराय :- | | |
| :- | | |
| खगड़िया :- | | |
| समस्तीपुर :- | | |
| जमुई :- | अजय कुमार | 09430030594 |
| वैशाली :- | | |
| :- | | |
| छपरा :- | | |
| सिवान :- | | |
| :- | | |
| गोपालगंज :- | | |
| :- | | |
| मुजफ्फरपुर :- . | | |
| :- | | |
| सीतामढ़ी :- | | |
| शिवहर :- | | |
| बेतिया :- | रवि रंजन मिश्रा | 9801447649 |
| बगहा :- | | |
| मोतिहारी :- | संजीव रंजन तिवारी | 9430915909 |
| दरभंगा :- | | |
| :- | | |
| मधुबनी :- | | |
| :- | प्रशांत कुमार गुप्ता | 6299028442 |
| सहरसा :- | | |
| मधेपुरा :- | | |
| सुपौल :- | | |
| किशनगंज :- | | |
| :- | | |
| अररिया :- | अब्दुल कय्यूम | 9934276870 |
| पूर्णिया :- | | |
| कटिहार :- | | |
| भागलपुर, :- | | |
| (ग्रा०) :- | रवि पाण्डेय | 7033040570 |
| नवगछिया :- | | |

## दिल्ली कार्यालय

**केवल सच**, हिन्दी मासिक पत्रिका,
द्वारा- संजय कुमार सिन्हा
A-68, 1st Floor,
नागेश्वर तल्ला, शास्त्रीनगर,
नई दिल्ली-110052
**संजय कुमार सिन्हा, स्टेट हेड**
मो०- 9868700991, 9431073769

## उत्तरप्रदेश कार्यालय

**केवल सच**, हिन्दी मासिक पत्रिका,
................................., **स्टेट हेड**

सम्पर्क करें
9308815605

## पश्चिम बंगाल कार्यालय

**केवल सच**, हिन्दी मासिक पत्रिका,
द्वारा- अजीत कुमार दुबे
131 चितरंजन एवेन्यू,
कोलकात्ता, पश्चिम बंगाल- 700073
**अजीत कुमार दुबे, स्टेट हेड**
मो०- 9433567880, 9308815605

## मध्य प्रदेश कार्यालय

**केवल सच**, हिन्दी मासिक पत्रिका,
हाउस नं.-28, हरसिद्धि कैम्पस
खुशीपुर, चांबड़
भोपाल, मध्य प्रदेश- 462010
**अभिषेक कुमार पाठक, स्टेट हेड**
मो०- 8109932505,

## झारखंड कार्यालय

**केवल सच**, हिन्दी मासिक पत्रिका,
वैष्णवी इंक्लेव,
द्वितीय त्तल, फ्लैट नं- 2बी
नियर- फायरिंग रेंज
बरियातु रोड, राँची- 834001
मो०- 7903856569, 6203723995

## छत्तीसगढ़ कार्यालय

**केवल सच**, हिन्दी मासिक पत्रिका,

................................., **स्टेट हेड**
सम्पर्क करें
8340360961

**संपादकीय व प्रधान कार्यालय:-**

☞ पूर्वी अशोक नगर, रोड नं.-14, मकान संख्या.- 14/28, कंकड़बाग, पटना-800020 (बिहार) मो०- 9431073769, 9955077308

☞ e-mail:- kewalsach@gmail.com, editor.kstimes@rediffmail.com
kewalsach_times@rediffmail.com

☞ स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक ब्रजेश मिश्र द्वारा सांध्य प्रवक्ता खबर वर्क्स, ए- 17, वाटिका विहार (आनन्द विहार), अम्बेडकर पथ, पटना 8000 14(बिहार) एवं पूर्वी अशोक नगर, रोड नं. 14, कंकड़बाग पटना-800020 से प्रकाशित, संपादक- ब्रजेश मिश्र। RNI NO.-BIHHIN/2006/18181

☛ पत्रिका में प्रकाशित समाचारों से संपादक की सहमति आवश्यक नहीं है।

☛ सभी प्रकार के वाद-विवादों का निपटारा पटना न्यायालय के अधीन होगा।

☛ आलेख पर कोई आपत्ति हो तो एक महीने के भीतर खंडन करें।

☛ किसी भी लेख के लिए रचनाकार/लेखक स्वयं जिम्मेवार होंगे।

☞ **सभी पद अवैतनिक हैं।**

☞ फोटो-समाचार साभार भी (माध्यम- इंटरनेट एवं अन्य स्त्रोत)

☞ कोई भी शिकायत हमारे पते पर लिखकर भेजें।

☞ **विज्ञापन का भुगतान चेक या ड्राफ्ट एवं RTGS से ही मान्य होगा।**

☞ भुगतान Kewal Sach को ही करें। प्रतिनिधियों को नगद न दें।

☞ A/C No. :- 0600050004768
BANK :- Punjab National Bank
IFSC Code :- PUNB0060020
PAN No. :- AAJFK0065A

☞ A/C No. :- 0600050004768
BANK :- State Bank of India
IFSC Code :- SBIN0003564
PAN No. :- AAJFK0065A

**प्रधान संपादक**

..........................................................

..........................................................

**झारखण्ड स्टेट ब्यूरो**

..........................................................

**झारखण्ड सहायक संपादक**

| | |
|---|---|
| अभिजीत दीप | 7004274675, 9430192929 |
| ब्रजेश मिश्र | 7654122344, 7979769647 |
| अनंत मोहन यादव | 9546624444, 7909076894 |

**उप संपादक**

| | |
|---|---|
| अजय कुमार | 6203723995, 8409103023 |

..........................................................

**संयुक्त संपादक**

..........................................................

**विशेष प्रतिनिधि**

| | |
|---|---|
| भारती मिश्रा | 8210023343, 8863893672 |

..........................................................

..........................................................

**झारखण्ड प्रदेश जिला ब्यूरो**

| | | |
|---|---|---|
| राँची | :- अभिषेक मिश्र | 7903856569 |
| | :- ओम प्रकाश | 9708005900 |
| साहेबगंज | :- | |
| खूँटी | :- | |
| जमशेदपुर | :- तारकेश्वर प्रसाद गुप्ता | 9304824724 |
| हजारीबाग | :- | |
| जामताड़ा | :- | |
| दुमका | :- | |
| देवघर | :- | |
| धनबाद | :- | |
| बोकारो | :- | |
| रामगढ़ | :- | |
| चाईबासा | :- | |
| कोडरमा | :- | |
| गिरीडीह | :- | |
| चतरा | :- धीरज कुमार | 9939149331 |
| लातेहार | :- | |
| गोड्डा | :- | |
| गुमला | :- | |
| पलामू | :- | |
| गढ़वा | :- | |
| पाकुड़ | :- | |
| सरायकेला | :- | |
| सिमडेगा | :- | |
| लोहरदगा | :- | |

## श्री चन्द्र प्रकाश सिंह

प्रधान संरक्षक सह प्रबंध संपादक

**'केवल सच'** पत्रिका **एवं 'केवल सच टाइम्स'**

राष्ट्रीय संगठन मंत्री, राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस (इंटक)

**पूर्व निदेशक सदस्य, ओरियेंटल बैंक ऑफ कॉमर्स**

09431016951, 09334110654

## डॉ. सुनील कुमार

शिशु रोग विशेषज्ञ सह मुख्य संरक्षक

**'केवल सच'** पत्रिका

**एवं 'केवल सच टाइम्स'**

एन.सी.- 115, एसबीआई ऑफिसर्स कॉलोनी,

लोहिया नगर, कंकड़बाग, पटना- 800020

फोन- 0612/3504251

## सुधीर कुमार

मुख्य संरक्षक सह निदेशक **''मगध इंटरनेशनल स्कूल''** टेकारी

**'' केवल सच ''** पत्रिका **एवं '' केवल सच टाइम्स ''**

9060148110

sudhir4s14@gmail.com

## कैलाश कुमार मौर्य

मुख्य संरक्षक

**'केवल सच'** पत्रिका **एवं 'केवल सच टाइम्स'**

**व्यवसायी**

**पटना, बिहार**

**7360955555**

| **बिहार राज्य प्रमंडल ब्यूरो** | | |
|---|---|---|
| पटना | | |
| मगध | | |
| सारण | | |
| तिरहुत | | |
| **पूर्णिया** | **धर्मेन्द्र सिंह** | 9430230000 7004119966 |
| भागलपुर | | |
| मुंगेर | | |
| दरभंगा | | |
| कोशी | | |

| विशेष प्रतिनिधि | |
|---|---|
| आशुतोष कुमार | 9430202335, 9304441800 |
| सूमन सौरभ | 9471492480, 7004952447 |
| बेंकटेश कुमार | 8521308428, 9572796847 |
| दीपनारायण सिंह | 9934292882 |
| आनन्द प्रकाश पाण्डेय | 9931202352, 7808496247 |
| रामजीवन साहू | 9430279411, 7250065417 |
| रजनीश कांत झा | 9430962922, 7488204140 |

| **छायाकार** | |
|---|---|
| त्रिलोकी नाथ प्रसाद | 9122003000, 9431096964 |
| मुकेश कुमार | 9835054762, 9304377779 |
| जय प्रसाद | 9386899670 |

| **झारखंड राज्य प्रमंडल ब्यूरो** | | |
|---|---|---|
| राँची | गुड्डी साव | 6299470142 |
| हजारीबाग | | |
| पलामू | | |
| दुमका | | |
| चाईबासा | | |

**कितना इक्तिफाक है कि महज छः महीने बाद सत्ता, शासन बदलते ही विभागीय मंत्रालय भी बदल गये। दिल मन की भावुकता देखने बनता है, जब छः महीने पहले स्वयं मंत्रियों को शपथ के लिए आगे करते रहे और मंच पर लगी बड़ी बैनरों पर बड़े फोटो देख मन ही मद गदगद होते रहें। किन्तु आज सबकुछ बदला-बदला सा है। मंच किसी और का, मंच पर तस्वीरे भी किसी और की। मंच पर चेहरे जाने-पहचाने किंतु अनजाने से लग रहे थे। जी हां, हम बात कर रहे हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का। राजधानी पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान एक बार फिर से नये मंत्रियों के शपथ ग्रहण का साक्षी बना, जहां स्वयं देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षामंत्री, मुख्यमंत्री सहित वरिष्ठ नेता मौजूद थे। नीतीश कुमार मंच पर आते ही मुख्यमंत्री की कुर्सी की ओर बढ़ना चाहा किन्तु उन्हें रोक लिया गया, याद दिलाया गया कि अब आप 'पूर्व' मुख्यमंत्री हैं। इसके बाद भी मंच पर नीतीश का जलवा देखते बना। सभी जदयू और भाजपा के नेताओं का गर्मजोशी से उन्होंने स्वागत किया, हांथ मिलाये और तो और एक क्षण ऐसा भी आया जब नीतीश कुमार ने पीएम मोदी के कंधों पर ही हांथ रख दिया। बहरहाल, सम्राट कैबिनेट के विस्तार की चर्चा कई दिनों से चल रही थी और फिर लिस्ट जारी हो गई। चयनित सदस्यों ने मंत्री पद की शपथ राज्यपाल बिहार के सामने ली। बता दें कि शपथ लेने वाले मंत्रियों में कई चेहरे नये हैं तो कई पुराने हैं जिन्हें फिर से पदभार मिला है। हालांकि मंत्रियों के इस कतार में कुछ नये चेहरे सुर्खिया बटोर रहे हैं जिनमें पहला नाम पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत हैं। वही शिवहर से डॉ० श्वेता गुप्ता को मंत्री बनाया गया है, वह भी चर्चा में हैं। साथ ही मिथिलेश तिवारी, नंदकिशोर राम सहित कई नाम हैं। जो सम्राट के इस मंत्रीमंडल में जगह पाये हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और दोनो डिप्टी सीएम विजय चौधरी एवं बिजेंद्र यादव को मिलाकर कुल 35 मंत्रियों को बिहार की राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सनद् रहे कि इन तमाम मंत्रियों को उनके जाति के हिसाब से हिस्सेदारी दी गई है। साथ ही सम्राट मंत्रीमंडल के मंत्री अनुभवी और ख्याति प्राप्त हैं। इनमें से कइयों को विरासत का लाभ भी मिला है तो कई काबिलियत के बल पर भी मंत्री बने हैं। मंत्रियों की इतनी बड़ी कतार अब बिहार में क्या कुछ कमाल दिखाती है ये देखने के लिए तैयार रहिए। सम्राट सेना के शपथ ग्रहण से उनके विभागों के बंटवारे तक की खबर पर प्रस्तुत है संयुक्त संपादक अमित कुमार की समीक्षात्मक रिपोर्ट :-**

बिहार की राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 7 मई को आयोजित सम्राट सरकार का शपथ ग्रहण समारोह कई मायनों में खास रहा। सम्राट सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार शपथ ग्रहण समारोह के मंच पर कई अलग-अलग तस्वीरें देखने को मिली, लेकिन इन सबके बीच नीतीश कुमार का वहीं पुराना अंदाज देखने को मिला। दरअसल शपथ ग्रहण समारोह के मंच पर जैसे ही नीतीश कुमार पहुंचे, उन्होंने अपने पुराने अंदाज से सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। कार्यकम में कई चीजें बदली हुई थीं। इससे पहले नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होते थे और सम्राट  चौधरी उनके साथ उनके मंच पर मौजूद रहते थे, लेकिन उस दिन की तस्वीर अलग थी। अब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं और नीतीश कुमार पहली बार उनके भव्य मंच पर पहुंचे थे। हालांकि इस दौरान खास बात यह रही कि नीतीश कुमार अपने ही पुराने अंदाज में दिखे। भले ही नीतीश कुमार बिहार के पूर्व सीएम के रूप में मंच पर पहुंचे थे, लेकिन मंच पर पहुंचते उन्होंने उसी जोश के साथ मंच पर मौजूद लोगों के साथ मुलाकात कर उनका अभिवादन किया। नीतीश कुमार बारी-बारी से मंच पर मौजूद नेताओं के पास पहुंचे और बड़े ही गर्मजोशी के साथ उनके साथ हाथ मिलाया। वही पटना के गांधी मैदान में पीएम नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, पूर्व सीएम नीतीश कुमार, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की मौजूदगी में भाजपा, जदयू, लोजपा-आर, हम और रालोमो के कुल 32 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बेहद आत्मीय अंदाज में एक-दूसरे से मिले। दोनों नेताओं ने मुस्कुराते हुए अभिवादन किया और कुछ देर बातचीत की। शपथ ग्रहण संपन्न होने के बाद नीतीश कुमार ने पीएम नरेंद्र मोदी से खास अंदाज में मुलाकात की। जब पीएम मोदी, सीएम सम्राट चौधरी मंच पर थे उस दौरान राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार भी वहीं थे। पीएम से मिलते ही उन्होंने उनके कंधे पर हाथ रखा। इसके बाद हाथ मिलाया। पीएम मोदी ने भी नीतीश कुमार का अभिवादन किया। इसके बाद नीतीश कुमार ने बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्रियों की मुलाकात पीएम से कराई। नीतीश ने विजेंद्र यादव और विजय कुमार से पीएम की मुलाकात कराई। पीएम और नीतीश कुमार की मुलाकात के दौरान दोनों के बीच खास केमेस्ट्री नजर आई। ज्ञात हो कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और कई अन्य नेताओं ने पटना के गांधी मैदान में बिहार सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार समारोह में पहुंचे थे।

गौरतलब है कि सभी वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में भाजपा, जदयू, लोजपा-आर, हम और रालोमो के कुल 32 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। इसके साथ ही सम्राट चौधरी की सरकार में दोनों डिप्टी सीएम विजय कुमार  चौधरी, बिजेंद्र प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर मंत्रियों की कुल संख्या 35 हो गई है। बिहार में सीएम समेत 36 मंत्री बन सकते हैं। भाजपा ने अपने कोटे के सभी 16

मंत्रियों के पद भर लिए हैं। जदयू ने 15 मंत्री बनाकर 1 पद आगे के लिए खाली रखा है। 32 नए मंत्रियों में 19 नीतीश की पिछली सरकार में भी मिनिस्टर बने थे। बचे 13 में ज्यादातर पहली बार मंत्री बने हैं, जबकि कुछ नेता एक अंतराल के बाद सरकार में लौटे हैं। सम्राट चौधरी की कैबिनेट में नीतीश कुमार की पिछली सरकार से ज्यादातर मंत्री फिर से जगह पा गए हैं, लेकिन भाजपा ने कई नए चेहरों को जगह दी है। भाजपा ने पार्टी के बड़े नेता मंगल पांडेय, सुरेंद्र मेहता और नारायण प्रसाद को फिर से मंत्री नहीं बनाया है। भाजपा कोटे से नीतीश मिश्रा और केदार गुप्ता ने एक पारी ब्रेक के बाद कैबिनेट में वापसी की है। बीजेपी ने मिथिलेश तिवारी, रामचंद्र प्रसाद, नंदकिशोर राम और इंजीनियर शैलेंद्र को पहली बार मंत्री बनाया है। जदयू कोटे से नीतीश के बेटे निशांत कुमार के अलावा बुलो मंडल और श्वेता गुप्ता पहली बार मंत्री बने हैं। जदयू ने पहले कभी मंत्री रहे भगवान सिंह कुशवाहा और दामोदर रावत को एक बार फिर मौका दिया है। लोजपा-आर, हम और रालोमो ने अपने पुराने मंत्रियों संजय पासवान, संजय सिंह, संतोष कुमार सुमन और दीपक प्रकाश कुशवाहा को दोबारा सरकार में भेजा है। बता दें कि सम्राट कैबिनेट में ओबीसी, ईबीसी, सवर्ण, दलित और महादलित का संतुलन बिठाने की कोशिश की गई है। राजपूत जाति के सबसे ज्यादा 4 नेता मंत्री बने हैं। नीतीश की पिछली सरकार में भी 4 ठाकुर मंत्री बनाए गए थे। राजपूतों के बाद कोइरी और भूमिहार के 3-3 मंत्री बने हैं। सम्राट चौधरी समेत कोइरी जाति से 3 कुशवाहा नेता मंत्री बने हैं। विजय चौधरी समेत 3 भूमिहार मंत्री बने हैं। 2-2 मंत्रियों वाली जातियों में यादव, ब्राह्मण, सूड़ी, कुर्मी, धानुक, निषाद, दुसाध, मुसहर और रविदास हैं। 1-1 मंत्री वाली जातियों में कानू, कलवार, कहार, पासी, तेली और गंगोता बिरादरी है, साथ ही 1 मुसलमान मंत्री भी बनाए गए हैं। वही सम्राट कैबिनेट में बिहार के 38 जिलों में 14 जिलों से कोई मंत्री नहीं बन सका। सीएम सम्राट समेत 35 मंत्रियों में 3-3 मिनिस्टर के साथ मधुबनी और वैशाली का दबदबा है। मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा, नालंदा, भोजपुर, गोपालगंज और जमुई जिले से 2-2 नेता मंत्री बनाए गए हैं। जमुई से एक ही गांव के पड़ोसी दामोदर रावत और श्रेयसी सिंह मंत्री बने हैं। 1 मंत्री पाने वाले 15 जिलों में सम्राट के गृह जिला मुंगेर के अलावा पटना, समस्तीपुर, सुपौल, लखीसराय, किशनगंज, जहानाबाद, पश्चिम चंपारण, शेखपुरा, पूर्णिया, कैमूर, सहरसा, शिवहर, बेगूसराय और गया शामिल हैं। नीतीश सरकार में 15 जिलों को मंत्री नहीं मिल पाया था। साथ ही नीतीश कुमार की पिछली सरकार के मुकाबले सम्राट चौधरी कैबिनेट में जहां मगध इलाके के मंत्री कम हुए हैं, वहीं मिथिला, तिरहुत, अंग, शाहाबाद और कोसी की हिस्सेदारी बढ़ी है। सम्राट चौधरी अंग इलाके के मुंगेर जिले की तारापुर सीट से विधायक हैं। नीतीश सरकार में अगर सबसे अधिक चर्चा किसी की हो रही है तो वह है पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की। ज्ञात हो कि शपथ समारोह के दौरान नीतीश कुमार मंच पर मौजूद गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, विजय सिन्हा, रामकृपाल यादव, संजय जायसवाल, रविशंकर प्रसाद, विजेंद्र प्रसाद यादव समेत अन्य नेताओं से मिले। इस दौरान निशांत कुमार ने अपने पिता का पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया और नीतीश कुमार ने निशांत को पीठ थपथपाकर बधाई दी। बिहार की राजनीति के लिए यह दिन बेहद अहम माना जा रहा है। दिगर बात है कि मंत्रिमंडल विस्तार से पहले चला सस्पेंस खत्म हो गया। निशांत कुमार को लेकर सस्पेंस था कि कि वह मंत्रिपरिषद में शामिल होंगे या नहीं, लेकिन वह मान गए। सूत्रों के मुताबिक, जेडीयू नेतृत्व के भीतर कई दौर की चर्चा के बाद निशांत कुमार को सरकार में

शामिल करने पर सहमति बनी। संकेत साफ हैं कि यह फैसला पार्टी के दीर्घकालिक राजनीतिक संतुलन को ध्यान में रखकर लिया गया है। अंदरखाने से मिली जानकारी के अनुसार, जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया। चर्चा का केंद्र जेडीयू की संगठनात्मक स्थिरता, सामाजिक समीकरण- खासतौर पर 'लव-कुश' आधार और भविष्य के नेतृत्व को लेकर था। पार्टी के भीतर यह आकलन रहा कि अगर उत्तराधिकार का सवाल लंबे समय तक अनिश्चित रहा तो आंतरिक गुटबाजी बढ़ सकती है। ऐसे में एक नियंत्रित और चरणबद्ध तरीके से नई पीढ़ी को सामने लाने की रणनीति पर सहमति बनी और निशांत कुमार की सम्राट कैबिनेट में एंट्री पक्की हो गई। सूत्रों के अनुसार, जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और सांसद ललन सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सात सर्कुलर रोड स्थित आवास पर लंबी बैठक की। इस बैठक का मुख्य एजेंडा निशांत कुमार को कैबिनेट में शामिल करने के लिए राजी करना था। अंदरखाने से मिली जानकारी के अनुसार, इन दोनों नेताओं ने नीतीश कुमार को यह समझाया कि पार्टी के भविष्य और जदयू की दृष्टि से सामाजिक समीकरण को मजबूती देने के लिए निशांत का सरकार में होना अनिवार्य है।

बताते चले कि नीतीश कुमार हमेशा से परिवारवाद के आरोपों से बचते रहे हैं, इसलिए वे निशांत को सीधे तौर पर आगे करने में हिचक रहे थे। इससे पहले जब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने थे, तब निशांत ने यह कहते हुए पद लेने से मना कर दिया था कि वे बिना चुनाव लड़े या जमीनी अनुभव हासिल किए कोई बड़ा पद नहीं चाहते हैं, लेकिन अब बताया जाता है कि ललन सिंह और संजय झा ने निशांत के साथ अलग से कई घंटों तक बैठके की। उन्होंने निशांत को भरोसा दिलाया कि उनकी एंट्री से पार्टी के भीतर उत्तराधिकार को लेकर चल रही गुटबाजी खत्म हो जाएगी और कार्यकर्ताओं में एक नया उत्साह जगेगा। निशांत कुमार को मनाने के लिए उनकी हालिया 'सद्भाव यात्रा' के फीडबैक का सहारा लिया गया। नेताओं ने उन्हें बताया कि जिस तरह से चंपारण से लेकर मगध तक युवाओं ने उनका स्वागत किया है, वह इस बात का संकेत है कि बिहार का युवा वर्ग उन्हें एक उम्मीद के तौर पर देख रहा है। बताया जा रहा है कि उन्हें संजीदगी से यह समझाया गया कि "बिना पद के सेवा की एक सीमा होती है, लेकिन सरकार में रहकर आप बदलाव ला सकते हैं"। जानकारी के मुताबिक, दिग्गज नेताओं के इसी तर्क ने आखिरकार निशांत कुमार के इरादों को बदल दिया। दूसरी ओर अंदरखाने की खबर यह भी है कि जेडीयू के भीतर कई गुट सक्रिय हैं। वरिष्ठ नेताओं को डर था कि अगर नीतीश कुमार के बाद कोई सर्वमान्य चेहरा सामने नहीं आया तो पार्टी बिखर सकती है। संजय झा और ललन सिंह ने नीतीश कुमार को राजी किया कि निशांत को अभी से 'प्रशासनिक ट्रेनिंग' देना जरूरी है, ताकि भविष्य में वे पार्टी की कमान संभाल सकें। इसी 'फ्यूचर प्लान' के तहत निशांत को मंत्री पद स्वीकार करने के लिए मनाया गया।

लब्बोलुआब है कि साल 2005 से बिहार की राजनीति नीतीश कुमार के इर्द-गिर्द घूमती रही है। उनके राजनीतिक कौशल का हर कोई कायल है। हाल ही में बिहार की सियासत में बड़ा बदलाव तब आया जब नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर भाजपा को बड़े भाई की भूमिका सौंपी। इसके बाद सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने। 7 मई को हुए मंत्रिमंडल विस्तार में निशांत कुमार की अचानक एंट्री ने सबको चौंका दिया। वह लगातार सक्रिय राजनीति से दूरी बनाने की बात कहते रहे थे, पर ऐन मौके पर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री के रूप में उन्होंने

निशांत कुमार
स्वास्थ्य मंत्री

शपथ ली। राजनीति में आए उन्हें महज कुछ ही महीने हुए हैं, लेकिन उनके जवाब किसी मंजे हुए राजनेता की तरह हैं। स्वास्थ्य मंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के दौरान उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उनके जवाब ने सबका दिल जीत लिया। बता दें कि निशांत कुमार स्वास्थ्य मंत्री के रूप में अपने कार्यालय पहुंचे। मीडिया ने उन पर सवालों की बौछार कर दी। विभाग से जुड़े एक सवाल पर निशांत ने बेहद शालीनता और सरलता से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अभी तो आया हूं, पहले दिन आज थोड़ा जान लूं, फिर कुछ कहूंगा। लंबी-चौड़ी घोषणाएं करने के बजाय उनकी इस स्पष्टवादिता ने लोगों को प्रभावित किया है। सोशल मीडिया पर उनके इस सादगी भरे अंदाज की काफी चर्चा हो रही है। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से राजनेता बने निशांत कुमार से बिहार के युवाओं को काफी उम्मीदें हैं। जहां एक ओर विपक्षी खेमा और सोशल मीडिया का एक धड़ा उन्हें अनुभव की कमी के कारण ट्रोल कर रहा है। वहीं समर्थकों का मानना है कि उनकी तकनीकी समझ बिहार के स्वास्थ्य ढ़ांचे को हाई-टेक बनाने में मील का पत्थर साबित होगी। अब यह भविष्य के गर्भ में है कि निशांत अपने पिता नीतीश कुमार जैसी अमिट छाप छोड़ पाते हैं या अपनी एक अलग पहचान बनाते हैं। हालांकि संजय झा और ललन सिंह की इस सफल घेराबंदी ने अब जेडीयू के भविष्य का रास्ता साफ कर दिया है। अब देखना यह होगा कि 'टीम निशांत' शासन व्यवस्था में क्या नया बदलाव लेकर आते है। ऐसे में आने वाले समय में यही देखना दिलचस्प होगा कि निशांत कुमार सरकार और संगठन के बीच किस तरह संतुलन बनाते हैं और जेडीयू को किस दिशा में ले जाते हैं।

बहरहाल, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में हुए बिहार कैबिनेट विस्तार में इस बार सिर्फ जातीय और क्षेत्रीय संतुलन ही नहीं, बल्कि राजनीतिक विरासत की भी खास झलक देखने को मिली। सम्राट कैबिनेट में बिहार के तीन पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे मंत्री बने हैं। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की है, जिन्होंने पहली बार मंत्री पद की शपथ लेकर न सिर्फ अपनी पार्टी जेडीयू बल्कि बिहार के लोगों को भी बड़ा मैसेज दिया है। निशांत कुमार के अलावा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत जगन्नाथ मिश्रा के बेटे नीतीश मिश्रा और पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन भी सम्राट कैबिनेट का हिस्सा बने हैं। ऐसे में बिहार की राजनीति में एक बार फिर 'सियासी विरासत' चर्चा के केंद्र में आ गई है। सम्राट कैबिनेट की सबसे बड़ी राजनीतिक घटना निशांत कुमार की एंट्री मानी जा रही है। लंबे समय तक सक्रिय राजनीति और किसी पद से दूरी बनाए रखने वाले निशांत कुमार आखिरकार स्वास्थ्य मंत्री बना दिये गए। बिहार की राजनीति में कई बार यह चर्चा होती रही कि क्या नीतीश कुमार अपने बेटे को राजनीति में लाएंगे या नहीं। हालांकि नीतीश कुमार हमेशा परिवारवाद के सवाल पर बचते रहे, लेकिन इस बार निशांत कुमार को कैबिनेट में जगह देकर जेडीयू ने बड़ा राजनीतिक संदेश दिया है। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान एक भावुक तस्वीर भी देखने को मिली, जब निशांत कुमार ने मंच पर अपने पिता नीतीश कुमार के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और नीतीश कुमार ने बेटे की पीठ थपथपाकर शुभकामनाएं दीं। वही सम्राट कैबिनेट में तीन पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे के मंत्री बनने की लिस्ट में दूसरा नाम पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा के बेटे नीतीश मिश्रा का आता है। हालांकि ये पहले से बिहार की राजनीति में सक्रिय हैं और पहले भी मंत्री भी रह चुके हैं। मिथिला क्षेत्र में उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। नीतीश मिश्रा को बीजेपी ने एक बार फिर कैबिनेट में शामिल कर ब्राह्मण समाज और मिथिला क्षेत्र दोनों को साधने की कोशिश की है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि नीतीश मिश्रा सिर्फ 'पूर्व सीएम के बेटे' नहीं, बल्कि संगठन और प्रशासनिक अनुभव वाले नेता के तौर पर भी अपनी पहचान बना चुके हैं। वही इस सूची में तीसरे मंत्री संतोष सुमन हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बेटे हैं, जिन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिली है। हालांकि वह पहले भी मंत्री रह चुके हैं। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की राजनीति में संतोष सुमन अहम चेहरा माने जाते हैं। दलित राजनीति में उनकी पकड़ और मांझी परिवार के प्रभाव को देखते हुए एनडीए ने उन्हें फिर से कैबिनेट में शामिल किया है। माना जा रहा है कि आगामी चुनावों में महादलित वोट बैंक को साधने में संतोष सुमन की बड़ी भूमिका रहने वाली है। हालांकि सम्राट कैबिनेट में तीन पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटों को जगह मिलने के बाद बिहार की राजनीति में परिवारवाद और राजनीतिक विरासत पर चर्चा तेज हो गई है। दिलचस्प बात यह है कि लंबे समय तक परिवारवाद के खिलाफ बयान देने वाले दलों में भी अब राजनीतिक परिवारों के चेहरे मजबूत हो रहे हैं। हालांकि राजनीतिक दल इसे अनुभव, सामाजिक पकड़ और संगठनात्मक क्षमता से जोड़कर देखते हैं,

निशांत कुमार नीतीश मिश्रा संतोष सुमन सम्राट चौधरी

लेशी सिंह

श्वेता गुप्ता

शीला कुमारी

रमा निषाद

श्रेयशी सिंह

लेकिन विपक्ष इसे परिवारवाद का नया चेहरा बताकर सवाल उठा सकता है।

गौरतलब है कि बिहार में नई सरकार के गठन के 22 दिन बाद बहुप्रतीक्षित कैबिनेट विस्तार पूरा हो गया। पटना के गांधी मैदान में आयोजित भव्य शपथ ग्रहण समारोह के बाद देर शाम विभागों का बंटवारा भी कर दिया गया। इस नई कैबिनेट में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपनी धमक बनाए रखी है, जबकि सामाजिक समीकरणों और आधी आबादी की भागीदारी का भी विशेष ध्यान रखा गया है। बता दें कि सम्राट कैबिनेट में महिला सशक्तिकरण की झलक साफ दिख रही है। कुल 5 महिला मंत्रियों को कैबिनेट में जगह दी गई है, जिनमें 3 जदयू और 2 भाजपा कोटे से हैं, जिनमें जदयू कोटे से लेशी सिंह हैं, इन्हें भवन निर्माण विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। इसके बाद नाम श्वेता गुप्ता का आता है। इन्हें समाज कल्याण विभाग सौंपा गया है। बता दें कि यह पहली बार मंत्री बनी हैं। इसके बाद नाम शीला कुमारी का आता है और ये विज्ञान, प्राद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग संभालेंगी। वही भाजपा कोटे बनी महिला मंत्रियों में नाम रमा निषाद को शामिल किया गया है और इन्हें पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का जिम्मा मिला है। इसके साथ ही अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज और विधायक श्रेयशी सिंह को उद्योग और खेल विभाग की कमान दी गई है। विदित हो कि सम्राट कैबिनेट में बनी ये पांच महिला मंत्रियों में एक नाम श्वेता गुप्ता का

श्वेता गुप्ता, मंत्री

सुर्खियों में है। बिहार की राजनीति में जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ताजा 'मास्टरस्ट्रोक' चर्चा का विषय बना हुआ है। शिवहर से पहली बार की विधायक डॉ. श्वेता गुप्ता को सम्राट चौधरी मंत्रिमंडल में शामिल करवाकर जेडीयू ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। राजनीति के जानकारों की नजर में यह निर्णय केवल एक मंत्री पद की नियुक्ति नहीं, बल्कि बाहुबली आनंद मोहन के परिवार के लिए एक सीधा राजनीतिक संदेश माना जा रहा है। दरअसल, शिवहर लंबे समय से बाहुबली आनंद मोहन और उनके परिवार का प्रभाव क्षेत्र रहा है, लेकिन डॉ. श्वेता गुप्ता को मंत्री बनाए जाने के पीछे का कारण कहीं न कहीं जातिगत समीकरण को प्रभावित करने की कवायद कहा जा रहा है।

बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू ने वैश्य समाज से आने वाली भाजपा की सीटिंग सांसद रमा देवी का टिकट काटकर आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद को मैदान में उतारा था। हालांकि लवली आनंद जीत गईं, लेकिन वैश्य वोटरों की नाराजगी ने जेडीयू नेतृत्व की चिंता बढ़ा दी थी, लेकिन, 2025 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने एक बड़ा प्रयोग करते हुए आनंद मोहन के बेटे और तत्कालीन विधायक चेतन आनंद को औरंगाबाद की नबीनगर सीट पर शिफ्ट कर दिया और उनकी जगह डॉ. श्वेता गुप्ता को मैदान में उतारा था। श्वेता गुप्ता ने न केवल यह सीट जीती, बल्कि राजद के नवनीत कुमार को 31,398 वोटों के बड़े अंतर से हराकर अपनी ताकत साबित की। खास बात यह कही जा रही है कि डॉ. श्वेता गुप्ता वैश्य/सूड़ी समुदाय से आती हैं और इन्हें समाज कल्याण मंत्री बनाकर पार्टी ने न केवल उस नाराजगी को दूर करने की कोशिश की है, बल्कि अब उन्हें मंत्री बनाकर नीतीश कुमार की

श्वेता गुप्ता

आनंद मोहन एवं लवली आनंद

जेडीयू ने शिवहर में आनंद मोहन के समांतर एक नया और बेदाग चेहरा स्थापित कर दिया है। इसके साथ ही, वे शिवहर के 78 साल के इतिहास में पहली महिला विधायक और अब मंत्री बनकर महिला सशक्तिकरण का एक बड़ा चेहरा बन गई हैं। वही राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि श्वेता गुप्ता की 'ताजपोशी' के पीछे जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के खिलाफ आनंद मोहन की हालिया बयानबाजी एक मुख्य कारण है। बता दें कि हाल के दिनों में आनंद मोहन ने जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था, जिससे पार्टी के भीतर असहज स्थिति पैदा हो गई थी। आनंद मोहन ने सार्वजनिक रूप से संजय झा की भूमिका पर सवाल उठाए थे, जिसे पार्टी नेतृत्व ने अनुशासनहीनता के तौर पर देखा। दिलचस्प बात यह है कि श्वेता गुप्ता की ताजपोशी में संजय झा की महत्वपूर्ण भूमिका बताई जा रही है जो आनंद मोहन के लिए एक कड़ा जवाब माना जा रहा है। वही जानकारों का मानना है कि यदि आनंद मोहन ने ये बयान नहीं दिए होते तो उनके बेटे चेतन आनंद मंत्री पद की दौड़ में आगे हो सकते थे। लेकिन, श्वेता गुप्ता को मंत्री बनाना इस बात का प्रमाण है कि नीतीश कुमार अब पार्टी के भीतर किसी भी प्रकार की गुटबाजी या शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ टिप्पणी बर्दाश्त करने के मूड में नहीं हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि श्वेता गुप्ता को मंत्री बनाकर नीतीश कुमार ने यह साफ कर दिया है कि पार्टी नेतृत्व के खिलाफ बयानबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पेशे से डॉक्टर और करोड़ों की संपत्ति की मालकिन डॉ. श्वेता गुप्ता ने 2025 के विधानसभा चुनाव में शिवहर सीट से ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। जेडीयू ने आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद को शिवहर से हटाकर औरंगाबाद की नबीनगर सीट पर भेजा था और श्वेता गुप्ता को टिकट दिया। उन्होंने राजद के नवनीत कुमार को 31,398 वोटों के बड़े अंतर से हराकर अपनी ताकत साबित की। आजादी के बाद शिवहर से

संजय झा

वह पहली महिला विधायक चुनी गई थीं और अब मंत्री बनकर उन्होंने जिले को ढाई दशक बाद मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व दिलाया है। जानकारी के अनुसार, श्वेता गुप्ता पेशे से एक डॉक्टर हैं और उनकी छवि काफी सौम्य और शिक्षित नेता की है। 44 वर्षीय डॉ. श्वेता गुप्ता का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है जो उन्हें बिहार की नई पीढ़ी के नेताओं में अलग खड़ा करता है। सीतामढ़ी और शिवहर इलाके में चिकित्सा सेवा के माध्यम से उन्होंने जो लोकप्रियता हासिल की, उसका लाभ पार्टी अब पूरे राज्य में वैश्य वोट बैंक को साधने के लिए उठाना चाहती। करोड़ों की संपत्ति की मालकिन होने के बावजूद, डॉ. श्वेता गुप्ता ने धरातल पर अपनी सक्रियता से जनता का भरोसा जीता है। इसके साथ ही श्वेता गुप्ता बिहार की नई और साफ-सुथरी राजनीति का प्रतिनिधि बनकर सामने आई हैं। निश्चित रूप से, श्वेता गुप्ता का उदय शिवहर की सांसद लवली आनंद और आनंद मोहन के परिवार की राजनीति के लिए एक बड़ी चुनौती के तौर पर उभरी हैं।

बहरहाल, सम्राट केबिनैट का विस्तार हो गया है। इसमें कई नये और पुराने चेहरे को मौका मिला है, लेकिन बिहार की नई सरकार यानी सम्राट चौधरी मंत्रिमंडल में शामिल एक नाम इन दिनों काफी चर्चा में हैं। ये राजनीति में चमक धमक वाले परिवार से नहीं है। गरीबी की बेड़ियां को तोड़ते हुए मंत्री पद तक पहुंचे हैं। बात की जा रही है डॉ. प्रमोद कुमार चंद्रवंशी की। जिनके मंत्री बनने की खबर ने न केवल उनके पैतृक गांव जहानाबाद के नेरथुआ मठ में खुशियाँ बिखेरी हैं। बल्कि संघर्ष कर रहे लाखों युवाओं को एक नई उम्मीद दी है। प्रमोद चंद्रवंशी की पहचान आज एक कद्दावर नेता के रूप में है, लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब वे पटना की सड़कों पर साइकिल से अखबार बांटा करते थे। जहानाबाद के एक बेहद साधारण किसान परिवार में जन्मे प्रमोद के लिए उच्च शिक्षा का खर्च उठाना नामुमकिन सा था। उनके पिता अयोध्या प्रसाद खेती-बाड़ी से बमुश्किल घर चलाते थे। अपनी पढ़ाई का खर्च निकालने के लिए प्रमोद ने पटना के पोस्टल पार्क इलाके में रहकर कई छोटे-बड़े काम किए। वे सुबह-सुबह अखबार बांटने निकलते, फिर घर-घर जाकर सरसों का तेल बेचते थे। इसी कड़ी मेहनत से मिली पाई-पाई जोड़कर उन्होंने अपनी डिग्री हासिल की और राजनीति के ककहरे सीखे। दिलचस्प बात यह है कि उनका तेल का व्यवसाय आज भी जारी है, जिसे अब उनके कर्मचारी संभालते हैं। प्रमोद चंद्रवंशी भले ही वे दूसरी बार मंत्री पद की शपथ ले चुके हों, लेकिन जमीन से जुड़ाव आज भी वैसा ही है। गांव के लोग बताते हैं कि महज दो साल पहले तक मंत्री जी का

डॉ० प्रमोद चंद्रवंशी

पैतृक घर एक झोपड़ीनुमा कच्चा मकान था। बाद में भाइयों के सहयोग से वहां एक छोटा सा पक्का मकान बनाया गया। उनके भाई पटना की एक गैस एजेंसी में मामूली वेतन पर नौकरी करते थे, जो इस परिवार की सादगी और ईमानदारी को बतलाता है। छात्र जीवन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़कर राजनीति की शुरुआत करने वाले प्रमोद चंद्रवंशी पहले भी नीतीश सरकार में वन, पर्यावरण एवं सहकारिता मंत्री रह चुके हैं। उनकी यह सफलता रातों-रात नहीं मिली, बल्कि दशकों के संघर्ष, त्याग और अटूट समर्पण का परिणाम है। डॉ. प्रमोद चंद्रवंशी की यह कहानी सिखाती है कि साधन सीमित हो सकते हैं, पर सपने नहीं। आज जब वे सम्राट सरकार में नई जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, तो पूरा जिला उनकी सादगी और जीवटता पर गर्व कर रहा है।

सम्राट कैबिनेट में एक नाम नंद किशोर राम का भी है जो पश्चिमी चंपारण के रामनगर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक हैं और सम्राट चौधरी कैबिनेट विस्तार में एक प्रमुख अनुसूचित जाति चेहरा बनकर उभरे हैं। नंद किशोर राम ने 2025 के विधानसभा चुनाव में रामनगर (सुरक्षित) सीट से राजद के सुबोध कुमार को करीब 35,000 से अधिक मतों के अंतर से हराकर पहली बार विधानसभा में कदम रखा था। भाजपा ने इस सीट पर अपनी दिग्गज नेता और पद्मश्री से सम्मानित भागीरथी देवी का टिकट काटकर नंद किशोर राम पर भरोसा जताया था, जिस पर वे पूरी तरह खरे उतरे और

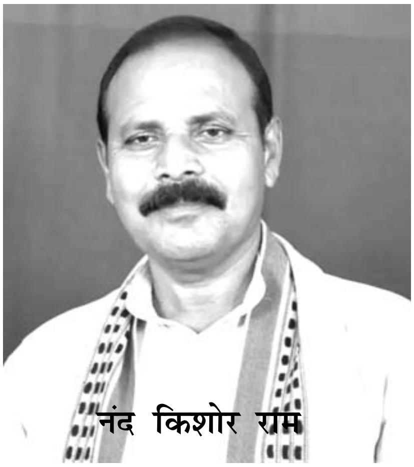

नंद किशोर राम

अब उन्हें इसका पुरस्कार मिला है। 53 वर्षीय नंद किशोर राम स्नातक हैं और राजनीति में आने से पहले एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं। वे भाजपा संगठन में बगहा जिला उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी भी निभा चुके हैं। उनकी छवि एक जमीन से जुड़े कार्यकर्ता की रही है, जो पार्टी के 'अंत्योदय' के सिद्धांत पर काम करते आए हैं। उनका बेदाग राजनीतिक करियर और सांगठनिक पकड़ ही उन्हें आज मंत्री पद की दहलीज तक ले आई है। बता दें कि नंद किशोर राम को कैबिनेट में शामिल कर भाजपा ने चंपारण के तराई इलाकों और थारू- अनुसूचित जाति बाहुल्य आबादी को एक बड़ा संदेश दिया है। भागीरथी देवी के उत्तराधिकारी के रूप में उन्हें मिली यह जिम्मेदारी क्षेत्र के विकास और सामाजिक न्याय को मजबूती देने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। सबसे खास बात तो यह कि एक जमीन से जुड़े कार्यकर्ता से मंत्री पद तक का उनका यह सफर राज्य की राजनीति में दलित नेतृत्व को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब नंदकिशोर राम के कंधों पर रामनगर के साथ-साथ पूरे प्रदेश के विकास की बड़ी जिम्मेदारी होगी।

बहरहाल, बिहार की राजनीति में सत्ता समीकरण के बदलते ही विभागों का बंटवारा हमेशा चर्चा का विषय रहता है। बिहार में नीतीश कुमार ने अपने करीब 20 वर्षों के शासनकाल में शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी जदयू कोटे के करीबी मंत्रियों को ही सौंपी। इस दौरान अनुसूचित जाति वर्ग से आने वाले अशोक चौधरी और सुनील कुमार भी शिक्षा मंत्री रहे। सम्राट चौधरी सरकार में शिक्षा विभाग को भाजपा ने अपने पास रखने का फैसला लिया है। वहीं शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी सवर्ण समाज से आने वाले बैकुंठपुर के विधायक मिथिलेश तिवारी को सौंपी गई है। बीजेपी की कोशिश राज्य की शैक्षणिक व्यवस्था में बदलाव लाने की है। ज्ञात हो कि मिथिलेश तिवारी 1988 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े और 1990 में भारतीय जनता पार्टी से सक्रिय राजनीति में आए। उसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने लगातार पार्टी में कई जिम्मेदारियों को निभाया है। राजद के शासन में पहली बार भाजपा ने मिथिलेश तिवारी को कटेया विधानसभा सीट से 2005 के फरवरी में उम्मीदवार बनाया। बसपा के उम्मीदवार रहे अमरेंद्र कुमार पांडेय उर्फ पप्पू पांडेय से उनका मुकाबला रहा, लेकिन उन्हें चुनाव हारना पड़ा। उसके बाद 2015 में जदयू और भाजपा जब अलग चुनाव मैदान में आये तो बैकुंठपुर से भाजपा ने भरोसा जताते हुए मिथिलेश तिवारी को चुनाव मैदान में उतारा। तब जदयू-राजद को पीछे छोड़कर उन्होंने चुनाव में जीत हासिल की। 2020 के चुनाव में एनडीए ने बैकुंठपुर से चुनाव मैदान में उतारा, लेकिन इस बार उन्हें जीत नहीं मिल सकी। इसके बाद वर्ष 2025 में हुए चुनाव में मिथिलेश तिवारी ने राजद को हरा कर परचम लहराया था। बिहार सरकार में पहली बार मंत्री बने मिथिलेश तिवारी ने अपने करियर की शुरुआत पटना में शिक्षक के रूप में की। गोपालगंज जिले के सिधवलिया प्रखंड अंतर्गत डुमरिया निवासी देवनारायण तिवारी के पुत्र मिथिलेश तिवारी के पिता देवनारायण तिवारी पटना में पीडब्लूडी विभाग में कर्मी थे। मिथिलेश तिवारी ने पटना में रहकर अर्थशास्त्र में बीए ऑनर्स किया और

मिथिलेश तिवारी

अपने शुरुआती जीवन में कुछ समय के लिए पटना में कोचिंग भी चलाते रहे और अब यह बिहार के शिक्षा मंत्री बनाये गये हैं। हालांकि बिहार सरकार में पहली बार मंत्री बने मिथिलेश तिवारी ने अपने दम पर अपनी पहचान बनाई है। उनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं रहा है। अपनी व्यवहार कुशलता, वाकपटुता और प्रखर वक्ता की छवि के कारण उन्होंने पार्टी में अपनी पकड़ बनाई और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का विश्वास जीत लिया। समय के साथ पार्टी में उनके समर्पण और कड़ी मेहनत के लिए उन्हें जाना और पहचाना जाने लगा, जिसका परिणाम आज मंत्री पद के रूप में सामने आया। इसके साथ ही बैकुंठपुर विधानसभा को 41 वर्षों बाद मंत्री पद मिला है। इससे पहले यहां से विधायक रहे ब्रजकिशोर नारायण सिंह उर्फ बाबू साहेब 1982 से 1985 तक बिहार सरकार में मंत्री रहे थे। तब बाबू साहब से उनको जाना जाता था। उनके ही पुत्र मंजीत सिंह बरौली से विधायक हैं। बैकुंठपुर में आज भी बाबू साहब को लोग सम्मान से नाम लेते है।

विदित हो कि बिहार की सियासी राजनीति में इन दिनों बहुत कुछ शोर शराबे के बिना हो जा रहा है। वह भी ऐसे कि दाएं हाथ से लिया गया फैसला बाएं हाथ को ही पता नहीं चल रहा। राजनीतिक गलियारे में चल रही चर्चा को मानें तो अभी एक और पॉलिटिकल धमाका होना बाकी है। हालांकि यह बदलाव वाला धमाका तो उसी दिन हो गया था जब जदयू से

निशांत कुमार

चंद्रमोहन राय

नंदकिशोर यादव

मंगल पाण्डेय

तेजप्रताप यादव

तेजस्वी यादव

शिक्षा विभाग ले लिया गया और बदले में बीजेपी ने स्वास्थ्य विभाग दे दिया। लेकिन इसी दिन कई और फैसले हुए। सूत्र बताते हैं कि एक और निर्णय होना अभी बाकी ही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष और विधान परिषद् के सभापति को लेकर शायद पेच फंस गया है। इसलिए अभी तक जनता के बीच कुछ भी नहीं आया। सनद् रहे कि जबसे एनडीए की सरकार बिहार में रही, शिक्षा विभाग हमेशा जदयू के पास रहा और स्वास्थ्य विभाग बीजेपी के पास। स्वास्थ्य महकमे में सुधार की नींव सबसे पहले चंद्रमोहन राय ने संभाली। इसके बाद नंदकिशोर यादव और फिर लगातार मंगल पांडेय स्वास्थ्य मंत्री रहे। बीच में महागठबंधन की सरकार में तेज प्रताप और तेजस्वी भी रहे, पर इस बार एक बड़ा फेरबदल हुआ। संभवत: निशांत कुमार को ले कर शिक्षा विभाग बनाम स्वास्थ्य विभाग की अदला-बदली की गई। खासतौर पर निशांत कुमार तो हेल्थ डिपार्टमेंट का महत्व और सिस्टम समझने के लिए लगातार दफ्तर आ रहे हैं। यहां तक कि शनिवार को भी ऑफिस का ताला खुलवाया और कई सख्त निर्देश भी जारी किए। वही बता दें कि एनडीए के शीर्ष नेतृत्व के साथ स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग के साथ-साथ विधानसभा अध्यक्ष और विधान परिषद् के सभापति पद को लेकर भी बात हुई। सूत्र बताते हैं कि बीजेपी को विधानसभा अध्यक्ष पद के बदले में विधान परिषद् में सभापति पद देने को लेकर बारगेनिंग हो रही है। ऐसे में बीजेपी ने संभवत: विधानपरिषद सभापति का पद नहीं लेने का मन बना लिया है। हो सकता है कि विधानसभा सत्र शुरू होने के साथ ही इसका खुलासा हो। वर्तमान में विधान परिषद् सभापति के पद पर अभी अवधेश नारायण सिंह हैं। अब देखना यह है कि यह फैसला कब और किन हालात में होता है।

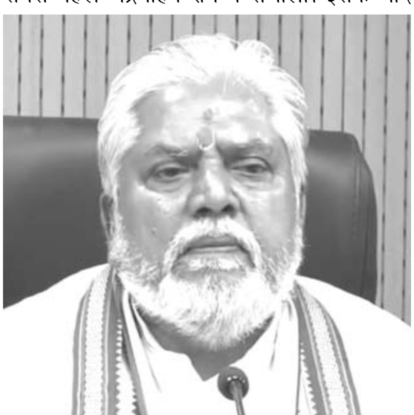
डॉ० प्रेम कुमार

गौरतलब है कि बिहार में सम्राट कैबिनेट के विस्तार के बाद सबसे ज्यादा चर्चा जिस नेता को लेकर हो रही है, वह हैं मंगल पांडेय की। कैबिनेट विस्तार में 32 मंत्रियों ने शपथ ली, लेकिन पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय को नई कैबिनेट में जगह नहीं मिली। इसके बाद राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक यह सवाल उठने लगा कि आखिर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और लंबे समय तक संगठन में अहम भूमिका निभाने वाले मंगल पांडेय को मंत्रिमंडल से बाहर क्यों रखा गया? हालांकि, राजनीति में हर फैसला सिर्फ पद से नहीं मापा जाता। यही वजह है कि मंत्री नहीं बनने के बावजूद बीजेपी के भीतर मंगल पांडेय का कद लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बिहार ही नहीं, पश्चिम

अवधेश नारायण सिंह

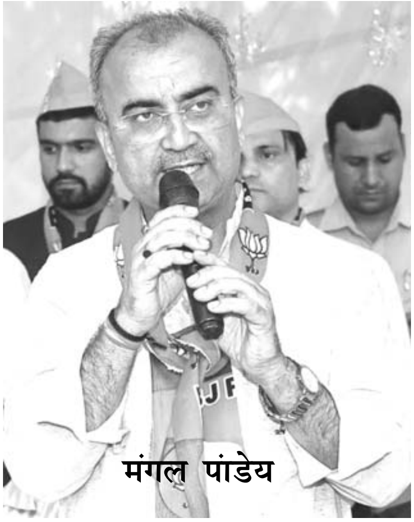

मंगल पांडेय

गृह मंत्री अमित शाह के साथ मंगल पांडेय

बंगाल तक उनके नाम की चर्चा तेज हो गई है। बीजेपी के अंदरूनी सूत्रों और राजनीतिक जानकारों की मानें तो मंगल पांडेय की सबसे बड़ी ताकत उनकी संगठनात्मक पकड़ मानी जा रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में पार्टी ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी थी। बंगाल प्रभारी के तौर पर उन्होंने लगातार संगठन को मजबूत करने, कार्यकर्ताओं को सक्रिय रखने और चुनावी रणनीति को जमीन पर उतारने का काम किया। चुनाव के दौरान मंगल पांडेय लगातार राज्य के नेताओं, केंद्रीय नेतृत्व और कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय बनाते नजर आए। यही वजह रही कि चुनाव खत्म होने के बाद भी केंद्रीय नेतृत्व का भरोसा उन पर और मजबूत हुआ। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि बीजेपी में संगठनात्मक क्षमता को हमेशा बड़ी अहमियत दी जाती है और मंगल पांडेय ने खुद को एक मजबूत संगठनकर्ता के रूप में साबित किया है। वही मंगल पांडेय के बढ़ते कद की सबसे बड़ी झलक बिहार कैबिनेट विस्तार के दौरान देखने को मिली। पटना के गांध ी मैदान में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंच पर पहुंचे तो उनकी मुलाकात मंगल पांडेय से बेहद गर्मजोशी भरी रही। अमित शाह ने मंच पर मंगल पांडेय से अलग से बातचीत की और उनके कान में कुछ कहा। इसके बाद राजनीतिक चर्चाओं का दौर तेज हो गया। बीजेपी के अंदरूनी हलकों में यह चर्चा शुरू हो गई कि अमित शाह ने मंगल पांडेय को भविष्य में बड़ी जिम्मेदारी मिलने का संकेत दिया है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि बीजेपी में इस तरह के संकेत काफी अहम माने जाते हैं। खासकर तब, जब किसी नेता को मंत्रिमंडल में जगह न मिलने के बावजूद केंद्रीय नेतृत्व सार्वजनिक मंच पर इतना महत्व देता दिखाई दे। वहीं पश्चिम बंगाल में बीजेपी विधायक दल की बैठक के दौरान भी मंगल पांडेय की सक्रियता चर्चा का विषय बनी रही। बैठक के बाद बंगाल में बीजेपी विधायक दल के नेता सुवेंदु अधिकारी की घोषणा के दौरान भी मंगल पांडेय लगातार अमित शाह के साथ नजर आए। इस दौरान सुवेंदु अधिकारी ने भी मंगल पांडेय के काम की तारीफ की। अमित शाह और मंगल पांडेय के बीच लगातार हो रही बातचीत ने यह साफ संकेत दिया कि पार्टी संगठन में उनकी भूमिका अब पहले से कहीं अधिक मजबूत हो चुकी है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि फिलहाल मंगल पांडेय को कैबिनेट से दूर रखकर संगठन या केंद्र में बड़ी भूमिका देने की तैयारी हो सकती है। यही वजह है कि मंत्री नहीं बनने के बावजूद उनका राजनीतिक प्रभाव कम होने के बजाय और बढ़ता दिखाई दे रहा है। सियासी गलियारे में चर्चा है कि आने वाले कुछ महीनों में मंगल पांडेय केंद्रीय कैबिनेट में भी शामिल हो सकते हैं। हालांकि इसको लेकर कहीं कुछ भी आधिकारिक रूप से नहीं कहा गया है। मंगल पांडेय को लेकर अब सिर्फ बिहार में ही नहीं, बल्कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में भी चर्चा तेज हो गई है। बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच यह संदेश गया है कि केंद्रीय नेतृत्व अब भी उन पर पूरा भरोसा जता रहा है। यही कारण है कि सम्राट कैबिनेट में शामिल नहीं होने के बावजूद मंगल पांडेय लगातार राजनीतिक सुर्खियों में बने हुए हैं। आने वाले दिनों में पार्टी उन्हें कौन सी नई जिम्मेदारी देती है, इस पर अब सभी की नजर टिकी हुई है।

बहरहाल, बिहार में सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली कैबिनेट का विस्तार कई मायनों में ऐतिहासिक और रणनीतिक माना जा रहा है। कैबिनेट में जातिगत संतुलन बनाने के लिए हर वर्ग को प्रतिनिधित्व दिया गया है। बिहार में नीतीश कुमार के समय से ही लव-कुश (कुर्मी-कोयरी) समीकरण एनडीए की मजबूती का आधार रहा है। मौजूदा कैबिनेट में भी इस पर सबसे ज्यादा भरोसा जताया गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी खुद कोयरी-कुशवाहा समाज से आते हैं। उनके साथ कुर्मी-कोयरी समाज के चार बड़े चेहरों को मंत्री बनाया गया है। इसमें निशांत कुमार, श्रवण कुमार, भगवान सिंह कुशवाहा और दीपक प्रकाश शामिल हैं। सरकार का यह कदम कुर्मी और कुशवाहा वोट बैंक को एकजुट रखने की बड़ी कोशिश है। आरजेडी के एम-वाई समीकरण को चुनौती देने के लिए यह गठजोड़ काफी अहम माना जा रहा है। बिहार की आबादी में लगभग 36 प्रतिशत हिस्सा अति पिछड़ा वर्ग का है। नीतीश कुमार की तरह ही सम्राट

# किस मंत्री को कौन सा मिला विभाग?

| | |
|---|---|
| सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री | : सामान्य प्रशासन, मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी, निर्वाचन, सिविल विमानन और ऐसे सभी विभाग रखे हैं, जो किसी को आवंटित नहीं किए गए हैं. |
| विजय कुमार चौधरी, उपमुख्यमंत्री | : जल संसाधन एवं संसदीय कार्य |
| विजेन्द्र प्रसाद यादव, उपमुख्यमंत्री | : वित्त एवं वाणिज्य-कर |
| निशांत कुमार | : स्वास्थ्य मंत्रालय |
| विजय सिन्हा | : कृषि मंत्रालय |
| नीतीश मिश्र | : नगर विकास आवास विभाग व सूचना प्रौद्योगिकी |
| दिलीप जायसवाल | : राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग |
| श्रवण कुमार | : ग्रामीण विकास और सूचना एवं जन संपर्क |
| लेसी सिंह | : भवन निर्माण विभाग |
| रामकृपाल यादव | : सहकारिता विभाग |
| दामोदर रावत | : परिवहन विभाग |
| संजय सिंह टाइगर | : उच्च शिक्षा और विधि विभाग |
| अशोक चौधरी | : खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग |
| भगवान सिंह कुशवाहा | : योजना एवं विकास विभाग |
| अरुण शंकर प्रसाद | : श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण युवा और रोजगार एवं कौशल विकास विभाग |
| मदन सहनी | : मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग |
| संतोष कुमार सुमन | : लघु जल संसाधन विभाग |
| रमा निषाद | : पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग |
| रत्नेश सदा | : आपदा प्रबंधन विभाग |
| कुमार शैलेंद्र | : पथ निर्माण विभाग |
| शीला मंडल | : विज्ञान प्रवैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग |
| केदार गुप्ता | : पर्यटन विभाग |
| लखेंद्र पासवान | : अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग |
| सुनील कुमार | : ग्रामीण कार्य विभाग |
| श्रेयसी सिंह | : उद्योग एवं खेल विभाग |
| जमा खान | : अल्पसंख्यक कल्याण विभाग |
| नंदकिशोर राम | : डेयरी एवं मत्स्य पशु संसाधन विभाग |
| बुलो मंडल | : ऊर्जा विभाग |
| प्रमोद कुमार | : खान एवं भूतत्व, कला एवं संस्कृति विभाग |
| श्वेता गुप्ता | : समाज कल्याण विभाग |
| रामचंद्र प्रसाद | : पर्यावरण और वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग |
| संजय सिंह | : लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग |
| संजय कुमार | : गन्ना उद्योग |
| दीपक प्रकाश | : पंचायती राज विभाग |

चौधरी ने भी इन साइलेंट वोटर्स को अपने पाले में रखने का पूरा प्रयास किया है। कैबिनेट में केदार गुप्ता (कानू), रमा निषाद (मल्लाह) और दिलीप जायसवाल जैसे चेहरों को जगह देकर ईबीसी समाज की आकांक्षाओं को पूरा करने की कोशिश की गई है। शीला मंडल के जरिए धानुक समाज को भी प्रतिनिधित्व मिला है। यह वर्ग चुनावों में निर्णायक भूमिका निभाता है। बीजेपी और जेडीयू को पता है कि सत्ता की चाबी इसी बड़े वोट बैंक के पास है। वही कैबिनेट विस्तार में महादलित और पासवान वोट बैंक का भी खास ख्याल रखा गया है। अशोक चौधरी, रत्नेश सदा और संतोष मांझी जैसे नाम दलित समाज के बड़े चेहरे हैं। वहीं चिराग पासवान की पार्टी से लखेन्द्र पासवान और संजय पासवान को शामिल कर पासवान वोटर्स को भी साधा गया है। इसके साथ ही बीजेपी ने अपने पारंपरिक फॉरवर्ड वोट बैंक को भी नाराज नहीं

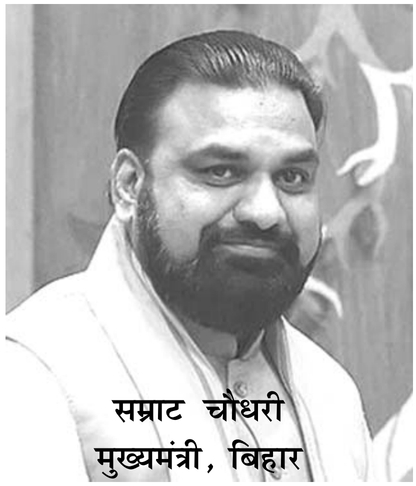

**सम्राट चौधरी**
**मुख्यमंत्री, बिहार**

होने दिया है। विजय कुमार सिन्हा और नीतीश मिश्रा के जरिए भूमिहार और ब्राह्मण समाज को प्रतिनिधित्व मिला है। राजपूत समाज से संजय टाइगर और श्रेयसी सिंह को मंत्री बनाकर एनडीए ने सवर्णों के बीच अपनी पकड़ मजबूत रखने का संकेत दिया है। इसके अलावे जेडीयू कोटे से जमा खान को कैबिनेट में शामिल करना एनडीए के लिए एक बड़ा मैसेज है। यह कदम नीतीश कुमार की सेकुलर छवि को बनाए रखने के लिए उठाया गया है। बीजेपी के मुख्यमंत्री की कैबिनेट में मुस्लिम चेहरे का होना यह बताता है कि गठबंधन सभी वर्गों को साथ लेकर चलने का दावा कर रहा है। कुल मिलाकर नई कैबिनेट एक ऐसा 'सोशल इंजीनियरिंग' फॉर्मूला है जो आरजेडी के एम-वाई समीकरण को सीधी चुनौती दे रहा है। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद भी बिहार की राजनीति में उनका प्रभाव कम नहीं हुआ है बल्कि निशांत कुमार की एंट्री से इसे और मजबूती मिली है तथा नीतीश कुमार की राजनीति को परछाई की तरह साथ रहकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जो गुड़ सीखे हैं, उनमें वह कामयाब होते दिख रहे हैं। अब बिहार में नया बदलाव हुआ है। नये मुख्यमंत्री, नये उपमुख्यमंत्री बने हैं। साथ ही सम्राट सरकार में लंबा-चौड़ा मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है। अब देखना ये है कि मुख्यमंत्री के साथ तमाम ये मंत्री क्या अपने विभागों के माध्यम से बिहार के विकास को धरातल पर ला पाने में संभव होंगे या फिर विकास कागजों पर ही रह जायेंगे? क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 20 वर्षों के कार्यों के दौराज किये गये जो विकास अभी दिख रहा है और जो आगे दिखते-दिखते बीच में ही रूक गया, उसे पूरा कर पायेंगे या नहीं। बिहार के विकास में सम्राट चौधरी खुद को कितना साबित कर पाते हैं, यह देखना होगा! फिलहाल विभाग के तमाम मंत्रियों ने अपने-अपने विभाग की कमान हाथ में ले ली है और सम्राट मुख्यमंत्री बनते ही एक्शन में दिख रहे हैं।●

● **अमित कुमार**

इन दिनों राजधानी पटना समेत प्रदेश के कई जिले हत्या और दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराधों की ढ़ेर पर बैठे हैं और इनमें हर नये दिन इजाफा ही हो रहा है। इसे क्या हम सुशासन का अंत कहेंगे? सीएम सम्राट के सारे दावे फेल हो रहे हैं? बिहार पुलिस को कड़े आदेश के बाद भी अपराध रोक पाने में अक्षम क्यों? बीते कई दिनों के भीतर बिहार में बढ़ते अपराध ने सुरक्षा की नीव हिलाकर रख दी है। जनता भय में है और आंकड़े बढ़ते जा रहे अपराध के। विपक्ष पहले से इस बात की हायतौबा मचाती रही है। कई बार विधानसभा में अपराध को लेकर लंबी बहश तक हुई किंतु फिल्मी डॉयलॉक मारकर मामले को रफादफा किया जा रहा है। इन दिनों की गंभीर अपराधिक घटनाओं पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार की कानून व्यवस्था बदहाल है। NCRB के आंकड़ों के अनुसार बिहार अपराध में शीर्ष पर है। विगत एक महीने में बलात्कार, हत्या, लूट और चोरी की घटनाओं में रिकॉर्डतोड़ वृद्धि हुई है लेकिन सरकार अपना जुर्म कबूल करने को तैयार ही नहीं है। बिहार में सरेराह सरेआम सत्ता संरक्षित अपराधियों द्वारा व्यवसायियों, छात्रों, शिक्षकों, आम नागरिकों और महिलाओं को कहीं भी, कभी भी गोली मारी जा रही है। सत्ता संरक्षण में अपराधी बेखौफ घूम रहे है। फायरिंग, छिनतई, बैंक लूट और राहगीरों से लूटपाट जैसी वारदातों से आमजन में दहशत का माहौल है। पुलिस शराब की तस्करी में व्यस्त और मस्त है। चरमराई हुई कानून व्यवस्था की किसी को परवाह नहीं, मुख्यमंत्री केवल हेडलाइन मैनेजमेंट को लेकर गंभीर है, विधि व्यवस्था को लेकर नहीं।

हालांकि बिहार में नीतीश युग के

तेजस्वी यादव

विराम के बाद सम्राट युग के प्रारंभ के साथ ही बिहार के लिए सबसे बड़ी चुनौती विधि-व्यवस्था को दुरूस्त करने की दिख रही है। जिस प्रकार बिहार में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा, वैसे में सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनते ही यूपी मॉडल यानि योगी आदित्यनाथ के कार्य करने के तरीकों पर अमल करने की मांग उठने लगी है। बता दें कि मुख्यमंत्री बनने से पूर्व सम्राट चौधरी राज्य के गृह मंत्री पद पर रहते हुए योगी के बुलडोजर कार्रवाई की कॉपी की थी और अब यूपी की तर्ज पर अपराधियों को सिर्फ जेल ही नहीं बल्कि ढ़ेर भी किए जाने लगे हैं। बता दें कि अहिंसावादी नीति पर कार्य करते हुए नीतीश कुमार ने अपराध पर अपने शुरूआती कार्यकाल में अंकुश लगाने का भरपूर कार्य किया, कुछ हद तक ये सफल भी हुए किन्तु बिहार में लागू हुए शराबबंदी के बाद से अपराध बढ़ते ही चले गये। शराबबंदी में छोटे से बड़े माफिया इस रोजगार में जुड़ते चले गये और ये बदस्तूर जारी है। हालात ऐसे हैं कि नये सीएम के और नए मंत्रीमंडल विस्तार के बाद मंत्रियों के कार्यालय यानि सचिवालय के भीतर ही शराब के ब्रांड चर्चा का विषय बन गये है। वही बालू उत्खनन और जमीनों से जुड़े अपराधों में इसकी संलिप्तता स्पष्ट देखी जा रही है। अपराध का दायरा बढ़ता जा रहा है, कम उम्र के युवा

# शराब बंदी पर सरकार के दावे हो रहे फेल

बिहार में शराबबंदी के जितने भी दावे सरकार कर ले किन्तु सारे दावे झूठे ही साबित होते दिख रहे हैं। ऐसे में नये सरकार के बनते ही शराब की गंध सचिवालय के भीतर ही फैल गये। जी हां, बिहार सचिवालय के विकास भवन में शराब की बोतले मिली और पूरे महकमे में हड़कंप मच गया। बता दें कि कार्यालय के पास डस्टबीन में शराब की बोतल बरामद की गई। बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून को लागू हुए वर्षो बीत चुके हैं, लेकिन राजधानी पटना के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले सचिवालय के विकास भवन से आई एक तस्वीर ने प्रशासनिक महकमे की नींद उड़ा दी है। सचिवालय के कूड़ेदान में शराब की खाली बोतलें बरामद हई, जिसके बाद पूरे परिसर में हड़कंप मच गया। कुछ कर्मियों ने बताया कि सफाईकर्मी सफाई कर रहे थे। इसी दौरान सचिवालय के विकास भवन स्थित कार्यालय के अंदर रखे डस्टबीन में रखी शराब कि बोतल पर पड़ी। सफाइकर्मी ने डस्टबिन के अंदर से शराब की बोतल बाहर निकाली तो आसपास के कर्मियों में हड़कंप मच गया। कर्मियों ने पास के कार्यालय में जाकर इस बात की जानकारी अपने अधिकारी को दी। अधिकारी भी बाहर निकले और फिर चुपचाप वहां से खिसक गए। फिर कर्मियों ने शराब की बोतल होने की जानकारी सचिवालय थाना को

दी। सूचना मिलते ही मद्य निषेध विभाग की पुलिस पहुंची और बोतल को जब्त किया। अब पुलिस सीसीटीवी खंगालकर मामले की जाँच करेगी। लोग कहने लगे कि जिस विकास भवन से पूरे प्रदेश की नीति और प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन होता है, वहां शराब के अवशेष मिलना सुरक्षा और कानून व्यवस्था दोनों पर गहरा तमाचा है। सचिवालय का यह क्षेत्र हाई-सिक्योरिटी जोन में आता है। यहां प्रवेश के लिए कड़ी मेटल डिटेक्टर जांच और सुरक्षाकर्मियों का पहरा होता है। ऐसे में शराब की बोतल का मिलना आश्चर्यजनक बात है। वही इस संदर्भ में उपमुख्यमंत्री विजय चौधरी से सवाल किया गया तो वह पत्रकारों पर भड़क गए। उन्होंने शराबबंदी कानून शब्द के गलत इस्तेमाल पर आपत्ति जताई और कानून को प्रभावी बताया। पत्रकारों ने जब सचिवालय परिसर में शराब की बोतल मिलने और राज्य में शराबबंदी की स्थिति पर सवाल पूछा, तो विजय चौधरी ने पलटकर पूछा कि क्या आपने कानून पढ़ा है? कानून का नाम जानते हैं? उन्होंने कहा कि कानून का वास्तविक नाम 'मद्य निषेध एवं उत्पाद शुल्क अधिनियम' है। इस कानून में शराब पीना, बेचना, भंडारण करना या उससे जुड़ी गतिविधियों को दंडनीय अपराध बनाया गया है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि मीडिया बार-बार शराबबंदी कानून शब्द का इस्तेमाल करता है, जबकि ऐसा कहना सही नहीं है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि हत्या करना भी अपराध है और उसके लिए कानून बना है, लेकिन क्या आप उसे 'हत्याबंदी कानून' कहते हैं? उन्होंने जोर देकर कहा कि शराब से जुड़े अपराधों पर कार्रवाई करना ही इस कानून का उद्देश्य है। मंत्री जी इस गंभीर प्रश्न पर बचकर निकलने के लिए पत्रकारों पर ही ठिकरा फोड़ दिया किन्तु अन्य सार्वजनिक जगह तो छोड़िए जहां पर सरकार के मंत्री विभाग को देखते हैं वहां पर शराब की बोतले मिलना लापरवाह और लचर कानून व्यवस्था को दर्शाता है।

राजधानी पटना में कई बन गये नये पुल, फिर भी यातायात जाम की समस्या है मौजूद

ज्यादातर अपराध में अपने पैर पसार रहे हैं, जिससे बिहार में एक बार फिर भय का माहौल पैदा होना शुरू हो गया है। यह भी सच है कि राज्य की पुलिस विधि-व्यवस्था को नियंत्रण करने से ज्यादा शराब और शराबियों को पकड़ने पर ज्यादा ध्यान देती है। दूसरी बात है कि राज्य के अन्य जिलों के साथ ही राजधानी पटना में कई पुल बनाये गये हैं, जिससे यातायात की समस्या से निजात मिल सके, किन्तु यहां भी यह समस्या कुंडली मारकर बैठ गई है। शहर के सड़कों से लेकर हाइवे तक यातायात बाधित रहते हैं तो इसके लिए यातायात पुलिसकर्मी ही जिम्मेदार हैं। यहां नियम-कानून के नाम पर ये पुलिसकर्मी क्या करते हैं, किन्ही से छुपी नहीं है। कुल मिलाकर राज्य को एक बेहतर भयमुक्त बिहार बनाने को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का पहला काम विधि व्यवस्था को बनाये रखना और आम जनों को सुरक्षा देना प्रथम प्राथमिकता में शामिल होते देखी जा रही हैं, तभी तो मुख्यमंत्री ने पुलिस को खुला चैलेंज दे डाला।

विदित हो कि बिहार की सत्ता संभालते ही सम्राट चौधरी का पुलिस को खुला चैलेंज दिखा। उन्होंने सीधे कह दिया कि बंदूक नहीं चलती तो इस्तीफा दो। वर्दी पहनने का हक उसी को जो लड़ना जानता हो। कागजी पुलिस नहीं फाइटिंग फोर्स चाहिए। अगर ट्रिगर नहीं दबा सकते तो खाकी उतार फेंको। अपराधी गोली चलाए और पुलिस मुंह ताके। अब बिहार में यह नहीं चलने वाला। सम्राट का फरमान या तो ठोकना सीखो या घर बैठो। अक्सर शांत और गंभीर रहने वाले सम्राट चौधरी का यह रौद्र रूप देखकर हर कोई हैरान है। सम्राट चौधरी ने पुलिस के जवानों और अधिकारियों को सीधे शब्दों में चेतावनी दे दी है। उनका कहना है कि अगर पुलिस लाचार दिखेगी तो जनता सुरक्षित कैसे महसूस करेगी। अपराधियों के मन में खौफ तभी होगा जब पुलिस के हाथ नहीं कांपेंगे। इसी बात को लेकर सम्राट चौधरी ने एक बड़ा अल्टीमेटम जारी कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि जिसे हथियार चलाना नहीं आता उसे वर्दी पहनने का कोई हक नहीं है। यह बयान सत्ता के गलियारों से लेकर पुलिस लाईन तक चर्चा का विषय बना हुआ है। सम्राट चौधरी ने स्पष्ट कर दिया

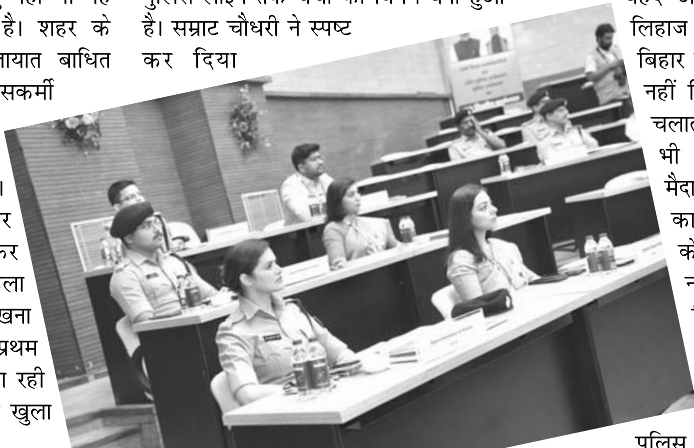

कि पुलिस की नौकरी कोई आराम की नौकरी नहीं है। अगर आप अपनी बंदूक नहीं संभाल सकते तो आपको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। सरकार आपको जनता की सुरक्षा के लिए तनख्वाह देती है ना कि घर बैठने के लिए। यह तीखी प्रतिक्रिया ऐसे समय में आई है जब बिहार पुलिस की फजीहत हो रही थी। हाल ही में सोशल मीडिय पर कई ऐसे विडियो वायरल हुए थे। इन विडियो में पुलिसकर्मी आपात स्थिति में गोली चलाने में नाकाम दिख रहे थे। कहीं बंदूक जाम हो रही थी तो कहीं पुलिसकर्मी को ट्रिगर दबाना नहीं आ रहा था। इन घटनाओं ने बिहार पुलिस की ट्रेनिंग और तैयारियों की पोल खोल कर रख दी। सम्राट चौधरी ने इन्हीं विडियो और खबरों को संज्ञान लेते हुए यह बात कही है। उनका कहना है कि सरकार पुलिस को अत्याधुनिक हथियार इसलिए देती है ताकि वह लड़ सके। करोड़ों रुपए खर्च करके पुलिस को आधुनिक सुविधाएं दी जा रही हैं। लेकिन अगर मौके पर हथियार काम ना आए तो यह पैसे और संसाधन बेकार है। सम्राट चौधरी का यह अंदाज बेहद आक्रामक था और उन्होंने भी कोई लिहाज नहीं बरता। उन्होंने कहा कि अब बिहार में ढोल मूल रवैया बिल्कुल बर्दाशत नहीं किया जाएगा। अगर अपराधी गोली चलाता है तो जवाब में पुलिस की गोली भी चलनी चाहिए। पुलिस का काम मैदान छोड़कर भागना या हथियार फंसने का बहाना बनाना नहीं है। अगर ट्रेनिंग के बावजूद कोई जवान अपना कर्तव्य नहीं निभा पा रहा तो यह गंभीर विषय है। यह सीधे तौर पर प्रदेश की सुरक्षा और जनता के विश्वास के साथ खिलवाड़ है। सम्राट चौधरी ने संकेत दिया कि अब पुलिस विभाग में सम्मान उसी को मिलेगा जो काम करेगा। सिफारिश और जुगाड़ के दम पर अब पुलिस में टिके रहना नामुमकिन होगा। प्रदर्शन के आधार पर ही अब अधिकारियों और जवानों को पोस्टिंग और सम्मान मिलेगा। उन्होंने पुलिस के आला अधिकारियों को भी कड़े निर्देश जारी किए। अब निचले स्तर के कर्मियों की ट्रेनिंग और फिटनेश की नियमित जांच होगी। सिर्फ भर्ती हो जाना काफी नहीं है बल्कि लगातार फिट रहना भी जरूरी है। हालांकि पुलिस भले ही इस बयान को कड़ा बता रही हो लेकिन सरकार का रुख साफ है। अपराधियों को मिट्टी में मिलाने के लिए पुलिस का सक्षम होना अनिवार्य है। यह बयान उन पुलिसकर्मियों के लिए आखिरी चेतावनी है जो लापरवाह हैं। अब या तो आप हथियार

विधि-व्यवस्था पर एक्शन को लेकर डीजीपी विनय कुमार से वार्ता करते सीएम सम्राट

चलाना सीख लीजिए या फिर अपना इस्तीफा तैयार रखिए। बदलते हुए बिहार में अब कामचोरी और लापरवाही के लिए कोई जगह नहीं बची है। सम्राट चौधरी के इस बयान के गहरे मायने निकाले जा रहे हैं। यह केवल एक बयान नहीं बल्कि पुलिस सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम है।

गौरतलब है कि सीएम सम्राट के फरमान के बाद से ही राज्य की पुलिस में मुस्तैदी बढ़ती देख जा रही है। बिहार में बढ़ते अपराध पर काबू पाने के लिए सम्राट चौधरी सरकार की ओर से उठाए जा कदम कारगर होते दिखे रहे हैं। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत अपराधियों का एनकाउंटर में सफाया किया जा रहा है। इससे राज्य के दुर्दांत अपराधी भयभीत हो गए हैं। बिहार में इन दिनों एनकाउंटर का दौर जारी है। बता दें कि सुल्तानगंज में पुलिस ने एनकाउंटर में कुख्यात अपराधी रामधनी यादव को मार गिराया। इसके बाद इस इलाके का एक अन्य दुर्दांत अपराधी रंजीत यादव उर्फ कनबुच्चा गायब हो गया है। वह अब जान बचाने के लिए भाग रहा है। ज्ञात हो कि बिहार के सुल्तानगंज में हाल ही में अपराधियों ने नगर परिषद के कार्यपालक अधिकारी कृष्ण भूषण की गोली मार कर हत्या कर दी थी। इसके 24 घंटे के अंदर ही पुलिस ने मुठभेड़ में हत्या के मुख्य आरोपी रामधनी यादव को मार गिराया था। सुल्तानगंज में रामधनी यादव ने कार्यपालक अधिकारी कृष्ण भूषण की उनके ऑफिस में घुसकर हत्या कर दी थी। इसके बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के सख्त निर्देश पर पुलिस ने रामधनी यादव को मुठभेड़ में मार गिराया। भागलपुर के सुल्तानगंज नगर परिषद के ईओ कृष्ण भूषण कुमार हत्याकांड बिहार की सबसे सनसनीखेज वारदातों में से एक है। 28 अप्रैल 2026 की शाम करीब 4 बजे, तीन हथियारबंद अपराधी सुल्तानगंज नगर परिषद कार्यालय में घुस गए। सभापति राजकुमार साह के साथ मीटिंग के दौरान चैंबर में ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। अपराधियों का मुख्य निशाना सभापति थे लेकिन निहत्थे ईओ कृष्ण भूषण कुमार अपनी जान की परवाह किए बिना अपराधियों से भिड़ गए। अपराधियों ने उनके सिर में सटाकर गोली मार दी। पुलिस जांच में सामने आया है कि ये हमला नमामि गंगे घाट और पार्किंग के टेंडरों को लेकर उपजे विवाद या हाल ही में किए गए अतिक्रमण हटाओ अभियान के बदले में किया गया था। वारदात के महज 24 घंटे के भीतर पुलिस ने मुख्य साजिशकर्ता रामधनी यादव को एक एनकाउंटर में ढेर कर दिया। वही सम्राट चौधरी के सत्ता संभालते ही बिहार पुलिस बदमाशों पर कहर बनकर टूट रही है। सीएम ने हाल ही में एक बयान में कहा था कि बेटियों से साथ अपराध करने वालों की फोटो पर माला चढ़ा दी जाएगी। गया में उन्होंने बदमाशों के पिंडदान करने का बयान भी दिया था। बिहार के बोधगया में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर सीएम सम्राट चौधरी एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इस कार्यक्रम में उन्होंने कई बातें कहीं। लेकिन सबसे अहम बात ये कही कि बिहार में अब अपराधियों का पिंड दान शुरू हो गया है। आपको बता दें कि गयाजी को मोक्ष की नगरी कहा जाता है और यहां का पिंड दान ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस दरौन मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि 'गयाजी तो पिंड दान के लिए प्रसिद्ध है। कुछ लोगों का पिंड दान शुरू हो गया है न। बिहार में सुशासन स्थापित करने के लिए ऐसे कई अपराधियों का पिंड दान हमारी सरकार करेगी।' मतलब साफ है सम्राट चौधरी ने अपराधियों को साफ अल्टीमेटम दे दिया है कि या तो क्राइम छोड़ दें या फिर दुनिया। वही उक्त कार्यक्रम के दौरान सीएम सम्राट चौधरी ने भूमाफिया को भी अल्टीमेटम दे दिया है। सम्राट चौधरी ने कहा कि कुछ लोग जमीन कब्जा कर रहे हैं। मठों के जमीनों पर जिन लोगों ने कब्जा किया है, उसे भी छुड़ाया जाएगा। बिहार सुशासन से चलेगा, एकदम कान खोलकर सुन लीजिए।

पुलिस मुठभेड़ में ढेर हुआ अपराधी रामधनी यादव

विदित हो कि मुख्यमंत्री पद की शपथ के बाद से ही बदमाशों का धड़ाधड़ एनकाउंटर शुरू हो गया। रामधनी यादव के बाद सीवान के

मृतक, कृष्ण भूषण
नगर परिषद् कार्यपालक अधिकारी, सुल्तानगंज

रामधनी यादव समेत अपराधियों नें कार्यालय में घूसकर मारी थी गोली

पुलिस मुठभेड़ में मारा गया सोनू यादव

बड़हरिया थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ में बदमाश सोनू कुमार यादव मारा गया। ज्ञात हो कि भाजपा नेता के बहनोई और उनके भांजे पर नगर थाना क्षेत्र के आंदर ढाला के पास गोलीबारी हुई थी, जिसमें दोनों लोगों को गोली लगी थी जिस मामले में बहनोई चंदन सिंह का इलाज चल रहा है, जबकि भांजे हर्ष की मौत हो गई थी। वही मामले में 30 अप्रैल को भी एक आरोपी छोटू यादव पुलिस एनकाउंटर में घायल हो गया। इसके बाद पटना के रामकृष्णा नगर थाना क्षेत्र में 19 अप्रैल 2026 को ज्वेलरी शॉप में हुई लगभग 20 लाख की लूट के मुख्य आरोपी दिलीप कुमार को पुलिस ने 21-22 अप्रैल की देर रात एक मुठभेड़ (हाफ एनकाउंटर) में पैर में गोली मारकर घायल कर दिया। जक्कनपुर इलाके में हुई इस कार्रवाई में आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने गोली चलाई। जबकि 26 अप्रैल को नवादा के रोह थाना क्षेत्र के कोशी गांव के पास पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हो गई। फायरिंग में कुख्यात अपराधी मिंटू यादव के पैर में गोली लगी थी, उस पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित था। बता दें कि सम्राट चौधरी का अपराधियों पर नकेल कसने की कार्यवाई नीतीश सरकार में गृह मंत्री रहते ही शुरू हो गई थी, नतीजा यह है कि बिहार पुलिस की एसटीएफ ने पिछले 4 महीने में 38 इनामी कुख्यातों सहित जिलों की टॉप 10 और 20 की सूची में शामिल 730 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके अलावा इनामी सहित 18 नक्सली भी गिरफ्तार हुए। इनामी अपराधियों में तीन लाख, दो लाख एवं एक लाख रुपये के घोषित एक-एक इनामी को पकड़ा गया। 50 हजार रुपये के 9 इनामी, जबकि 25 हजार रुपये के 26 इनामी अपराधियों को पकड़ा गया है। बिहार में अपराध कर फरार होने वाले अपराधियों पर भी एसटीएफ की कड़ी नजर है। बिहार के कुल 17 अपराधियों को देश के विभिन्न राज्यों से गिरफ्तार कर लाया गया। वहीं, दूसरे राज्यों में अपराध कर बिहार में छिपे 21 अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई। मुख्यमंत्री बनने से पूर्व गृह मंत्री पद पर रहकर पुलिस महकमें पर लगाम कसते हुए हुए सम्राट चौधरी ने राज्य पुलिस को जो हिदायत दी थी, उस पर बिहार पुलिस ने अमल करते हुए कई कार्रवाइयां पूरी की। बता दें कि इसी साल इस साल 6 फरवरी को एसटीएफ और स्थानीय पुलिस ने वैशाली (हाजीपुर) में एक संयुक्त ऑपरेशन के दौरान कुख्यात अपराधी प्रिंस उर्फ अभिजीत को मार गिराया था। वह सोना लूट, हत्या और डकैती के 30 से अधिक मामलों में वांछित था और उस पर दो लाख रुपये का इनाम घोषित कर रखा था। इसके बाद 17 मार्च को कुंदन ठाकुर और प्रियांशु दुबे को मोतिहारी के चकिया में पुलिस मुठभेड़ के दौरान मार गिराया गया। बता दें कि घटना से एक दिन पहले कुंदन ठाकुर ने चकिया के अपर थानाध्यक्ष को फोन कर धमकी दी थी। इस एनकाउंटर में एसटीएफ के एक जवान श्रीराम यादव भी गंभीर रूप से घायल होकर इलाज के दौरान शहीद हो गए थे।

बहरहाल, बिहार में अब अपराधियों की खैर नहीं है। पुलिस लगातार अपराधियों पर नकेल कस रही है तो वहीं अब मुख्यमंत्री सम्राट

रामकृष्णा नगर ज्वेलरी शॉप लूट का आरोपी दिलीप कुमार का पुलिस मुठभेड़ में हुआ हाफ एनकाउंटर

कुख्यात अपराधी प्रिंस उर्फ अभिजीत को पुलिस ने मार गिराया

पुलिस मुठभेड़ में मारा गया मोतिहारी, चकिया का कुख्यात अपराधी कुंदन ठाकुर एवं प्रियांशु दूबे

# बिहार में 16 आईपीएस का तबादला

बिहार सरकार
गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

अधिसूचना

सं0–1/पी01–01/2025 गृ0आ0– 6149 /पटना, दिनांक 10 मई, 2026

भारतीय पुलिस सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–4 में अंकित पद एवं स्थान पर पदस्थापित किया जाता है/अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है :–

| क्र0 सं0 | पदाधिकारी का नाम एवं बैच | वर्तमान पदस्थापन | नव पदस्थापन/ अतिरिक्त प्रभार |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | डॉ0 परेश सक्सेना, भा0पु0से0 (1994) | अपर पुलिस महानिदेशक–सह–अपर आयुक्त, असैनिक सुरक्षा, बिहार, पटना<br>**अतिरिक्त प्रभार–**<br>महानिदेशक–सह–आयुक्त, असैनिक सुरक्षा, बिहार, पटना<br>(नव प्रोन्नत पुलिस महानिदेशक) | महानिदेशक–सह–आयुक्त, असैनिक सुरक्षा, बिहार, पटना<br>(गैर संवर्गीय पद) |
| 2. | श्री निर्मल कुमार आजाद, भा0पु0से0 (1994) | अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवायें एवं संचार, बिहार, पटना<br>(नव प्रोन्नत पुलिस महानिदेशक) | पुलिस महानिदेशक (प्रशिक्षण), बिहार, पटना<br>(संवर्गीय पद) |
| 3. | श्री सुधांशु कुमार, भा0पु0से0 (1996) | अपर पुलिस महानिदेशक, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो एवं आधुनिकीकरण, बिहार, पटना<br>**अतिरिक्त प्रभार–**<br>अपर पुलिस महानिदेशक, यातायात, बिहार, पटना | अपर पुलिस महानिदेशक, विधि–व्यवस्था, बिहार, पटना<br>(संवर्गीय पद)<br>**अतिरिक्त प्रभार–**<br>अपर पुलिस महानिदेशक, यातायात, बिहार, पटना<br>(गैर संवर्गीय पद) |
| 4. | डॉ0 अमित कुमार जैन, भा0पु0से0 (1996) | अपर पुलिस महानिदेशक मद्यनिषेध एवं राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, बिहार, पटना<br>**अतिरिक्त प्रभार–**<br>अपर पुलिस महानिदेशक (कमजोर वर्ग) अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना | अपर पुलिस महानिदेशक, आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना<br>(गैर संवर्गीय पद) |
| 5. | श्री नैयर हसनैन खान, भा0पु0से0 (1996) | अपर पुलिस महानिदेशक, आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना | अपर पुलिस महानिदेशक, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस, बिहार, पटना<br>(संवर्गीय पद) |
| 6. | डॉ0 कमल किशोर सिंह, भा0पु0से0 (1996) | अपर पुलिस महानिदेशक (बजट/अपील/कल्याण), बिहार, पटना<br>**अतिरिक्त प्रभार–**<br>अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवे, बिहार, पटना | अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवे, बिहार, पटना<br>(संवर्गीय पद) |
| 7. | श्री अजिताभ कुमार, भा0पु0से0 (1997) | अपर पुलिस महानिदेशक, प्रोविजनिंग, बिहार, पटना | अपर पुलिस महानिदेशक, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो एवं आधुनिकीकरण, बिहार, पटना<br>(संवर्गीय पद) |
| 8. | श्री संजय सिंह, भा0पु0से0 (1997) | अपर पुलिस महानिदेशक (प्रशिक्षण), बिहार, पटना | अपर पुलिस महानिदेशक (बजट, अपील एवं कल्याण), बिहार, पटना<br>**अतिरिक्त प्रभार–**<br>अपर पुलिस महानिदेशक, सुरक्षा, बिहार, पटना<br>(उत्क्रमित संवर्गीय पद) |
| 9. | श्री अमित लोढ़ा, भा0पु0से0 (1998) | अपर पुलिस महानिदेशक, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो, बिहार, पटना | अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवायें एवं संचार, बिहार, पटना<br>(संवर्गीय पद) |
| 10. | श्री अमृत राज, भा0पु0से0 (1998) | अपर पुलिस महानिदेशक (सुरक्षा), बिहार, पटना | अपर पुलिस महानिदेशक, साईबर अपराध एवं सुरक्षा इकाई, बिहार, पटना<br>(गैर संवर्गीय पद) |
| 11. | श्रीमती कासे सुहिता अनुपम, भा0पु0से0 (1998) | विशेष सचिव, गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार, पटना | अपर पुलिस महानिदेशक (कमजोर वर्ग) अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना<br>(उत्क्रमित संवर्गीय पद) |
| 12. | श्री विकास वैभव, भा0पु0से0 (2003) | परामर्शी, बिहार राज्य योजना पर्षद, पटना | पुलिस महानिरीक्षक, मगध क्षेत्र, गयाजी<br>(संवर्गीय पद) |
| 13. | श्री क्षत्रनील सिंह, भा0पु0से0 (2005) | पुलिस महानिरीक्षक, मगध क्षेत्र, गयाजी | विशेष सचिव, गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार, पटना<br>(गैर संवर्गीय पद) |
| 14. | श्री पी0 कन्नन, भा0पु0से0 (2005), | पुलिस महानिरीक्षक, रेल, बिहार, पटना<br>**अतिरिक्त प्रभार–**<br>पुलिस महानिरीक्षक, आधुनिकीकरण, बिहार, पटना | पुलिस महानिरीक्षक, प्रोविजनिंग, बिहार, पटना<br>**अतिरिक्त प्रभार–**<br>पुलिस महानिरीक्षक, आधुनिकीकरण, बिहार, पटना<br>(संवर्गीय पद) |
| 15. | श्री रंजीत कुमार मिश्रा, भा0पु0से0 (2007) | पुलिस महानिरीक्षक, साईबर अपराध एवं सुरक्षा इकाई, बिहार, पटना | पुलिस महानिरीक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना<br>(संवर्गीय पद)<br>**अतिरिक्त प्रभार–**<br>पुलिस महानिरीक्षक, साईबर अपराध एवं सुरक्षा इकाई, बिहार, पटना |
| 16. | श्री संजय कुमार, भा0पु0से0 (2008) | पुलिस महानिरीक्षक, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस, बिहार, पटना | पुलिस महानिरीक्षक, विशेष शाखा, बिहार, पटना<br>(संवर्गीय पद) |

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(दीपक कुमार)
सरकार के अवर सचिव।

सं0–1/पी01–01/2025 गृ0आ0– 6149 /पटना, दिनांक 10 मई, 2026

प्रतिलिपि :– प्रभारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना (सी0डी0 के साथ) को राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अवर सचिव।

सं0–1/पी01–01/2025 गृ0आ0– 6149 /पटना, दिनांक 10 मई, 2026

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अवर सचिव।

एक ओर बिहार पुनः अपराध का दायरा बढ़ा रहा है तो वही सम्राट अपराधियों के पिंडदान की तैयारी में जुटे हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी लगातार एक्शन में दिख रहे हैं। बिहार की विधि व्यवस्था का कायम रखने के लिए ईमानदार और तेज तर्रार पुलिस अधिकारियों का चयन बहुत जरूरी है। ऐसे में सीएम सम्राट ने बिहार के 16 आईपीएस अफसरों का तबादला किया है। इनमें पहला नाम चर्चित आईपीएस अधिकारी विकास वैभव का भी है, जिन्हें मगध रेंज के आईजी की जिम्मेदारी दी गई है। मगध क्षेत्र (गयाजी) के आईजी क्षत्रनील सिंह का पटना ट्रांसफर कर दिया गया और वह गृह विभाग में विशेष सचिव लगाए गए हैं। उनकी जगह आईपीएस विकास वैभव को मगध का नया आईजी नियुक्त किया गया है, गृह विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी की है। इनके साथ ही नैयर हसनैन खान को बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की जिम्मेदारी दी गई है। वो पहले आर्थिक अपराध इकाई में थे। वहीं राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो एवं आधुनिकीकरण के अपर पुलिस महानिदेशक सुधांशु कुमार को अब एडीजी विधि–व्यवस्था देखने का जिम्मा सौंपा गया है। आईपीएस अधिकारी एडीजी परेश सक्सेना को असैनिक सुरक्षा विभाग में ही पुलिस महानिदेशक बनाया गया है। वहीं निर्मल कुमार आजाद को पुलिस महानिदेशक की जिम्मेदारी दी गई है, साथ ही डॉ. अमित कुमार जैन को आर्थिक अपराध इकाई का एडीजी बनाया गया है। आईपीएस डॉ. कमल किशोर सिंह को एडीजी रेलवे नियुक्त किया गया है, पहले उनके पास इसका अतिरिक्त प्रभार था। अजिताभ कुमार को एडीजी एससीआरबी एवं आधुनिकीकरण, संजय सिंह को एडीजी बजट अपील एवं कल्याण के साथ एडीजी सुरक्षा पद पर तैनात किया गया है। आईपीएस अमित लोढ़ा को एडीजी तकनीकी सेवाएं एवं संचार नियुक्त किया गया है। वहीं, अमृत राज को एडीजी साइबर अपराध एवं सुरक्षा इकाई लगाया गया है। गृह विभाग की विशेष सचिव के.एस. अनुपम का ट्रांसफर कर एडीजी सीआईडी कमजोर वर्ग बना दिया गया है। पी कन्नन को आईजी प्रोविजनिंग, रंजीत कुमार मिश्रा को आईजी सीआईडी और संजय कुमार को आईजी विशेष शाखा की नई जिम्मेदारी दी गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एनडीए सरकार में मंत्रियों के शपथ और विभागों के बंटवारे के बाद स्पष्ट रूप से अपनी प्राथमिकताएं बताई थी। उन्होंने मंत्रियों से भी प्रशासनिक सुध ार और जवाबदेही पर जोर देने के लिए कहा था। मंत्रियों ने भी कहा था कि वो अपने–अपने विभाग में जवाबदेही को अच्छी तरह निभाएंगे और इसमें किसी भी तरह की ढील बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को भ्रष्टाचार के मामले में 'जीरो टॉलरेंस' की नीति अपनाने, परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और 'सात निश्चय' को तेजी से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में विपक्ष बढ़ते अपराध, बलात्कार के मामलों और हिंसा को मुद्दा बनाता रहा है। ऐसे में सीएम सम्राट को नौकरशाही में विश्वास और कार्यकुशलता बनाए रखना (भले ही गुटबाजी और भ्रष्टाचार की समस्याएं मौजूद हों) बेहद जरूरी है। इस मामले में सम्राट चौधरी की तुलना पड़ोसी राज्य यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की जाएगी। अपराध पर सख्त कार्रवाई करना और साथ ही सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखना, सीएम के 'विकसित बिहार' के एजेंडे के लिए बहुत जरूरी है।

चौधरी ने भी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर साफ–साफ कह दिया है कि पुलिस को चुनौती देने वालों को 48 घंटे के अंदर जवाब दिया जाएगा। सीएम सम्राट चौधरी ने अपराध मुक्त बिहार का जिक्र करते हुए कहा है कि अब कोई भी अपराधी बच नहीं पाएगा। यहां बता दें कि मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद सम्राट चौधरी लगातार अपराधियों को सख्त लहजे में चेतावनी देते आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने पटना में मंदिरी नाला पर बने सड़क का उद्घाटन किया और फिर अपने संबोधन में अपराधियों को कड़े लहजे में चेताया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि हमने पुलिस के हाथ खोल दिए हैं। पुलिस को कोई चुनौती देता है तो उसे 48 घंटे में जवाब मिलेगा। कोई अपराधी बच नहीं सकता है। उद्योग को लाना है तो बिहार में सुशासन को और बेहतर ढंग से स्थापित करना है। हमें अपराध मुक्त बिहार बनाना है, इसके लिए हम कुछ भी करेंगे। इससे समझौता नहीं करेंगे। सीएम ने कहा कि कौन अपराधी किस जाति का है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बता दें कि एक तरफ जहां

## सारण में सामुहिक दुष्कर्म के बाद फॉरेंसिक जांच में जुटी पुलिस

विपक्ष बिहार में अपराध के मुद्दे पर रह रहकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए सरकार लगातार यह दावा कर रही है कि बिहार में अपराधियों पर जोरदार प्रहार जारी है। सम्राट सरकार के पहले 18 दिन में ही मगध से अंग और सारण तक पुलिस ने पांच एनकाउंटर किए थे। इसमें तीन हाफ एनकाउंटर शामिल थे तो वहीं दो मुठभेड़ में पुलिस ने अपराधियों को मार गिराया था।

बिडम्बना है कि बिहार की विधि व्यवस्था बनाने की दिशा में सीएम सम्राट का अपराधियों का 'पिंडदान करवाने' जैसे बयानों का असर पूरी तरह नहीं दिख पा रही है। प्रदेश के अपराधियों में मौत का खौफ नहीं पनप पा रहा। पांच एनकाउंटर के बाद भी अपराधी जघन्य अपराध करने से कतरा नहीं रहे। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हाल ही में पुलिस-प्रशासन को सख्त निर्देश दिए थे कि जब तक बेटी अपने घर नहीं पहुंच जाती, तब तक पुलिस चौन से नहीं बैठेगी। इसका मतलब साफ था कि बिहार की बेटियों को पूरी सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। लेकिन सारण जिले में सीएम के निर्देश को पलीता लगाया जा रहा है। जहां सीएम के सख्त निर्देश के बाद भी पुलिस प्रशासन बेटियों की सुरक्षा करने में असफल हो रही है, वहीं अपराधियों के मन से कानून का डर भी खत्म होता दिख रहा है। इसका उदाहरण है सारण जिले में 17 साल की छात्रा से गैंगरेप। ज्ञात हो कि एकमा थाना क्षेत्र में लाइब्रेरी से लौटते समय छात्रा से गैंगरेप का मामला सामने आया है। सारण जिले के एकमा थाना क्षेत्र में लाइब्रेरी में पढ़ने वाली 17 वर्षीय छात्रा के साथ तीन युवकों ने कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। दिनदहाड़े हुई इस घटना ने इलाके में

सनसनी फैला दी है। पुलिस ने मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार पीड़िता दाउदपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली है और हंसराजपुर स्थित 'पाठशाला लाइब्रेरी' में पढ़ाई करने आती थी। बताया जा रहा है कि छात्रा अपने एक परिचित युवक के साथ मोटरसाइकिल से लौट रही थी। इसी दौरान गंजरपर पेट्रोल पंप के समीप बाइक सवार दो युवकों ने उनका रास्ता रोक लिया। पीड़िता के अनुसार दोनों आरोपियों ने चाकू दिखाकर डराया और जबरन उसे तथा उसके साथी को भरोपुर कब्रगाह के पास झाड़ियों की ओर ले गए। आरोप है कि इसके बाद दोनों युवकों ने फोन कर अपने एक और साथी को मौके पर बुलाया। पीड़िता ने पुलिस को दिए बयान में आरोप लगाया है कि तीनों आरोपियों ने उसके साथ बारी-बारी से दुष्कर्म किया। घटना के दौरान जब छात्रा ने हिम्मत दिखाते हुए शोर मचाना शुरू किया तो आरोपी उसे जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। घटना के बाद पीड़िता सदमे में है, वहीं इलाके में भी भारी आक्रोश देखा जा रहा है। दूसरी तरफ बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के कोटवा स्थित एकेआरआर कॉलेज परीक्षा केंद्र के बाहर बेखौफ अपराधियों ने एक परीक्षार्थी की चाकू घोंपकर निर्मम हत्या कर दी। घटना के बाद पहुंची पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। इस घटना के बाद कॉलेज में सनसनी फैल गई। बताया जाता है कि छात्र स्नातक की परीक्षा देकर कॉलेज से बाहर निकला था कि अपराधियों ने छात्र पर चाकू से ताबड़तोड़ कई वार किए, जिससे अत्यधिक रक्तस्राव के कारण उसकी स्थिति बिगड़ गई। घटना को अंजाम देकर अपराधी फरार हो गए। एक घटना राजधानी पटना की है जहां एक युवक को सिर्फ इसलिए मौत के घाट उतार दिया गया क्योंकि उसने अपनी भतीजी के साथ हो रही छेड़खानी का विरोध किया था। अपराधी इतने बेखौफ थे कि उन्होंने घर में घुसकर कर हमला कर दिया। इस हिंसक झड़प में युवक की जान चली गई, जबकि बीच-बचाव करने आए उसकी पत्नी और मासूम बच्चे भी गंभीर रूप से घायल हैं। वही जमुई जिले में अब तक दो महिला एवं दो पुरुष की हत्या हो चुकी है। खैरा के एक गांव में 15 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना ने लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए हैं। लोगों में घटना को लेकर उबाल है और दो पक्षों के बीच स्थिति तनावपूर्ण थी, लेकिन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर तीन आरोपितों को गिरफ्तार कर स्थिति को संभाल लिया। इसी दिन सुबह में गिद्धौर के केवाल मुसहरी में लक्ष्मीपुर थाना क्षेत्र के बेला गांव के सोनू का सिर कटा शव पुलिस ने बरामद किया। मामले में पुलिस ने एक आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। सिमुलतला में एक विवाहिता की हत्या कर दी गई। इन घटनाओं को हुए

सीएम आवास से कुछ ही दूरी पर मिली नाबालिग युवति की लाश

ज्यादा समय नहीं बीता था कि सदर थाना क्षेत्र के इस्लामनगर मुहल्ला स्थित कब्रिस्तान के समीप से पुलिस ने एक 35 वर्षीय अज्ञात महिला का शव बरामद किया। महिला के चेहरे पर चोट के निशान हैं। जिससे उसकी हत्या की आशंका जताई जा रही है। इससे पहले झाझा के ताराकुरा जंगल से पुलिस ने आटो चालक का पेड़ से लटका हुआ शव बरामद किया था। वही झाझा में अपराधियों द्वारा सात लाख की रंगदारी मांगे जाने के बाद डीलर का परिवार दहशत में है। वही सबसे शर्मनाक घटना नवादा जिले की है जहां धमौल थाना क्षेत्र में चौकीदार जितेंद्र पासवान पर थाने के सामने चाकू से हमला किया गया। गंभीर हालत में उन्हें पीएमसीएच पटना रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। ऐसी बहुत सी अपराधिक घटना हर रोज घटित हो रही है पर सवाल है कि इसे रोका कैसे जाये?

विदित हो कि इस दिशा में सीएम सम्राट हर वो प्रयास कर रहे हैं। बता दें कि बिहार में स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं की सुरक्षा को लेकर नई सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली कैबिनेट ने 'पुलिस दीदी' यानी अभया ब्रिगेड को और मजबूत करने का फैसला लिया है। नई कैबिनेट बैठक में तय किया गया कि महिला पुलिसकर्मियों को अब स्कूटी और बाइक दी जाएगी। इसका मकसद यह है कि वे स्कूल, कॉलेज और कोचिंग के आसपास आसानी से गश्त कर सकें और छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें। सरकार ने इस योजना के लिए कुल 66.75 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। इसके तहत 1500 महिला पुलिसकर्मियों को स्कूटी दी जाएगी, जबकि 3200 पुलिसकर्मियों को मोटरसाइकिल दी जाएगी। इस फैसले से महिला पुलिस की पहुंच और तेजी दोनों बढ़ेगी, जिससे वे तुरंत किसी भी घटना पर कार्रवाई कर सकेंगी। सरकार का मानना है कि स्कूटी और बाइक मिलने के बाद पुलिस दीदी ज्यादा तेजी से इलाके में पहुंच सकेंगी। इससे मनचलों और असामाजिक तत्वों पर तुरंत कार्रवाई की जा सकेगी। सरकार ने स्कूटी की कीमत करीब 1,25,000 रुपये और मोटरसाइकिल की कीमत लगभग 1,50,000 रुपये तय की है। इसी आधार पर पूरे प्रोजेक्ट का बजट तैयार किया गया है। इस फैसले के बाद सरकार का दावा है कि स्कूल और कॉलेज जाने वाली छात्राओं को अब और सुरक्षित माहौल मिलेगा। यह कदम महिला सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है।

बहरहाल, सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री पद पर शपथ लेने के बाद से प्रत्येक दिन अपराध के आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं, जो चिंता का विषय है। हालांकि सम्राट की पुलिस एक तरफ अपराधियों के एनकाउंटर करने में जुटी है तो दूसरी तरफ अपराधियों का मनोबल भी कम होता नहीं दिख रहा। ऐसे में सीएम सम्राट उन अपराधियों का पिंडदान कैसे करा पायेंगे! सीएम सम्राट के आदेश को मानते हुए बिहार पुलिस तमंचे चला सकते हैं का प्रमाण देने लगे हैं किंतु अपराधियों में भय बना पाना इनके लिए मुश्किल ही दिख रहा है। खैर! अपराधमुक्त बिहार के लिए सीएम सम्राट का प्रयोग किस-किस प्रकार से होगा, यह देखना होगा किंतु बिहार की वर्तमान स्थिति को देखते हुए इतना ही कहा जा सकता है, 'अपराध नहीं हो रहे कम, सम्राट दिखायेंगे अपना दम?'●

# बिहार में रोजगार प्रधान उद्योग क्यों नहीं?

● **कुमार अनिकेत**

मैं वो बिहार हूँ जिसे 'शांति का निवास' कहा गया है। सर्वकालिक महानतम साम्राज्य मगध राजवंश मेरा अतीत रहा, कई धारोहर को अपने आगोश में समेटे हुए मैंने एक कीर्तिमान को स्थापित किया। दुनिया को शून्य की परिभाषा से लेकर आधुनिक शल्य चिकित्सा का आधार बना। मिथिला की एक शानदार कला 'मधुबनी पेंटिंग' को स्थानीय घरों की दीवारों और फर्श से निकालकर देश ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया। बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत भारत की आध्यात्मिक, कलात्मक और ऐतिहासिक जड़ों की गहरी जानकारी प्रदान करती है। मगर आज वही बिहार अपनी पहचान खो चूका है। कभी जिसे समृद्ध राज्य का दर्जा प्राप्त था, उसे आज एक बेबस और लाचार राज्य के तौर पर सम्बोधित किया जाता है। गरीबी एवं बेरोजगारी इस राज्य की कभी न खत्म होने वाली जटिल समस्या बन चुकी है। कभी फक्र से इतराता बिहार आज बेबसी का चोला ओढ़े गुम खड़ा है आखिर क्यों?

'हम एक स्थलरुद्ध राज्य हैं' ये वाक्य मुख्यमंत्री अपनी विफलता को छुपाने के लिए भले ही प्रयोग करे मगर सच्चाई कुछ और ही है ऐसे कई स्थलरुद्ध क्षेत्र और देश हैं जो बिहार से कहीं अधिक समृद्ध हैं। किसी राज्य के विकास में उद्योग एक बहुत एहम भूमिका निभाता है,मगर कोई भी औद्योगीकरण राज्य की स्तिथि और विभिन्न मानकों के विश्लेषण के बाद ही संभव हो सकता है। अगर बिहार की बात की जाए तो यह कृषि प्रधान राज्य है, यहाँ कृषि आधारित उद्योग एक बहुत बड़ा विकल्प बन सकता है जो कि अकुशल श्रमिकों के निर्यात को रोक सकता

है।

ऐसा नहीं है कि ये संभावनाएं सरकार एवं उनके अधिकारियो से छुपी हुई है मगर इस पर कभी भी ठोस निर्णय नहीं लिया गया। इस राज्य को समृद्ध बनाने के लिए कभी भी सार्थक प्रयास किये ही नहीं गए। मुख्यमंत्री नितीश कुमार को 'कुर्सी कुमार' की उपाधि भी बहुत कुछ दबे शब्दों में बताना चाहती है। आज सरकार को व्यापारियों कि असल स्थिति से अवगत कराने का समय है और उनकी समस्याओ को निष्पक्ष रूप से सुनने एवं सुलझाने की जरुरत है।

☞ **सुरेश चिप्स की कहानी :-** बिहार की बदहाली एवं औद्योगीकरण के प्रति उदासीनता का साक्षात् उदहारण है 'सुरेश चिप्स' कि यह कहानी। अपने भाई एवं कुछ दोस्तों की मदद से चन्दन राज ने बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में सेमीकंडक्टर की कंपनी को खोलना चाहा मगर इस चाहत ने उनका जो शोषण किया वो बिहार के प्रशासनिक विफलता को उजागर करता है। जिसका उल्लेख कुछ इस प्रकार है :- (1) तीन फेज की बिजली के लिए घूस कि राशि १ लाख से शुरू हुई और 75 हजार तक आकर रुक गई (2) कंपनी का पंजीकरण कराना भी बिहार में जंग लड़ने से कम न था हर एक मेज पर पैसे लिए जाते और फिर एक तारीख तय कर दी जाती और बेवजह फाइल को धीरे-धीरे आगे बढ़ाया जाता (3) उद्योग विभाग सिर्फ बड़े बड़े बैनर कि वाह-वाही तले ही खुश था जिसे जमीनी हकीकत से कोई वास्ता न था आज भी आप इस विभाग में जा कर देख लीजिए आपके उद्योग खोलने का विचार, पुनर्विचार में तब्दील न हो जाये तो फिर कहियेगा (4) बैंक लोन के लिए तो शायद आपको

पुनर्जन्म लेना पर सकता है मगर लोन मिल ही जायेगा इसकी कोई गारंटी नहीं, चन्दन राज व्यवसाय लोन लेना चाहते थे जो कि बिलकुल उचित भी था मगर बैंक के भ्रष्टाचार एवं लालफिताशाही ने उन्हें इसे कृषि ऋण कि तरफ धकेल दिया। अब आप खुद अपने विवेक से फैसला ले कि क्या ऐसी व्यवस्था में कोई भी बड़ा व्यापारी यहाँ उद्योग लगाने कि पहल करेगा?

चन्दन राज को प्रशासन से ही नहीं बल्कि समाज से भी शोषण का सामना करना पड़ा। दुर्गा पूजा जैसे पवित्र त्यौहार में 25 हजार चंदे के रूप में माँगा जाता और सरस्वती पूजा में 15 हजार क्यूंकि आप एक कंपनी चला रहे है, दुर्भाग्य तो ये था कि पुलिस भी इन मामलो में आँख बंद कर लेती, क्यूंकि इन पैसो में उनकी भी हिस्सेदारी बनती है। अगर ऐसी वसूली को हम 'रंगदारी कर' कहे तो ये गलत नहीं।

ऑफिस में कर्मचारी चप्पल पहन कर आते क्यूंकि सड़क पर पानी जमा था और उनके पैंट ऊपर तक मुड़े होते, अगर कोई भी बहुराष्ट्रीय कंपनी अगर उन्हें इन हालत में काम करते देख ले तो बिजनेस डील करना तो दूर ऐसी कंपनी को तत्काल बंद करने कि सलाह दे दे। चन्दन ने अपनी पीड़ा को जब सोशल मीडिया पर व्यक्त किया तो मानो पूरा बिहार प्रशासन उनका दुश्मन बन बैठा। जबकि नैतिकता यह कहती है कि बिहार के इन विभागों जो समीक्षा करने की जरुरत थी ताकि यहाँ औद्योगीकरण को बढ़ावा दिया जा सके। अगर सकारात्मक कदम उठाकर उचित निर्णय लिया जाता तो तस्वीर कुछ और ही होती। जब उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री मिहिर कुमार सिंह से इस बात पर एक पत्रकार द्वारा स्पष्टीकरण माँगा गया तोह उनका जवाब तो उनका जवाब खानापूर्ति जैसा था और ऐसा प्रतीत हुआ की उनकी रूचि ऐसे मामलो में ना का बराबर है। तो सवाल ये उठता है फिर ये ढोंग क्यों ? जब आपलोगो ने ये फैसला कर लिया है कि बिहार सिर्फ श्रमिक की आपूर्ति का प्रमुख केंद्र बनकर रहेगा तो फिर बड़े-बड़े वादों का जुमला क्यों ?

कहानी यही खत्म नहीं होती है पहले भी बिहार के हितो को ध्यान में रखकर सत्यजीत सिंह ने भागलपुर में 'मखना उद्योग, जो कि मेगा फूड प्रोजेक्ट का हिस्सा था, खोलना चाहा मगर उनके खवाबो का महल भ्रष्ट सरकरी तंत्र ने चकनाचूर कर दिया। सत्यजीत सिंह ने बिहार में मौजूद समस्याओं का हवाला देता हुए अपने सपने को अलविदा कहना ही उचित समझा और ये गलत भी नहीं है कोई भी कारोबारी एक अच्छे और संतुलित वातावरण में कार्य करना चाहता है न कि अनिश्चिताओं के परिवेश में। इसके अलावा, ऋषिकेश शर्मा भागलपुर में एक छोटा हवाई जहाज लैंडिंग बेस खोलना चाहते थे, मगर वो भी बिहार के विभागों कि क्रूढ़ प्रक्रिया के आगे धराशाही हो गए। इन सब चीजों में सबसे एहम बात यह है कि किसी विभाग ने सकारात्मकता नहीं दिखाई अगर बिहार की समृद्धि का उद्देश्य पूरा करना होता तो समस्याओं का समाधान खुद विभागों द्वारा ही कर दिया जाता या और जरुरी सुझाव जो मार्गदर्शक का काम करते उसे इनलोगो के साथ साझा किया जाता। यह दिखता है कि बिहार में कार्यप्रणाली किस कदर बेसरोकार और बेतुका है जिसे सिर्फ उन्ही कार्यो को करना है जिससे बाबुओ की जेबे गरम होती हो।

☞ **उद्योग विभाग, बिहार :-** अब आप इस वेबसाइट पेज पर नजर डालिये ये बिहार सरकार के उद्योग विभाग का है जिसमे 1500+ स्टार्टअप के फंडिंग का जिक्र किया गया है, मगर यहाँ उन सभी स्टार्टअप की कोई व्रिस्तित जानकारी नहीं है। बिहार में जब बैंको से स्टार्टअप फंडिंग को लेकर RTI के माध्यम से जानकारी मांगी गई तो बैंक अधिकारी बगले झाकने लगे और जवाब भी जो आया उसने साफ साफ स्पष्ट कर दिया की बैंक ऐसी कोई फंडिंग का इक्छुक नहीं। तो सवाल अब उठता है कि इन 1500+

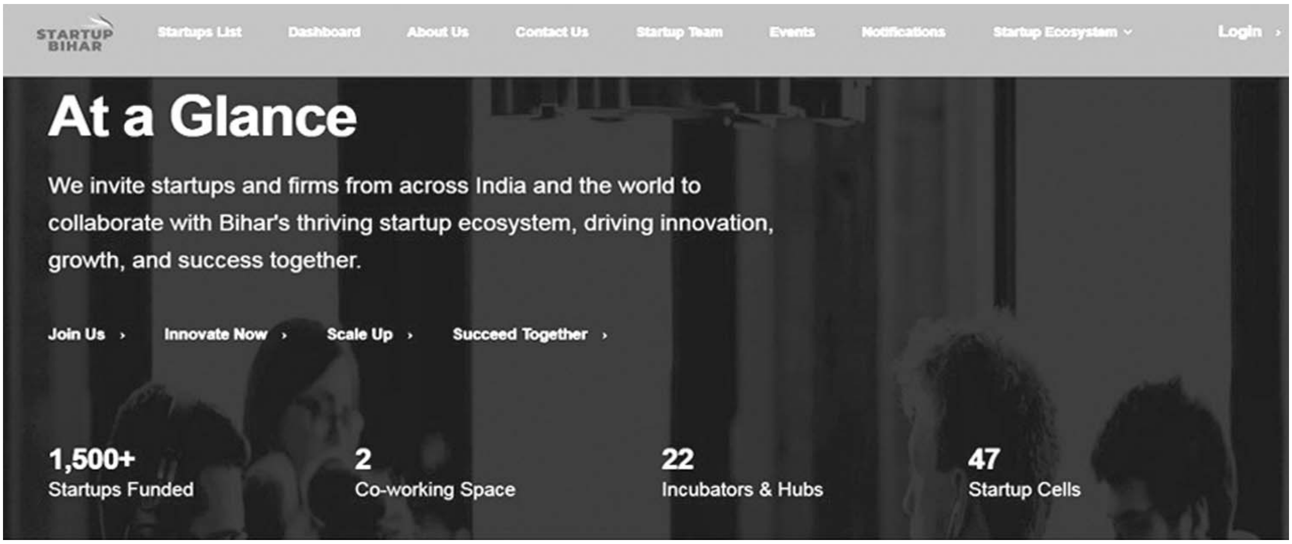


स्टार्टअप को फंडिंग किसने की , बिहार सरकार ने ? अगर की है तो उन्हें साझा करने से कतरा क्यों रही है। जिन लोगो को भी स्टार्टअप फंडिंग मिली है वे उन सभी लोगो के लिए मार्गदर्शक का काम करेंगे जो बिहार में स्टार्टअप खोलने के इक्छुक है।

नीचे दिया गया संलेख जो कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने दिया है वो बिहार में उद्योग की दयनीय स्तिथि बतलाता और ये तोह सिर्फ एक बैंक है अमूमन सारे बैंको की यही हालत है कुछ तो ऐसे भी है जिन्होंने सवाल से बचने के लिए इस सवाल को 'गोपनीय और सुरक्षा संबंधी' दायरे में ला कर खड़ा कर दिया।अब इन सारे चीजो का विश्लेषण एक ही बात की ओर हमें ले जाता है कि कहनी और कथनी में यहाँ अकल्पनीय फर्क है, जिसे छुपाने के लिए तरह-तरह की कहानियो को समय-समय पर गढ़ा जाता है। ऐसे तो अनंतकाल तक भी यहाँ कोई औद्योगीकरण नहीं होगा क्यूंकि प्रतिबद्धता यह किसी ओर नहीं झलकती है।

☞ **व्यवसाय लोन और बैंको का हाल :-** बैंक की सहायता से चीजें आसान और सुचारू हो सकती हैं, मगर यहाँ कहानी कुछ और ही है रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार बैंको में चरम पर है जो कि DSA के माध्यम से कुशलतापूर्वक चलाया जाता है। यहाँ सभी बैंको पर कटाक्ष करना सही नहीं होगा क्योंकि बिहार के लोग भी डॉक्यूमेंट्स के मामले में सुस्त और लापरवाह है और जो छोटा उद्योग या स्टार्टअप खोलना चाहते है, उनमे दस्तावेजों का व्यवस्थित संकलन करना आता ही नहीं है। मगर इन सब बातो के बावजूद बैंक को अगर कटघरे में खड़ा किया जाये तो कही से गलत नहीं है।

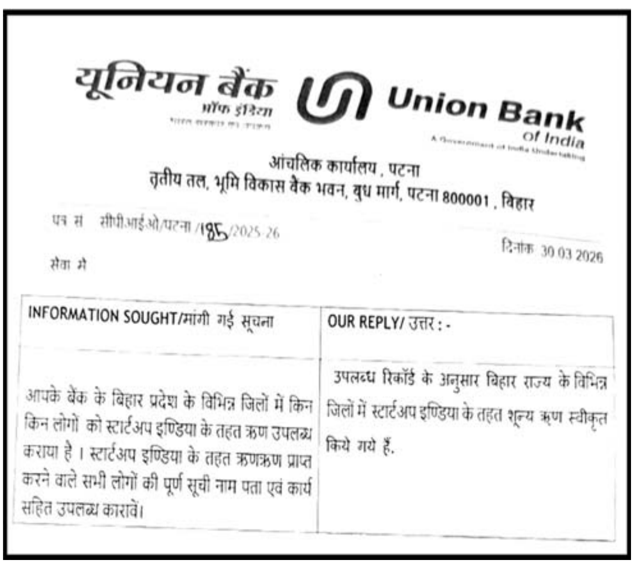
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
Union Bank of India

आंचलिक कार्यालय , पटना
तृतीय तल, भूमि विकास बैंक भवन, बुध मार्ग, पटना 800001 , बिहार

पत्र सं सीपीआईओ/पटना /185/2025-26

दिनांक 30.03.2026

सेवा मे

| INFORMATION SOUGHT/मांगी गई सूचना | OUR REPLY/ उत्तर : - |
|---|---|
| आपके बेंक के बिहार प्रदेश के विभिन्न जिलों में किन किन लोगों को स्टार्टअप इण्डिया के तहत ऋण उपलब्ध कराया है । स्टार्टअप इण्डिया के तहत ऋणऋण प्राप्त करने वाले सभी लोगों की पूर्ण सूची नाम पता एवं कार्य सहित उपलब्ध करावें। | उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार बिहार राज्य के विभिन्न जिलों में स्टार्टअप इण्डिया के तहत शून्य ऋण स्वीकृत किये गये हैं. |

ग्राहकों की सहायता के लिए हर बैंक ने "MAY I HELP YOU" का एक विशेष काउंटर खोल कर रखा है, मगर ये काउंटर एक किराने की दूकान के अलावा कुछ भी नहीं, यहाँ पहले आपकी हैसियत को तोला जाता है और आप बैंक को क्या दे सकते है इसका आकलन किया जाता है। अगर इन्हे पता चल गया की आप स्टार्टअप लोन के लिए आये है फिर तो आपको ये पूरे बैंक की परिक्रमा करवाएंगे और सबसे पसंदीदा सवाल इनका 'आप के पास FD या कोलैटरल है?' आप पर विश्वास कैसे करे? यह हाल महज १० लाख के छोटे ऋण के लिए होता है। कभी भी छोटे उद्यमियों के लिए बैंक तत्परता नहीं दिखाता, सुझाव तो दूर उनके दस्तावेजों को देखकर उन्हें उचित सलाह देना बैंक के लिए तिरस्कार स्वरुप है। सवालो की बौछार से जहाँ स्टार्टअप ऋण के ग्राहक का स्वागत हो वहाँ उस ग्राहक के अंदर तुक्छता का भाव आना सामान्य है। हर बैंक में जब एक सा व्यवहार मिले तो कोई भी स्वाभिमानी इंसान अपनी प्रयत्नशीलता खो देता है।

बायो फ्यूल पालिसी 2023 ने भी कोई कमाल नहीं दिखाया अभी तक एक भी बायो फ्यूल प्लांट बिहार में नहीं लगा और न ही इसकी समीक्षा की गई। इसका मुख्य कारण बिहार में जमीन की समस्या है ,बिहार में जमीने एक तो बहुत महंगी है और यहाँ विवादित जमीनो की भरमार है। यहाँ भू -माफियो का राज है और इनके द्वारा ही जमीन की दरों को असामन्य तरीके से बढ़ाने का खेल चलाया जा रहा है। सबसे दुखद बात तो यह है कि ये सब सरकार के संज्ञान में होते हुए भी धरल्ले से चल रहा है और सरकार सुशासन का ढिंढोरा पीटने में लगी है।

सबसे निन्दनीय बात ये है की दिल्ली तक इस बात कि गूंज बनी हुई है कि बिहार के नेताओ का बिहार के प्रति कोई विजन है ही नहीं और इसका जिक्र खुल कर मोदी सरकार में कैबिनेट स्तर के मंत्री द्वारा किया गया। जिस तरह से बिहार गर्क में जा रहा है ये बात बिलकुल सत्य प्रतीत होती नजर आ रही है। बेरोजगारी और गरीबी यहाँ तीव्र गति से बढ़ती जा रही है और जनता जात पात के उलझनों में ही फसी है।●

● संजय सिन्हा

महाभारत समय के राज्य इन्द्रप्रस्थ यानि दिल्ली में भव्य जनजाति सांस्कृतिक समागम का आयोजन अगामी 24 मई, 2026 रविवार को इन्द्रप्रस्थ के लालकिला में होना निश्चित है। जिसमें कमसे कम डेढ़ लाख आदिवासी समाज के लोग पहुँच रहे हैं। ये संख्या अगर 3 लाख या उससे अधिक भी हो जाये तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। देश के कोने कोने से आदिवासी कुटुंब अपने चरण इन्द्रप्रस्थ के धरती पर रखेगें। आने वाले हमारे भगवान् बिरसा मुंडा जी की 150 वीं जयंती के अवसर पर गरीब अमीर बहुत पढ़े लिखे या अनपढ़ कुछ आदिवासी हस्तियां भी शामिल होगीं ऐसा उम्मीद किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात आदिवासी समाज के आने वाले कुटुबं में आधे लोगो पहली बार इन्द्रप्रस्थ यानि देश की राजधानी दिल्ली आयेगें उसमें भी आधे शायद पहली बार रेलगाड़ियों (ट्रेंन) पर चढ़ेगें। दिल्ली में विश्व हिन्दू परिषद्, सेवा भारती, वनवासी कल्याण, बीजेपी एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसके जोर शोर से तैयारी कर रहीं हैं। सबसे बड़ी बात कि दिल्ली की जनता अपने आदिवासी भाई बहन माताओं एवं वरिष्ठों की स्वागत के लिए हाथों में फुल- मालाएँ, पटका, तिलक से अभिनंदन के लिए तैयार कर लिया है। इस जनजाति सांस्कृतिक समागम के मुख्य अतिथि गृहमंत्री अमित शाह होगें जबकि जनजाति सुरक्षा

## देश के इतिहास में आदिवासी समाज का होगा सबसे बड़ा जमावड़ा

**विश्व हिन्दू परिषद् के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता श्रीमान आलोक कुमार से पत्रिका के दिल्ली प्रभारी पत्रकार संजय कुमार सिन्हा से हुए वार्तालाप के प्रमुख अंश :-**

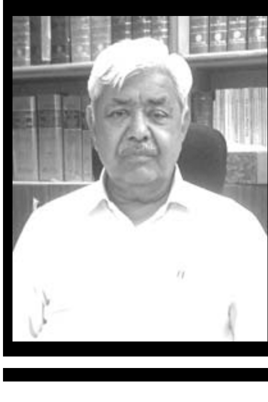

**❖ इस आदिवासी समागम में पूरे देश के लोग आएंगे?**

हमने तो जनजातीय समाज को ही बुलाया है, ट्राइबल्स को ही बुलाया है। और मैं विश्वास करता हूँ कि कई लाख लोग आयेगे। ये देश के इतिहास में आदिवासी समाज का सबसे बड़ा जमावड़ा होगा और इसमें अन्य बातों के अलावा ये बात दोबारा ध्यान में लाई जाएगी कि ट्राइबल्स में से जो लोग ईसाई धर्म ग्रहण कर लेते हैं, वो अपने ट्राइब की परंपरा से, देवताओं से, पूजा-पद्धतियों से अलग हो जाते हैं। क्योंकि तब वो क्राइस्ट को पूजते हैं और वो गिरिजाघर में पूजा करते हैं। उनकी धार्मिक पुस्तक भी अलग हो जाती है। इसलिए जैसा अनुसूचित समाज के लिए है । अनुसूचित समाज और अनुसूचित जनजाति, दोनों में एक अंतर है। अनुसूचित जाति के बारे में ये लिखा हुआ है उस ऑर्डर में कि जो हिंदू नहीं है ख़ हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध नहीं है ख़ वो अनुसूचित जाति का नहीं होगा। और जनजाति में ये लिखा नहीं है। लिखा जाना चाहिए। ये मांग करेंगे और ये पूरी व्यवस्था विश्वव्यापी तैयारी करा देगी।

**❖ विश्व हिन्दू परिषद् ये आयोजन करवा रही है?**

नहीं जी, हमारे जिम्मे भोजन की व्यवस्था है।

# जनजाति समाज को एक मंच पर लाने का हैं हमारा प्रयास

## अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के प्रमुख श्रीमान अतुल योग से पत्रिका के दिल्ली प्रभारी पत्रकार संजय कुमार सिन्हा से हुए वार्तालाप के प्रमुख अंश :-

❖ **माना जा रहा है कि आदीवासी समाज खासकर झारखंड में जो एक सामान प्रथा चल पड़ी है कि मुस्लिम पुरुष आदीवासी महिला से शादी कर उसके जमीन हड़प रहे हैं, जिसे दमाद प्रथा भी कहा जा रहा है, तो इस संदर्भ में वनवासी कल्याण आश्रम के क्या राय हो सकता है?**

हमारा कहना है कि जनजाति समाज जो है, जो अपनी रूढ़ि परंपरा, आस्था को मानता है, तो उनको अनुसूचित जनजाति माना जाएगा, मानना चाहिए। ऐसा हमारा कहना है। और जो अन्य धर्मों में जाते हैं, तो स्वाभाविक रूप से वो अपनी उस आस्था-परंपरा पक्का मानते नहीं हैं, मान नहीं सकते। लेकिन जो बोलते हैं, वो अपने कानून हैं। कहने से वो वंचित रह जाते हैं इस परंपरा को मानने से। क्या होता है कि जो आस्था और संस्कृति, धर्म और संस्कृति का जो कहिए, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ऐसा हम कहते हैं। क्योंकि संस्कृति एक प्रकार से धर्म की आस्था का प्रकटीकरण होता है। लेकिन आज बहुत ज्यादा प्रचलन है कि संस्कृति और धर्म को अलग रखा जा रहा है। केवल वस्त्र, कैसे कपड़े पहनना, कौन भाषा में बोलना, कौन-सा जाति में जन्म लेना, वो तो ठीक अपनी जगह पर है। लेकिन आस्था-परंपरा को नहीं माना जाता है। पूजा के नाम पर खाना-पीना तो होता है लेकिन पूजा नहीं करते हैं, व्रत नहीं रखते हैं। यह जो परंपराएं, जो कुछ रूढ़ियां हैं, उनको मानते नहीं हैं। इस समय एक प्रकार का ये छल है।

❖ **अगर माना जाए तो घूम-फिरा के आप लोग सरकार में ही हैं, तो फिर धर्मपरिवर्तन अनुसूचित जाति के लिए तो कानून में व्यवस्था नहीं है परंतु जनजातियों के लिए ऐसा संभव है, क्यों? ऐसा होना चाहिए कि कोई धर्म बदलते ही पिछला सभी सुविधाएं स्वतः बंद हो जाये।**

ऐसे संगठन के नाते बोलिए तो ये हमारी डिमांड रहेगी कि जो अपनी आस्था-परंपरा को मानते हैं उनको दर्जा मिलना चाहिए जनजाति समाज का। ये हमारी मांग है। लेकिन अभी जो 24 तारीख को कार्यक्रम हो रहा है, ये भगवान बिरसा मुंडा के 150वें जन्म वर्ष के उपलक्ष्य में जनजातीय गौरव वर्ष है। तो उस उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम हो रहा है। तो भगवान बिरसा मुंडा अपने आप में धर्म, संस्कृति, परंपरा से जुड़े हुए, उत्सव-भाषणीय एक आइकॉन हैं। सब मानते हैं, सराहनीय। इस अवसर पर हम लोग पूरे जनजाति समाज को एक मंच पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। और लगभग दिल्ली में 350 जनजातियां, जनजाति समाज के एक लाख से अधिक लोग एकत्रित हो रहे हैं। और यह भी इस बार होगा, इतना बड़ा समारोह। और अपनी धर्म-संस्कृति-परंपरा के उत्सव, भाषणीय इतिहास को बचाने का ख्र मैं बोलू आंदोलन है, ऐसा मैं कहूंगा। उस रूप में भगवान बिरसा मुंडा का आदर्श है। उनका 150वां जन्म वर्ष मनाया जा रहा है, ये भगवान् बिरसा मुण्डा का वैभव आज भी उतना ही ऊंचा है। भारत में तीन राज्य है जहाँ जनजाति समाज के गाँव नहीं है वो है दिल्ली हरियाणा और पंजाब। आदिवासी समाज इन तीनों राज्यों में पढ़ने के लिए लोगों का आना, रोजगार नौकरी के लिए एक अलग बात है। तो दिल्ली वालों ने कभी जनजातीय समाज को नजदीक से देखा नहीं है, समझा नहीं है और जो जानते हैं वो केवल अकादमिक जगह पर, डिस्कशन में, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी में पूछते हैं, या कुछ फिल्मों में देखते हैं। तो एक इमेज बनी हुई है कि उधर ही वो बेचारा है, पिछड़ा हुआ है, सोशल-इकोनॉमी से लैस हो रहा है। कुछ लोग उनको असंभावित हैं, बैकवर्ड है, क्रिमिनल हैं, ऐसा मानते हैं समझते हैं। उन लोगों के मन में जनजातीय समाज के बारे में एक इमेज बनी हुई है। इसलिए स्थानीय लोगों को भी आना चाहिए और सभी संस्कृति को समझना चाहिए।

❖ **इस भव्य कार्यक्रम में आपके प्रमुख सहयोगी संस्थान कौन हैं?**

जैसे कि हमारे पूरे सभी क्षेत्र से लोग आ रहे हैं। सभी राज्यों में हमारे कार्यकर्ता हैं। जैसे हमारे करिया मुंडा जी, हमारे राष्ट्रीय संरक्षक हैं। भारतीय जनजाति सुरक्षा मंच के कालीचरण जी के लोग भी इस समारोह में आएंगे। तो एक अलग रूप रहेगा और उनको भी कई जगह लोगों को वक्तव्य मिलेगा। बाकि राज्य क्षेत्र के लोग तो आएंगे ही। लेकिन ये नॉन-पॉलिटिकल कैरेक्टर में रहेगा, समाज के कैरेक्टर में रहेगा। एक्साइट्स्मेंट का स्वरूप रहेगा, इसमें कई संगठन है, जैसे अभी कुछ बिहार चल रहा है, 20 राज्यों परिषद तैयारी कर रही है, इसमें तैयारी में सभी संगठन जुड़े हैं। जैसे विद्यार्थी परिषद के लोग रहेंगे, धार्मिक संगठन भी लगे हैं, सामाजिक संगठन भी लगे हैं। जो समाज का तबका है, व्यवसायी वर्ग है, वो भी बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहा है। कॉलेज के स्टूडेंट्स भी इसमें लगे हुए हैं। तो कुल मिलाकर समाज से ही जुड़े हैं। समाज को अच्छे ढंग से दिल्लीवासियों ने स्वागत किया है। जो लोग आएंगे, एक बतनशा भाषण रहेगा। ये सारे लोग अपना खुद का टिकट निकालकर आ रहे हैं। ये कोई पॉलिटिकल पार्टी या नेशनल मीडिया को पैसा देकर नहीं ला रहे हैं। सब लोगों ने अपने टिकट का पैसा जमा किया है। ये इतिहास में भी बड़ी बात हो, पैसा देने का मतलब ही नहीं है। लोग अपने पैसे से टिकट ले रहे हैं। लोग इसलिए आ रहे हैं कि वो चाहते हैं कि हमारी धर्म-संस्कृति बचे। हम सब भारतवासी हैं, हम सब एक हैं। और जैसा कल्याण आश्रम जब काम करता है, हमारा स्लोगन है, "वनवासी है, ग्रामवासी, नगरवासी, हम सब भारतवासी", तो कुल मिलाकर जोड़ने की बात है। इसको हमने जनजाति समाज के सहारे इसलिए नहीं कह रहे हैं कि किसी के जिंदाबाद या मुर्दाबाद का कार्यक्रम है। जनजाति समाज को जोड़ने वाला एक पॉजिटिव कार्यक्रम है।

❖ **अंतिम एक सवाल आपने तो पहले ही कह दिया कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में कोई आदिवासी गांव नहीं है। जो लोग रोजगार, नौकरी के लिए आए हैं वही हैं। तो ऐसे जनजाति समाज के लिए कहेंगे कि,आप 24 मई, 2026 के कार्यक्रम में अवश्य पधारे?**

दिल्ली में भी लोग नौकरी के लिए आए, विद्यार्थी हैं, उनके लिए संपर्क चल रहा है। हम लोग के माध्यम से जो हम लोग लिखे हैं, उससे आना उनको चाहिए और हम तो ये भी कहेंगे कि ये कार्यक्रम केवल जनजाति समाज का नहीं है। अन्य भारतीय भी देखने के लिए आएं। जनजाति समाज मुख्यतः रहेगा, लेकिन जो सहयोग करने वाला समाज है, जैसे नगरीय समाज है, वो भी बड़ी संख्या में आएगा और व्यवस्था में लगेगा। वो सबको सुविधा प्रदान करेगा। सहयोगी ऐसे ही जुड़े हैं। लेकिन जो अतिथि और यजमान का संबंध होता है, उसमें अतिथि के रूप में हमारे जनजाति समाज हैं और शहर के लोग उनका सत्कार करेंगे। ऐसा ही भाव

है और इससे पहले इतिहास में देखेंगे, जब-जब नगर को आवश्यकता थी, तो जनजाति समाज के पास लोग जाते थे और सहयोग उन्हें मिलती थी राम के समय हो, या महाभारत के समय हो, या राणा प्रताप जी, रेश्वाजी महाराज के समय भी। सभी समय में देखेंगे तो इस समाज ने जनसरोकारों की रक्षा की है। आज पहली बार ये समाज नगरों में आ रहा है। और इसमें लगभग 30 प्रतिशत लोग ख्र मेरे ख्याल से कम बोल रहा हूं ख्र ये 35 प्रतिशत तक पहली बार रेलगाड़ी या इतनी लंबी सफर में बैठेंगे। ऐसे में काफी लोग हैं। महिलाएं भी बड़ी संख्या में आ रही हैं। लगभग 30 से 35 प्रतिशत चार्ट पर महिलाएं भी आ रही हैं तो इसमें जनजाति का एक अच्छा, यूनिक और रोचक स्वरूप होगा, ऐसा मुझे लगता है।

# जिस समय प्रभु राम पर संकट था, हमारे वनवासी बंधु-भगिनियों ने ही साथ दिया

**विश्व हिन्दू परिषद् इन्द्रप्रस्थ प्रांत अध्यक्ष श्रीमान कपिल खन्ना से आदिवासी समागम पर पत्रिका के दिल्ली प्रभारी पत्रकार संजय कुमार सिन्हा से हुए वार्तालाप के प्रमुख अंश :-**

❖ **इन्द्रप्रस्थ में जनजातीय समागम हो रहा है, ये शायद भारत में पहली बार हो रही होगी। हमें इस आयोजन का पता चला कि ये बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा हैं और हमें यह भी पता चला कि सारे आदिवासी समाज अपने पैसे से ट्रेंन टिकट लेकर आ रहे हैं। सबसे खास बात ये कि विश्व हिंदू परिषद् दिल्ली प्रदेश सहयोग कर रही है, मतलब व्यवस्थाओं में सहयोग कर रही है। इस संदर्भ में दिल्ली वालों की क्या प्रतिक्रिया रहेगी और उनका सहयोग कितना रहेगा?**

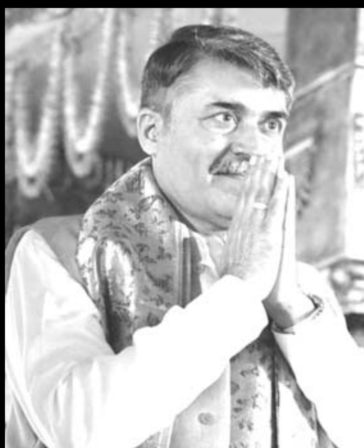

सबसे पहले तो ऐसा सौभाग्य हम इन्द्रप्रस्थ वालों को पहली बार मिली है। ये विश्व में पहली बार होने जा रहा है। इतिहास में पहली बार होने जा रहा है। इतने सब वनवासी बंधु-भगिनी अपने स्वयं के उद्देश्य से, स्वयं के संसाधन से इंद्रप्रस्थ में यहां पर आ रहे हैं। अपनी ही वेशभूषा में पूरे इंद्रप्रस्थ प्रांत को उस दिन हम लोग रंगमय बना देंगे। "जनजातीय गौरव समागम" के नाम से ये समागम होने जा रहा है। तो पूरे भारत से हमारे वनवासी बंधु-भगिनी सब आ रहे हैं। और उनके आतिथ्य में एक छोटा सा कार्य करने का, लॉजिस्टिक्स का सहयोगदान करने का सौभाग्य विश्व हिंदू परिषद इंद्रप्रस्थ प्रांत को मिला है। हम लोग अपने सौभाग्य पर इतराते हैं और पूरी मेहनत से हम सब कार्यकर्ता बंध , इस पुण्यकार्य में लगे हुए हैं। दिल्ली, जिसको कि हम इंद्रप्रस्थ कहते हैं ख्र और हम चाहते भी हैं कि इसका नाम इंद्रप्रस्थ हो ख्र उसके सभी निवासियों से हमारा अनुरोध है कि जीवन में ये पहली बार अवसर आ रहा है, जब अपनी ही वेशभूषा में हमारे वनवासी बंधु-भगिनी हमारे सामने उपस्थित होंगे और हमें प्रभु राम के सच्चे भक्त, जो उनके साथ रहे ख्र हम सब जानते हैं कि जिस समय प्रभु राम पर संकट था, जब लंका पर आक्रमण करने गए प्रभु राम, तो हमारे वनवासी बंधु-भगिनियों ने ही साथ दिया और वही उनकी ढाल बनकर उनके साथ में गए। और रावण वध का पुण्य कार्य उस समय हुआ, तो ऐसे वनवासी बंधु-भगिनी का आतिथ्य करने का सौभाग्य हमारे इंद्रप्रस्थ प्रांत के निवासियों को मिल रहा है। आप सब अपने इस सौभाग्य का पूरा लाभ लें और उनकी सेवा करें, उनको आतिथ्य प्रदान करें। और विश्व हिंदू परिषद से जुड़कर इस कार्य को करना है, ऐसी योजना बनाएं। यही मेरा आग्रह है।

मंच से उसके राष्ट्रीय संयोजक गणेश राम भगत, इन्द्रप्रस्थ प्रांत संयोजक-अशोक कुमार गोंड, महेश मागचंदका-स्वागत समिति अध्यक्ष, विशिष्ट अतिथि-डॉक्टर राजकिशोर हंसदा, सत्येन्द्र सिंह खरवार, हर्ष चौहान, बुधरी तांती, तेची गुविन, हीरा कुमार नागू, प्रकाश उईके, विश्व हिन्दू परिषद् के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता श्री आलोक कुमार, इन्द्रप्रस्थ प्रांत के अध्यक्ष खन्ना जी एवं महामंत्री सुबोध चंद्रा इसके अलावे अन्य संस्थान के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। इनसे बातें करने पर विशेष रूप में ये सभी बहुत उत्साहित हैं और गर्व कर रहे हैं।

दुनिया के सबसे बड़े जनसंख्या वाली देश भारत में समस्याएं तो अनेक है परन्तु मानव द्वारा उत्पादित समस्याएं सबसे अधिक है। दुनिया के देशों में प्राकृतिक आपदा जैसी समस्याएं ज्यादा होती है, परंतु हाल के वर्षों में आतंकी वारदात वैसे देशों में भी बढ़ा हैं जहाँ कभी शांति के लिए जाना जाता था। हम अपने देश भारत की समस्याओं पर ध्यान देते हैं तो समस्याओं में सबसे बड़ी कहें या जटिल तो वह है धर्म परिवर्तन। धोखाधड़ी से हिन्दू लड़कियों से शादी एवं उनके धन पर अधिकार, ऐसी घटना अगर नगरीय क्षेत्रों में होती है तो इसे आधुनिकता का नशा कहते हैं। परंतु ग्रामीण क्षेत्र वनवासी क्षेत्रों में ऐसी घटना को पिछड़ापन या बैकुएडनेस की संज्ञा दी जाती है अभी हम बातें करेगें जनजाति क्षेत्रों की भारत के लगभग 9 प्रतिशत जनसंख्या जो लगभग 12 करोड़ की आबादी देश में मौजूद है। इनके 97 जीले बहूसंख्यक वाले हैं। जबकि अधिसूचित जनजातीय समूह 705 है। इनके सुरक्षा हेतु विशेष कानून में प्रावधान भी है और कानून भी इसके बाद भी जनजाति वर्ग की लड़कियों को प्रेमजाल में फंसा कर उनके अधिकारों को हनन करना एवं उनके जमीन जायदाद पर कब्जा करना इसके कई उदाहरण झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश में देखा जा सकता है जबकि पीछे अधिक वर्षों से आदिवासी जंगलों और प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर रहे हैं। खनन, बांधों और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के कारण हो रहे विस्थापन से वे अपनी पारंपरिक जमीनों और आजीविका से दूर हो जाते हैं, जिससे उन्हें गहरा आर्थिक और सामाजिक संकट झेलना पड़ता है।

आदिवासी क्षेत्रों में आज भी शिक्षा का स्तर काफी निम्न है। स्कूलों की कमी, गरीबी और अपनी भाषा व संस्कृति से जुड़ाव न होने के कारण बच्चे औपचारिक शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। अशिक्षा उन्हें योजनाओं का लाभ उठाने और रोजगार प्राप्त करने में मुख्य बाधा बनती है। अधिकांश आदिवासी समुदाय आज भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं। आधुनिक तकनीक तक पहुंच न होने के कारण वे पारंपरिक कृषि करते हैं जिससे पर्याप्त आय नहीं होती। दुर्गम और जंगली इलाकों में रहने के कारण उन्हें बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं (अस्पताल, साफ पानी) समय पर नहीं मिल पातीं। कुपोषण और एनीमिया (खून की कमी) जैसी स्वास्थ्य समस्याएं इन समुदायों में बहुत अधिक देखी जाती रही हैं। वैश्वीकरण और बाहरी दुनिया के संपर्क में आने से आदिवासी अपनी पारंपरिक जीवनशैली, बोलियों और रीति-रिवाजों से दूर हो रहे हैं। एक गहरी 'पहचान का संकट' इन समुदायों के युवाओं के सामने एक बड़ी चुनौती है। अपनी संस्कृति को बचाना सबसे बड़ी चुनौती है जहाँ सुविधा आरक्षण तो जरूर है। परंतु बौद्धिक छमता कम होना भी एक समस्या माना जाना चाहिए। ●

● **संजय सक्सेना ( वरिष्ठ पत्रकार, लखनऊ )**

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा की शानदार सफलता ने उत्तर प्रदेश की सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर जो पोस्ट किया, उसमें एक गहरी चेतावनी छुपी थी। उन्होंने लिखा, 'हर फरेबी फतह की एक मियाद होती है, ये बात ही सच्चाई की बुनियाद होती है।' यह बयान महज ट्वीट नहीं, बल्कि 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव के लिए विपक्ष की मनोस्थिति का आईना है। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की हार के बाद सपा और कांग्रेस गठबंधन अब यूपी में अपनी रणनीति को नई सिरे से ढालने में जुट गया है। दरअसल, बंगाल के नतीजे विपक्ष के लिए कई सबक लेकर आए हैं। सपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरनमय नंदा ने साफ कहा कि तृणमूल की हार की बड़ी वजह भ्रष्टाचार और पुरानी सरकार के खिलाफ गुस्सा था। यूपी में भी भाजपा की सरकार दस साल पूरे कर चुकी है। ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी का सवाल स्वाभाविक रूप से उठता है। लेकिन विपक्ष जानता है कि केवल इसी पर भरोसा करके 2027 नहीं जीता जा सकता। 2024 लोकसभा चुनाव में सपा-कांग्रेस गठबंधन ने यूपी में 43 सीटें हासिल की थीं। विधानसभा क्षेत्रों में यह आंकड़ा बहुमत के काफी करीब था। इस बढ़त को मोमेंटम में बदलने की कोशिश सपा कर रही है, लेकिन बंगाल की जीत ने भाजपा के कार्यकर्ताओं में नई जान फूंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पांच राज्यों के नतीजों के बाद पार्टी कार्यालय में जो भाषण दिया, उसमें यूपी पर खास फोकस था।

उन्होंने सपा पर तीखा हमला बोला और मिशन यूपी की शुरुआत का संकेत साफ दे दिया। अखिलेश यादव भी अपने कार्यकर्ताओं को पहले से ही चेतावनी दे रहे थे कि बंगाल के बाद भाजपा का पूरा अमला यूपी की ओर मुड़ जाएगा। इसलिए सतर्क रहने की जरूरत है। विपक्ष की सबसे बड़ी चिंता अब कार्यकर्ताओं का मनोबल बनाए रखने की है। बंगाल में ममता बनर्जी के साथ अखिलेश के अच्छे संबंध रहे हैं। ममता यूपी में प्रचार भी करने आई थीं। उनकी हार ने विपक्षी खेमे में निराशा फैलाई है। बसपा के लिए तो यह स्थिति और भी चुनौती भरी है। बाइपोलर चुनावों में बसपा का अस्तित्व बचाना अब आसान नहीं रह गया है। मायावती की पार्टी को 'बी टीम' का टैग झेलना पड़ रहा है। ऐसे में कई दलित और पिछड़े वोटर सपा को विकल्प के रूप में देख रहे हैं। सपा के वरिष्ठ नेता मानते हैं कि गैर-यादव ओबीसी, दलित और अन्य वर्गों में उनका सामाजिक विस्तार काफी हद तक कामयाब रहा है। कांग्रेस के साथ गठबंधन भी कायम रखने की कोशिश है। बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने का काम पिछले काफी समय से चल रहा है।

विपक्ष को लगता है कि बंगाल में भाजपा की जीत में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और अल्पसंख्यक वोटों के बंटवारे ने भी भूमिका निभाई। यूपी में इसे रोकने के लिए अखिलेश यादव ने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को सख्त हिदायत दी है। कोई ऐसा बयान या आचरण न हो जिससे भाजपा को फायदा मिले। कानून-व्यवस्था को लेकर लगाई जाने वाली

आलोचना भी सीमित रखने की सलाह दी गई है। इसी क्रम में अखिलेश के सोशल मीडिया पर हनुमान चालीसा की पंक्तियां साझा की गईं। सॉफ्ट हिंदुत्व की छवि बनाने की कोशिश साफ नजर आ रही है। इटावा में केदारेश्वर मंदिर का लोकार्पण सावन के महीने में प्रस्तावित है। इसे भव्य बनाने की तैयारी चल रही है। महिला आरक्षण जैसे मुद्दों पर भी सपा भाजपा को घेर रही है। विपक्ष की रणनीति अब ध्रुवीकरण से बचते हुए सामाजिक समीकरणों पर जोर देने की है। बंगाल के नतीजों का मनोवैज्ञानिक असर भले ही हो, लेकिन यूपी में एंटी इनकम्बेंसी भाजपा के खिलाफ काम कर सकती है। यह तर्क सपा के नेतृत्व को भरोसा दिला रहा है। दूसरी ओर भाजपा में बंगाल की जीत से अपार उत्साह है। 2024 लोकसभा चुनाव में यूपी भाजपा का प्रदर्शन काफी खराब रहा था। मात्र 33 सीटें मिलीं और वोट प्रतिशत 41.37 प्रतिशत पर सिमट गया। सहयोगी दलों को मिलाकर एनडीए 36 सीटों पर अटक गया। 2014 में 71 सीटों और 42.32 प्रतिशत वोट के मुकाबले यह गिरावट काफी तेज थी। 2019 में वोट प्रतिशत बढ़ा लेकिन सीटें घटीं। विधानसभा चुनावों में भी 2017 की तुलना में 2022 में भाजपा की सीटें कम हुईं। 312 से घटकर 255 रह गईं। इन निराशाजनक आंकड़ों के बावजूद भाजपा 2027 की तैयारी में पूरी तरह जुट गई है। प्रदेश महामंत्री संगठन दो साल से क्षेत्रवार और विधानसभा वार बैठकें कर रहे हैं। बूथ स्तर पर नए सिरे से समीक्षा हो रही है। नई जिला इकाइयां गठित की गई हैं। पंकज चौधरी प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद लगातार दौरों पर हैं। दूध और शक्ति केंद्रों का सत्यापन कर निष्क्रिय पदाधिकारियों को हटाया जा रहा है। बंगाल में यूपी के कई मंत्रियों और नेताओं की टीम लगी थी, इसलिए यह जीत यूपी भाजपा के लिए खास महत्व रखती है। फिर भी चुनौतियां कम नहीं हैं। पार्टी के अंदर जातीय

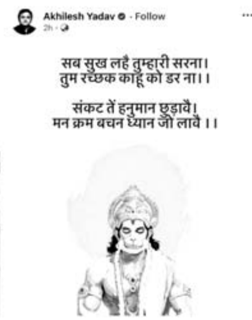


गोलबंदी एक बड़ी समस्या बन गई है। क्षत्रिय,

ब्राह्मण, कुर्मी, लोध समेत अलग-अलग जातियों की बैठकें और दबाव पार्टी नेतृत्व के लिए चिंता का विषय हैं। यूजीसी विवाद और शंकराचार्य विवाद जैसे मुद्दों पर भी जातीय रंग साफ दिखा। सरकार और संगठन के बीच समन्वय की कमी की शिकायतें भी आती रहती हैं। अधिकतर बड़े चेहरे पूर्वांचल से होने के कारण क्षेत्रीय संतुलन बनाना भी मुश्किल हो रहा है। भाजपा नेतृत्व इन मुद्दों पर लगातार काम कर रहा है। मंडल और जिला कमेटियों में विभिन्न जातियों और क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की कोशिश हो रही है। मंत्रिमंडल विस्तार और प्रदेश कार्यकारिणी में बदलाव के जरिए संतुलन साधने की कवायद चल रही है। सरकार और संगठन की बैठकें नियमित रूप से हो रही हैं ताकि कोई अंतर न रहे।

2027 का चुनाव अब सिर्फ एक साल से भी कम समय में है। दोनों तरफ तैयारियां तेज हो गई हैं। सपा सामाजिक विस्तार और समीकरणों पर भरोसा कर रही है तो भाजपा बंगाल की जीत से मिले मोमेंटम और संगठनात्मक मजबूती को भुनाने की कोशिश में है। अखिलेश यादव कार्यकर्ताओं को सतर्क रखने पर जोर दे रहे हैं तो भाजपा मिशन मोड में काम कर रही है। यूपी की सियासत में यह लड़ाई अब केवल वोट और सीटों की नहीं, बल्कि मनोबल, रणनीति और भविष्य की दिशा तय करने की भी है। बंगाल का नतीजा यूपी के लिए एक नया अध्याय खोल गया है। देखना होगा कि विपक्ष इस चुनौती का कितना मुकाबला कर पाता है और भाजपा अपनी पिछली गिरावट को कितना दूर कर पाती है। 2027 का समर सामाजिक समीकरणों, जातीय गणित और विकास के एजेंडे के बीच होगा। दोनों पक्ष पूरी ताकत झोंक रहे हैं। नतीजा जो भी हो, यूपी की राजनीति फिर से नई दिशा लेगी।●

● अजय कुमार ( वरिष्ठ पत्रकार, लखनऊ )

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर स्पष्ट और सख्त संदेश दिया है कि सार्वजनिक सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। इससे पहले भी सीएम योगी आदित्यनाथ कई बार कह चुके हैं कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी और अगर कोई ऐसा करता है, तो कार्रवाई होगी। योगी ने पहले भी कहा था कि सड़क सार्वजनिक जगह है, वहां ट्रैफिक और लोगों की सुविधा प्रभावित नहीं होनी चाहिए। यह बयान कोई नया नहीं है, लेकिन हर बार जब यह मुद्दा उठता है, तो योगी की प्रतिक्रिया और भी कड़ी होती जाती है। दरअसल, हाल ही में हैदराबाद के एक मुस्लिम उपदेशक सैय्यद अयूब ने उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को सड़क पर नमाज पढ़ने के लिए उकसाया और सीएम योगी को खुली चुनौती दी। वायरल वीडियो में सैय्यद अयूब ने कहा कि अगर मस्जिदों में जगह कम पड़ जाती है तो लोग सड़कों पर भी नमाज पढ़ सकते हैं, और उन्होंने मुख्यमंत्री को सीधी चुनौती देते हुए कहा कि अगर किसी में हिम्मत है तो मुसलमानों को सड़कों पर नमाज पढ़ने से रोककर दिखाए। इस बयान के बाद राज्य में पुलिस और प्रशासन और भी सतर्क हो गया। लेकिन योगी सरकार ने बिना किसी दबाव के अपना रुख बरकरार रखा कि सड़क किसी के लिए भी नमाज या पूजा की जगह नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कानून-व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ पर कड़ी चेतावनी देते हुए साफ कहा

कि पर्व-त्योहारों के दौरान सार्वजनिक उद्दंडता और माहौल बिगाड़ने की किसी भी कोशिश को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर हाल में शांति, सुरक्षा और अनुशासन सुनिश्चित किया जाए और धार्मिक आयोजनों में परंपरागत स्वरूप का ही पालन कराया जाए। ईद-उल-फितर और अलविदा नमाज जैसे बड़े अवसरों पर जब लाखों लोग एकत्रित होते हैं, उस समय भी सरकार ने किसी को भी सड़कों पर कब्जा करने की इजाजत नहीं दी। मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों और पुलिस कप्तानों को सीधे निर्देश दिए गए कि संवेदनशीलता के साथ काम करें, लेकिन कानून से कोई समझौता न हो। सड़क पर नमाज के अलावा योगी सरकार मस्जिदों और अन्य धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के अनियंत्रित उपयोग पर भी सख्त लगाम कसे हुए है। सीएम योगी ने आदेश दिया कि बिना इजाजत के अब लाउडस्पीकर और माइक नहीं लगाए जाएंगे। जो लाउडस्पीकर पहले से इजाजत लेकर लगे हैं, उनकी आवाज धार्मिक परिसर से बाहर नहीं जानी चाहिए। नए धार्मिक स्थलों पर नए माइक लगाने की अनुमति नहीं मिलेगी।

यह आदेश किसी एक धर्म को टारगेट करके नहीं था। यह सभी धार्मिक स्थलों पर समान रूप से लागू किया गया। मंदिर हो, मस्जिद हो या गुरुद्वारा, सबके लिए एक ही नियम। योगी सरकार की सख्ती के बाद धार्मिक स्थलों पर लगे 17 हजार लाउडस्पीकरों की आवाज धीमी हो गई और 125 जगहों से लाउडस्पीकर हटा भी दिए गए। गौरतलब हो कि साल 2023 में

सैय्यद अयूब

राजीव कृष्ण

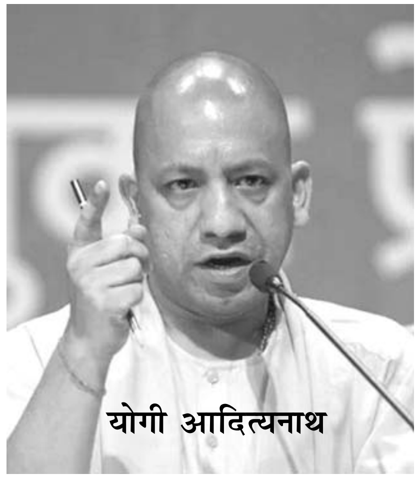
योगी आदित्यनाथ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर यूपी में 61,399 लाउडस्पीकर चेक किए गए। योगी सरकार के आने के बाद धार्मिक स्थलों से होने वाले ध्वनि प्रदूषण पर सख्ती की गई। मुख्यमंत्री ने विधानसभा सत्र में कहा था कि सरकार ने बेवजह के ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित किया है और सभी धर्मों के लोगों ने स्वेच्छा से लाउडस्पीकर हटाए हैं। बहरहाल, योगी सरकार ने केवल बयानों तक खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि जमीन पर ठोस कार्रवाई भी की।

नेपाल सीमा से लगे जनपदों में यूपी सरकार ने अवैध रूप से बनी मस्जिदों, मजारों, ईदगाहों और मदरसों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। प्रशासन ने पिछले कुछ समय में 350 से अधिक अवैध धार्मिक स्थलों को चिह्नित कर सीलिंग और ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया को अंजाम दिया। जिन जिलों में यह कार्रवाई हुई, उनमें श्रावस्ती, बहराइच, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, पीलीभीत, बलरामपुर और लखीमपुर खीरी शामिल हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर चला अवैध कब्जा मुक्त अभियान यह संदेश देता है कि प्रदेश की जमीन पर अनधिकृत कब्जा, चाहे किसी भी धर्म के नाम पर हो, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गौरतलब हो कि सड़क पर नमाज और लाउडस्पीकर जैसे मुद्दे योगी सरकार की एक बड़ी रणनीति के हिस्से हैं, और वह रणनीति है जीरो टॉलरेंस। 2017 से राज्य में डकैती, लूट, दंगा, हत्या, अपहरण और बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों में 85 फीसदी तक की भारी गिरावट दर्ज की गई है। सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के कारण उत्तर प्रदेश की कानून-व्यवस्था में बड़े पैमाने पर सुधार हुआ है। 68 माफिया और उनके करीब 1500 सहयोगियों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है और 142 अरब रुपये की अवैध संपत्ति जब्त की गई है। ये आंकड़े बताते हैं कि जिस यूपी को कभी माफियाओं का अड्डा माना जाता था, वहां अब कानून का राज स्थापित हो चुका है।

यूपी की छवि कुछ वर्ष पहले तक एक ऐसे राज्य के रूप में थी, जहाँ अलग-अलग क्षेत्रों में माफियाओं और बाहुबलियों का दबदबा था। उन्हें या तो राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था या वे खुद राजनेता बन गए थे। लेकिन देश के सबसे बड़े सूबे में योगी सरकार आने के बाद यहाँ की तस्वीर बदल गई। सरकारी दावों की पुष्टि एनसीआरबी के राष्ट्रीय स्तर के आंकड़े भी कर रहे हैं। एनसीआरबी की वर्ष 2024 की रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रीय क्राइम रेट 252.3 के मुकाबले यूपी का क्राइम रेट केवल 180.2 है। देश की लगभग 17 प्रतिशत आबादी उत्तर प्रदेश में रहती है, लेकिन कुल अपराधों के मामले में राज्य का स्थान 18वां है। यूपी के डीजीपी राजीव कृष्ण ने कहा कि पिछले नौ वर्षों में आधुनिक पुलिस स्टेशन, एंटी रोमियो स्क्वॉड, महिला हेल्प डेस्क, फास्ट ट्रैक कोर्ट और संगठित अपराधों के खिलाफ सख्त कार्रवाई ने प्रदेश में कानून-व्यवस्था को मजबूत किया है। पश्चिम बंगाल के नेता सुवेंदु अधिकारी भी पश्चिम बंगाल में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ वाला मॉडल लागू करने की बात करते नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार पहले से ही सड़कों पर नमाज पढ़ने को लेकर सख्त रुख अपनाए हुए है और सार्वजनिक स्थानों पर बिना अनुमति धार्मिक जमावड़ों पर रोक लागू है। यह योगी मॉडल की सबसे बड़ी सफलता मानी जा रही है। जब अन्य राज्यों की सरकारें यूपी की नीतियों की नकल करने लगें, तो समझिए कि काम हो रहा है। लब्बोलुआब यह है कि योगी आदित्यनाथ का यह रुख कि सड़क किसी की निजी जायदाद नहीं है, न नमाज के लिए और न किसी अन्य धार्मिक कार्यक्रम के लिए, दरअसल संविधान की भावना के अनुरूप है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कानून-व्यवस्था को सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि बताया और कहा कि बीते वर्षों में अपराध पर प्रभावी नियंत्रण, माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई और पुलिस व्यवस्था में सुधार से प्रदेश में निवेश का माहौल बेहतर हुआ है। आज का उत्तर प्रदेश वह नहीं है जहाँ अपराधी खुलेआम घूमते थे, जहाँ माफिया राजनीति को नियंत्रित करते थे, जहाँ सड़कें रात को बंद हो जाती थीं। आज का यूपी एक ऐसा प्रदेश बन रहा है जहाँ सबके लिए एक कानून है और उस कानून के सामने न कोई माफिया टिका, न कोई अतिक्रमणकारी और न कोई सड़क पर नमाज पढ़ने की जिद करने वाला।●

● **शशि रंजन सिंह/राजीव कुमार शुक्ला**

बिहार-गंगा के पवित्र तट पर बसा 38 जिलों वाला वह राज्य जहाँ बोधगया की धरती बुद्ध की करुणा से सिंची है, वैशाली की मिट्टी महावीर के पसीने से पुनीत है और सीतामढ़ी की भूमि माँ सीता के पद-चिह्नों से अंकित है। इसी राज्य में 10 से 15 हजार मंदिर और मठ हैं, जिनमें से लगभग 4,600 बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद (BSBRT) में पंजीकृत हैं। लेकिन आज इन्हीं मंदिरों की जमीनें भू-माफिया हड़प रहे हैं। महंत भ्रष्ट होकर संपत्ति बेच रहे हैं और जो संस्था इन सबकी रक्षक होनी चाहिए थी, बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद, वह खुद इन कुकृत्यों में शामिल होती दिख रही है।

बिहार हिंदू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 (अधिनियम 2, 1951) के तहत स्थापित बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद का मूल उद्देश्य था, राज्य के मंदिरों, मठों, ट्रस्टों और धर्मशालाओं की संपत्तियों की सुरक्षा, उनका उचित प्रबंधन और पूजा-पाठ की पवित्र परंपरा को अक्षुण्ण रखना। इस अधिनियम की धारा 32 स्पष्ट रूप से कहती है कि किसी भी न्यास की संपत्ति, पूजा-व्यवस्था में परिवर्तन या किसी बाहरी संस्था को अधिकार देने के लिए न्यास समिति की अनुशंसा अनिवार्य है।

2 जनवरी 2025 को बिहार सरकार के विधि विभाग ने बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया। कारण था, 'पर्षद में कार्य का संपादन ठीक से नहीं हो रहा था।' यह परिषद जनवरी 2021 में गठित की गई थी। महज 4 साल में इसका भंग होना इस बात का सबूत है कि इसका कामकाज किस स्तर तक गिर चुका था।

❖ **18 जिलों में मंदिर-मठों की जमीन की अवैध बिक्री :-** अप्रैल 2025 की एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के 18 जिलों में मंदिर-मठों की जमीनें अवैध रूप से

**रणवीर नंदन की अध्यक्षता में बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद, इस्कॉन के विवादित एच.एच. भक्ति प्रमोद भागवत महाराज और श्री राधाकुंज बिहारी वेलफेयर फाउंडेशन का एक षड्यंत्र, जो 18वीं शताब्दी के मंदिर को निगलना चाहता है।**

बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद
BIHAR STATE BOARD OF RELIGIOUS TRUSTS
VIDYAPATI MARG, PATNA - 800 001

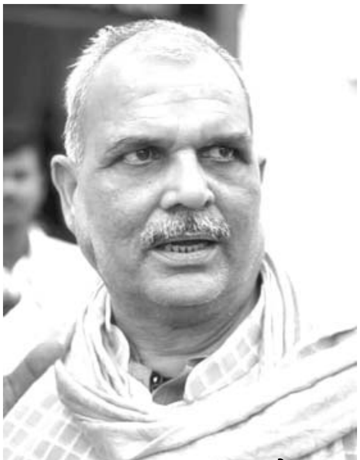

हरिभूषण ठाकुर बचोल

प्रो. रणवीर नंदन

बेची जा रही हैं। इनमें मुजफ्फरपुर, भागलपुर, जहानाबाद, कैमूर, नालंदा, लखीसराय, शिवहर, भोजपुर, पश्चिमी चंपारण, शेखपुरा, पूर्वी चंपारण, पटना, मुंगेर, खगड़िया, रोहतास, मधुबनी, दरभंगा और अरवल शामिल हैं। इन जिलों से रिकॉर्ड तक उपलब्ध नहीं है।

❖ **इन जमीनों पर :-**

फर्जी बिक्री दस्तावेज तैयार किए गए, सीमांकन और मापी में जानबूझकर कठिनाई पैदा की गई, भू-माफियाओं ने अतिक्रमण कर लिया, चहारदीवारी निर्माण तक नहीं हो पाई।

बिहार में करीब 10,000 से 15,000 मंदिर और मठ हैं, लेकिन न्यास बोर्ड में केवल 4,600 का ही निबंधन है। 2,512 से अधिक मंदिर-मठ तो पंजीकृत भी नहीं हैं।

2024 में सारण जिले के प्रसिद्ध धर्मनाथ मंदिर में लाखों रुपये के घोटाले का मामला सामने आया। समिति के कुछ सदस्य मंदिर की दानपेटी से आय न तो कोषाध्यक्ष को दे रहे थे, न सचिव को। राज्य धार्मिक न्यास परिषद ने पूरी समिति को भंग कर दिया।

❖ **मुजफ्फरपुर में महंत की हत्या, संपत्ति विवाद में जान गई :-** अगस्त 2025 में मुजफ्फरपुर के राम जानकी मठ के महंत कौशल किशोर दास की हत्या हुई। यह मठ एक जमीनी विवाद में फँसा था, स्थानीय परिवार द्वारा मठ की जमीन पर अतिक्रमण का आरोप था। यह घटना बताती है कि बिहार में मंदिर-मठों की जमीन के लिए हिंसा की हद तक जाया जा रहा है।

❖ **भीखमदास ठाकुरबाड़ी, भू-माफियाओं से सांठगांठ :-** अप्रैल 2025 में पटना के बाकरगंज स्थित भीखमदास ठाकुरबाड़ी के दोनों महंत- जय नारायण दास और विमल दास को परिषद अध्यक्ष प्रो. रणवीर नंदन ने वित्तीय अनियमितता, धोखाधड़ी और भू-माफियाओं से सांठगांठ के आरोप में तत्काल प्रभाव से हटाया।

***यहाँ विडम्बना यह है कि जिस परिषद के अध्यक्ष रणवीर नंदन ने यह कार्रवाई की, वही अध्यक्ष श्री विष्णु भगवान मंदिर के मामले में नियमों की अनदेखी करते हुए एक प्राइवेट कंपनी को मंदिर सौंप रहे हैं।***

❖ **रणवीर नंदन, विवादों में लिपटे परिषद अध्यक्ष :-** बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के पूर्व अध्यक्ष किशोर कुणाल (पूर्व IPS अधिकारी) का 29 दिसंबर 2024 को हार्ट अटैक से निधन हो गया। उनके निधन के बाद प्रोफेसर रणवीर नंदन को परिषद का अध्यक्ष बनाया गया। साथ ही हरिभूषण ठाकुर बचोल सहित 10 लोगों को सदस्य बनाया गया। परिषद अध्यक्ष बनने के तुरंत बाद नवंबर 2025 में प्रो. रणवीर नंदन ने बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम आने के दो सप्ताह के भीतर ही 'सनातन धर्म को बढ़ावा देने' के एजेंडे की घोषणा की। वे भाजपा के वरिष्ठ सदस्य के रूप में भी जाने जाते हैं।

❖ **रणवीर नंदन पर आरोप :-** स्थानीय स्तर पर प्रबंध समितियों, पुजारियों और धार्मिक संगठनों की ओर से रणवीर नंदन पर निम्नलिखित आरोप लगाए जाते रहे हैं :-

☞ बिहार के कई मठों की संपत्ति बेचने में अपने पद का दुरुपयोग।
☞ मठाधीशों की नियुक्तियाँ पैसा लेकर करना।
☞ विवादित छवि के व्यक्तियों को मठाधीश नियुक्त करना।
☞ न्यास समितियों की अनुशंसा की अनदेखी करते हुए एकतरफा निर्णय लेना।
☞ मीडिया और 'केवल सच' की जाँच के दौरान व्हाट्सएप/फोन का जवाब न देना।

'केवल सच' के संवाददाताओं ने इस मामले में प्रो. रणवीर नंदन से कई बार व्हाट्सएप और फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने एक बार भी जवाब नहीं दिया। वहीं जब 'केवल सच' ने परिषद के वरिष्ठ सदस्य और पूर्व विधायक श्री हरिभूषण ठाकुर 'बचोल' से पूछा तो उन्होंने स्वीकार किया :- ***'बिना न्यास समिति की अनुशंसा के यह नहीं किया जा सकता। मेरी जानकारी में यह बात नहीं है। अध्यक्ष महोदय का अधिकार है।'***

**हरिभूषण ठाकुर 'बचोल', (पूर्व विधायक) सह**
**वरिष्ठ सदस्य, बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद**

6 अप्रैल 2026 को प्रो. रणवीर नंदन के हस्ताक्षर से जारी पत्रांक-15 में दावा किया गया कि 13 दिसंबर 2025 की परिषद बैठक में 'सर्वसम्मति' से श्री राधाकुंज बिहारी वेलफेयर फाउंडेशन को पूजा-पाठ, राग-भोग और जीर्णोद्धार की अनुमति दी गई। यह सब कामदेव कुमार के

12 जून 2025 के व्यक्तिगत पत्र के आधार पर।

❖ **लेकिन तथ्य यह है कि :-**

☞ न्यास समिति के किसी भी सदस्य ने इसकी अनुशंसा नहीं की।

☞ न्यास समिति के पदेन अध्यक्ष (SDO) की कोई सहमति नहीं ली गई।

☞ कामदेव कुमार मंदिर प्रबंध समिति से अधिकृत नहीं हैं।

☞ कामदेव कुमार के पत्र में 'फ्लैट' की माँग भी थी, जो भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता है।

❖ **एच.एच. भक्ति प्रमोद भागवत महाराज, ISKCON विवाद:-**

एच.एच. भक्ति प्रमोद भागवत स्वामी महाराज, पूर्व में एच.जी. रुक्मिणी मोहन दास के नाम से जाने जाते थे। ये ISKCON (International Society for Krishna Consciousness) के पटना केंद्र से जुड़े रहे हैं।

अक्टूबर 2024 में ISKCON पटना में बड़ा विवाद छिड़ा। RJD नेता और पूर्व बिहार मंत्री तेज प्रताप यादव ने ISKCON पटना के प्रमुख पर यौन दुराचार का आरोप लगाया और निष्कासित करने की माँग की। ISKCON की ओर से बयान आया कि चार वरिष्ठ सदस्यों की एक जाँच टीम गठित की गई है।

❖ **ISKCON India Bureau की जाँच के बाद, मंदिर में प्रबंधन विफलता, भाई-भतीजावाद और गंभीर अनियमितताओं के मद्देनजर :-**

☞ कृष्ण कृपा दास को 5 वर्ष की अनुशासनात्मक छुट्टी पर भेजा गया।

☞ Temple Management Council गठित किया गया।

☞ कई अन्य अधिकारी भी अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत।

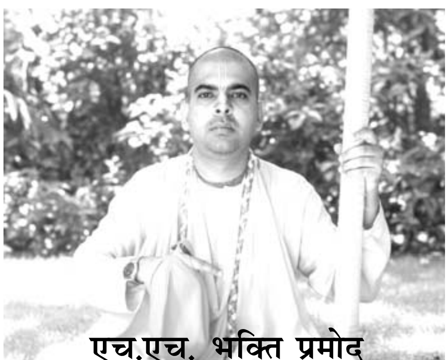
**एच.एच. भक्ति प्रमोद भागवत महाराज**

मार्च 2026 में एक वायरल ऑडियो सामने आई जिसमें देवकी नंदन दास और एच.एच. भक्ति प्रमोद भागवत स्वामी महाराज के बीच बातचीत है। इस ऑडियो ने ISKCON की आंतरिक गतिविधियों को लेकर नई बहस छेड़ दी।

❖ **भक्ति प्रमोद भागवत महाराज पर विशेष आरोप :-**

☞ नवंबर 2025 में संन्यास लेने से पहले ही मठवासियों पर शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दुर्व्यवहार के आरोप।

☞ ISKCON पटना केंद्र में गंभीर वित्तीय घोटालों की आरोपण।

☞ ISKCON की जोनल अथॉरिटी द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई।

☞ सोशल मीडिया पर लीक ऑडियो और वायरल वीडियो ने भक्त समुदाय को विभाजित किया।

❖ **ISKCON में भ्रष्टाचार का व्यापक संदर्भ :-** ISKCON का इतिहास आंतरिक विवादों से भरा रहा है। किर्तनानंदा स्वामी को 1987 में ISKCON से निष्कासित किया गया, धोखाधड़ी और बाल उत्पीड़न के आरोपों के बाद। भक्ति विद्यापूर्ण स्वामी पर 2022 में ISKCON ने बाल यौन उत्पीड़न के लिए प्रतिबंध लगाया। ISKCON बेंग्लुरू के मधु पंडित दास पर कर्नाटका हाईकोर्ट ने 'फ्रॉड' का निर्णय दिया।

***ऐसे संस्था से विवादित रूप से जुड़े व्यक्ति की प्राइवेट कंपनी को एक ऐतिहासिक मंदिर का प्रबंधन सौंपना, यह महज असावधानी नहीं, सुनियोजित षड्यंत्र की ओर इशारा करता है।***

☞ **श्री राधाकुंज बिहारी वेलफेयर फाउंडेशन : धर्म की आड़ में कॉर्पोरेट खेल :-**

☞ **कंपनी के बारे में तथ्य (MCA रिकॉर्ड) :-**

☞ कंपनी का नाम :- श्री राधाकुंज बिहारी वेलफेयर फाउंडेशन।

☞ CIN: -U88900BR2024N PL071581

☞ निगमन तिथि :- 25 सितंबर 2024

☞ प्रकार :- Private Limited Company (नॉन-गवर्नमेंट)

☞ ROC :- ROC-पटना पंजीकृत

☞ पता :- C/o Bijendra Prasad, Deewan Mohalla, Hamam, Patna-800008

❖ **निदेशकगण :-**रमेश कुमार, देवांशु अभिषेक, अमित कुमार, इशु शर्मा, शशि रंजन सिन्हा, रोहित वशिष्ट, राहुल वशिष्ट।

❖ **इस कंपनी की विवादास्पद छवि :-**

☞ यह कंपनी केवल डेढ़ साल पुरानी है।

☞ कोई स्थापित इतिहास नहीं।

☞ ISKCON के एक विवादित व्यक्तित्व से जुड़ी है।

☞ 'वेलफेयर फाउंडेशन' के नाम के बावजूद Private Limited Company की संरचना।

☞ इसका पंजीकृत पता एक निजी व्यक्ति के घर का पता है।

☞ 18वीं शताब्दी के मंदिर प्रबंधन के लिए आवश्यक अनुभव या धार्मिक परंपरा का कोई आधार नहीं।

❖ **'जीर्णोद्धार' के नाम पर क्या होगा? :-** कामदेव कुमार के पत्र को हाशिये पर लिखी उनकी अपनी टिप्पणी से स्पष्ट है कि बदले में उन्हें 'मंदिर परिसर में 2 कमरे का फ्लैट' चाहिए था।

❖ **प्रबंध समिति का आरोप :-** ***'वास्तव में मंदिर के पूजा-पाठ राग-भोग के लिए नहीं, बल्कि मंदिर की संपत्ति में निर्माण करने का***

*अधिकार उक्त निजी कंपनी को अवैधानिक रूप से दे दिया गया है।'*

❖ **श्री विष्णु भगवान मंदिर, रानीघाट : षड्यंत्र की पूरी कहानी :-**

❖ **मंदिर का इतिहास :-** श्री विष्णु भगवान मंदिर, रानीघाट (सुमति पथ, ठाकुरबाड़ी), महेंद्रू, पटना-6 गंगा नदी के तट पर 18वीं शताब्दी में स्थापित एक अत्यंत प्राचीन धार्मिक स्थल है। यह मंदिर बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद में निबंधन संख्या-716 के तहत वर्ष 1999 से पंजीकृत है।

❖ **न्यास समिति का गठन (2005) :-** परिषद के पत्रांक-3015, दिनांक-01/09/2005 के माध्यम से न्यास समिति का गठन किया गया, जिसमें अनुमंडल पदाधिकारी (पदेन अध्यक्ष), प्रत्युष नंदन, अतुल कुमार, प्रशांत कुमार, अविनाश कुमार सिन्हा, संतोष कुमार गुप्ता और विश्व मोहन प्रसाद वर्मा शामिल हैं। यह समिति तब से सक्रिय है।

❖ **2014 में भी हुआ अतिक्रमण :-** परिषद के तत्कालीन अध्यक्ष किशोर कुणाल के पत्रांक-733, दिनांक 29/8/14 के अनुसार 17 अगस्त 2014 को असामाजिक तत्वों ने चहारदीवारी तोड़कर न्यास की जमीन पर अवैध निर्माण शुरू कर दिया था। उन्होंने एसएसपी, पटना को त्वरित कार्रवाई का आदेश दिया था।

❖ **कामदेव कुमार का षड्यंत्रकारी पत्र :-** 12 जून 2025 को कामदेव कुमार ने परिषद अध्यक्ष को लिखा कि वे 27 वर्षों से पुजारी हैं और 85 वर्ष की आयु में अब पूजा करने में असमर्थ हैं, इसलिए श्री राधाकुंज बिहारी वेलफेयर फाउंडेशन को पूजा की अनुमति दी जाए।

❖ ***पत्र के हाशिये पर उन्होंने अपने परिवार के लिए मंदिर परिसर में 2 कमरे का फ्लैट माँगा।***

❖ **प्रबंध समिति के अनुसार :-**

☞ कामदेव कुमार ने प्रबंध समिति की कोई अनुमति नहीं ली।

☞ वह प्रबंध समिति के अधिकृत सदस्य नहीं हैं।

☞ उनका एकाकी पत्र लिखना ही नियम-विरुद्ध है।

❖ **परिषद का पत्रांक-15, कानून का उल्लंघन :-** 6 अप्रैल 2026 को प्रो. रणवीर नंदन के हस्ताक्षर से जारी पत्रांक-15 में कामदेव कुमार के उस अनधिकृत पत्र को आधार बनाकर श्री राधाकुंज बिहारी वेलफेयर फाउंडेशन को मंदिर की पूजा-पाठ, राग-भोग और जीर्णोद्धार की अनुमति दे दी गई।

❖ **कानूनी उल्लंघन :-**

☞ बिहार हिंदू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 की धारा 32 का खुला उल्लंघन।

☞ वर्तमान न्यास समिति की कोई अनुशंसा नहीं।

☞ पदेन अध्यक्ष SDO की सहमति नहीं।

☞ किसी कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं।

❖ **प्रबंध समिति का प्रतिरोध :-**

☞ 13 जनवरी 2025 को मंदिर प्रांगण में बैठक बुलाई गई। आवेदन की प्रतिलिपि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रमंडलीय आयुक्त, DM और SDO को भी भेजी गई।

☞ वर्ष 1945 :- मंदिर की ट्रस्ट डीड पटना रजिस्ट्री कार्यालय में दर्ज (Baba Sant Dass, Ranighat Mahendru)।

☞ वर्ष 1999 :- बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद में पंजीकरण (ज्ञापांक-2620, दिनांक-14/01/1999)।

☞ वर्ष 2005 :- न्यास समिति का गठन (पत्रांक-3015, दिनांक-01/09/2005)।

☞ वर्ष 2014 :- अतिक्रमण की शिकायत, पूर्व अध्यक्ष किशोर कुणाल का SSP को आदेश (पत्रांक-733, दिनांक-29/8/14)।

☞ 25 सितंबर 2024 :- श्री राधाकुंज बिहारी वेलफेयर फाउंडेशन का MCA में निगमन (डेढ़ साल पुरानी कंपनी)।

☞ 12 जून 2025 :-कामदेव कुमार का अनधिकृत पत्र, 'फ्लैट' की माँग सहित।

☞ 13 दिसंबर 2025 :- परिषद की बैठक (कथित 'सर्वसम्मत' निर्णय)।

☞ 6 अप्रैल 2026 :- परिषद का विवादित पत्रांक-15 जारी (प्रो. रणवीर नंदन के हस्ताक्षर)।

☞ 13 मई 2026 :- प्रबंध समिति द्वारा आपत्ति पत्र दर्ज, राष्ट्रपति से SDO तक सभी को प्रतिलिपि।

❖ **बड़ा सवाल, हिंदू मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण और धार्मिक स्वायत्तता :-** भारत में एक विचित्र विडम्बना है। मुस्लिम वक्फ बोर्ड और ईसाई चर्च की संपत्तियाँ उनकी अपनी धार्मिक संस्थाओं द्वारा प्रबंधित होती हैं। लेकिन हिंदू मंदिर सरकारी नियंत्रण में हैं। बिहार में भी यही हो रहा है। सरकार-नियुक्त परिषद एक एकछत्र शक्ति बन गई है जो बिना किसी जवाबदेही के मंदिरों का भाग्य तय कर सकती है। बिहार हिंदू धार्मिक न्यास अधिनियम में संशोधन, न्यास समिति की शक्तियाँ बढ़ें, अध्यक्ष की एकतरफा शक्तियों पर अंकुश लगे, सभी मंदिर-मठों की डिजिटल संपत्ति रजिस्ट्री तैयार हो और सार्वजनिक की जाए, परिषद के निर्णयों की जाँच के लिए स्वतंत्र लोकपाल की नियुक्ति हो, विवादित छवि के व्यक्तियों को मठाधीश या परिषद अध्यक्ष जैसे धार्मिक पदों पर न नियुक्त किया जाए, प्राइवेट कंपनियों को सार्वजनिक धार्मिक न्यास की संपत्तियाँ सौंपने पर पूर्ण प्रतिबंध हो।

❖ **उपसंहार : धर्म बचाना है तो जागना होगा :-** गंगा के तट पर 18वीं शताब्दी में बना श्री विष्णु भगवान मंदिर आज एक ऐसे षड्यंत्र का शिकार है जो तीन स्तरों पर एक साथ काम कर रहा है :-

☞ स्तर 1, व्यक्तिगत भ्रष्टाचार :- कामदेव कुमार जैसे लोग जो मंदिर की संपत्ति में 'फ्लैट' बनवाने की माँग तक पहुँच गए।

☞ स्तर 2, संस्थागत विफलता :- बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद जो धारा 32 जैसे स्पष्ट कानूनी प्रावधानों को दरकिनार कर एकाकी निर्णय लेने की संस्कृति में डूबी है।

☞ स्तर 3, बाहरी कब्जे का प्रयास :- ISKCON से विवादित रूप से जुड़े एक व्यक्ति की डेढ़ साल पुरानी प्राइवेट कंपनी जो 'जीर्णोद्धार' की आड़ में मंदिर की जमीन हड़पना चाहती है।

बिहार सरकार यदि सच में हिंदू धर्म और उसकी धरोहर की रक्षा में विश्वास रखती है, तो इस मामले में तत्काल जाँच और कार्रवाई जरूरी है।

***हिंदुओं के मंदिर, उनकी जमीन और उनकी आस्था, सब दाँव पर लगे हैं। अब चुप रहना देश के साथ विश्वासघात होगा।●***

***"साधु ऐसा चाहिए, जैसा सूप सुभाय, सार-सार को गहि रहे, थोथा देई उड़ाय।" :- संत कबीर***

● **शशि रंजन सिंह/राजीव कुमार शुक्ला**

संत कबीर ने पाखंडियों को पहचानने की कसौटी बताई थी। आज उनके ही मठ की जमीन पर जो पाखंड हो रहा है, उसे देखकर लगता है, कबीर अगर आज होते तो उनके दोहों की धार और भी पैनी होती। बिहार के समस्तीपुर जिले के रोसड़ा में 300-400 वर्ष पुराने दो कबीर मठ हैं। एक-कबीर आचार्य गद्दी, लक्ष्मीपुर बगीचा, दूसरा-कबीर वाचवंशीय आचार्य गद्दी महादेव मठ। इनकी जमीन आज एक संगठित गिरोह के कब्जे में जा रही है और तमाशा यह है कि इस गिरोह में भू-माफिया, भ्रष्ट अधिकारी, एक लालची महंत और बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद की संदिग्ध निष्क्रियता, सब एक साथ शामिल हैं।

9 फरवरी 2026 को लोकसभा में सांसद मनोज कुमार ने अतारांकित प्रश्न संख्या-1487 के माध्यम से पूछा, ''क्या भू-माफियाओं द्वारा स्थानीय प्रशासन की कथित संलिप्तता के साथ लगभग 500 करोड़ रूपये मूल्य के मुख्य मंदिरों सहित कई एकड़ भूमि को अवैध रूप से हस्तांतरित किया गया है?'' संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने उत्तर दिया, "समस्तीपुर जिला प्रशासन द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार, इन मठों की भूमि के हस्तांतरण में स्थानीय प्रशासन की ऐसी कोई भागीदारी नहीं है।"

यह उत्तर किसी खोखले मटके की तरह है-ऊपर से बंद, अंदर से खाली। क्योंकि उसी समय जब यह जवाब संसद में पढ़ा जा रहा था, बिहार विधानसभा में सरकार स्वयं स्वीकार कर चुकी थी कि "जमाबंदी बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के परिमार्जन कर ऑनलाइन कर दी गई, जो विधि संगत प्रतीत नहीं होता।" आर्थिक अपराध इकाई ने जांच का आदेश दे दिया था। दैनिक भास्कर का स्टिंग ऑपरेशन उस कमरे तक पहुँच चुका था, जहाँ बैठकर फर्जी दस्तावेज बनाए गए थे। फिर केंद्र

भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या : 1487**
उत्तर देने की तारीख : सोमवार, 9 फरवरी, 2026
20 माघ, 1947 (शक)

**बिहार में कबीर मठों का संरक्षण और विकास**

**1487. श्री मनोज कुमार:**

क्या **संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि बिहार के समस्तीपुर जिले में स्थित कबीर आचार्य गद्दी लक्ष्मीपुर बगीचा, रोसरा और कबीर वाचवंशीय आचार्य गद्दी महादेव मठ, रोसरा 300 से 400 वर्ष पुराने मठ हैं जिनकी समृद्ध आध्यात्मिक, धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत है;
(ख) क्या सरकार द्वारा पर्याप्त संरक्षण न मिलने के कारण भू-माफियाओं द्वारा स्थानीय प्रशासन की कथित संलिप्तता के साथ लगभग 500 करोड़ रुपये मूल्य के मुख्य मंदिरों सहित कई एकड़ भूमि को अवैध रूप से हस्तांतरित किया गया है;
(ग) यदि हां, तो इन महत्वपूर्ण कबीर मठों के संरक्षण, पुनरुद्धार और विकास के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(घ) क्या सरकार का बिहार में धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इन मठों में पर्यटकों और तीर्थयात्रियों के लिए स्वच्छ पेयजल, शौचालय, अतिथि गृह और सामुदायिक भवन जैसी सुविधाएं प्रदान करने का विचार है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**
**संस्कृति और पर्यटन मंत्री**
**(श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)**

(क): जी हां। कबीर आचार्य गद्दी लक्ष्मीपुर बगीचा, रोसरा और कबीर वाचवंशीय आचार्य गद्दी महादेव मठ, रोसरा, बिहार राज्य के समस्तीपुर जिले में अवस्थित हैं और ये मठ बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के अंतर्गत पंजीकृत हैं।

(ख) और (ग): समस्तीपुर जिला प्रशासन द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार, इन मठों की भूमि के हस्तांतरण में स्थानीय प्रशासन की ऐसी कोई भागीदारी नहीं है।

(घ) और (ङ): प्राप्त सूचना के अनुसार, बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड संपूर्ण राज्य में विभिन्न मठों के ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व को आत्मसात् करते हुए बिहार में धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। बिहार राज्य सरकार ने बिहार सरकार के पर्यटन विभाग की विभिन्न योजनाओं के तहत प्रमुख मठों में स्वच्छ पेय-जल, स्वच्छता सुविधाएं (शौचालय), अतिथि गृहों और सामुदायिक भवनों जैसी आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं।

*****

सुनील कुमार तिवारी
बि०प्र०से०
मा० उप मुख्यमंत्री के आप्त सचिव
बिहार सरकार, पटना

Sunil Kumar Tiwari
B.A.S.
P. S. to Hon'ble Deputy Chief Minister
Government of Bihar, Patna

पत्रांक- 900 म०उ० (आ०)

दिनांक- 19-01-2026

सेवा में,
जिला पदाधिकारी,
समस्तीपुर।

विषय:- बिहार सरकार एवं संत कबीर मठ की 13 बीघा भूमि हड़पने के संबंध में।

महाशय,

श्री रविन्द्रनाथ सिंह, पूर्व जिला सांसद प्रतिनिधि ग्राम–दुबौली, पो०–ठाठोपुर, थाना–बहेरी, जिला–दरभंगा से प्राप्त आवेदन जो रोसड़ा अंचल, समस्तीपुर के अंचलाधिकारी बंदना कुमारी, अंचल कर्मियों, रजिस्ट्रार कार्यालय के कर्मियों, महंथ विद्यानाथ शास्त्री एवं कुख्यात भू–माफिया चंदन सिंह द्वारा बिहार सरकार एवं संत कबीर मठ की लगभग 13 बीघा भूमि हड़प लिए जाने से संबंधित है।

निदेशानुसार उक्त आवेदन पर जाँच कर नियम संगत कार्रवाई करना चाहेंगे एवं की गई कार्रवाई से अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत करना चाहेंगे।

अनु०:–यथोक्त।

(सुनील कुमार तिवारी)

कार्यालय: विकास भवन, बेली रोड, पटना–800015 Office- Vikash Bhawan, Bailey Road, Patna-800015
दूरभाष 0612-2215591 (का०), ईमेल–ministercell@gmail.com Phone No.: 0612-2215591(O)

---

समाहरणालय, समस्तीपुर।
समस्तीपुर– 848101
(जिला राजस्व प्रशाखा)

पत्रांक ..23...../रा०

प्रेषक :– अपर समाहर्त्ता,
समस्तीपुर।

प्रेषित :–
1. श्री महंथ दीप नारायण दास,
कबीर मठ, लक्ष्मीपुर बगीचा,
रोसड़ा, जिला–समस्तीपुर
2. श्री चन्दन सिंह,
पिता–अखिलेश्वर सिंह,
ग्राम–महधी, जिला–समस्तीपुर

समस्तीपुर, दिनांक ..02–1–..........2026 ई०।

विषय :– अंचल रोसड़ा अन्तर्गत कबीर मठ, रोसड़ा की भूमि की कायम की गई जमाबंदी से संबंधित साक्ष्य उपलब्ध कराने के संबंध में।

उपर्युक्त विषयक प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 305/सी० दिनांक 24.12.2025 के द्वारा श्री महंथ दीप नारायण दास, कबीर मठ, लक्ष्मीपुर बगीचा, रोसड़ा, जिला–समस्तीपुर का आवेदन पत्र संलग्न कर भेजा गया है, जिसमें उनके द्वारा अंचल रोसड़ा स्थित कबीर मठ, लक्ष्मीपुर के भूमि का भू–माफिया द्वारा फर्जी कागजात के आधार पर वर्तमान अंचल अधिकारी, रोसड़ा के द्वारा गलत तरीके से जमाबंदी कायम किये जाने एवं रसीद निर्गत किये जाने की शिकायत की गई है।

उक्त आवेदन पत्र की जाँच हेतु दिनांक 06.01.2026 की तिथि निर्धारित की गई है।

अतः निदेश दिया जाता है कि उक्त आवेदन पत्र में वर्णित बिन्दुओं की जाँच हेतु निर्धारित तिथि दिनांक 06.01.2026 को 12.00 बजे दिन में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में उपस्थित होकर अपना पक्ष एवं साक्ष्य लिखित रूप में अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

इसे अत्यावश्यक समझें।

अपर समाहर्त्ता,
समस्तीपुर

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक–09/वि०प० ध्यानाकर्षण (समस्तीपुर) VI–09/2026–..........(9) रा०, पटना दिनांक–
प्रतिलिपि– उप सचिव, बिहार विधान परिषद् सचिवालय को 05 अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(मोना झा)
उप निदेशक,
सर्वेक्षण कार्यालय।

ज्ञापांक–09/वि०प० ध्यानाकर्षण (समस्तीपुर) VI–09/2026–406(9) रा०, पटना दिनांक–17/02/2026
प्रतिलिपि–प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–10ए, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(मोना झा)
उप निदेशक,
सर्वेक्षण कार्यालय।

---

सरकार को "कोई भागीदारी नहीं" कैसे दिखी? या दिखी और दिखाई नहीं दी?

❖ **चंदन सिंह : एक माफिया, एक सुनियोजित षड्यंत्र :**- इस पूरे प्रकरण की धुरी है भू–माफिया 'चंदन सिंह'। उसके नाम पर दर्ज प्रत्येक लेन–देन एक सुनियोजित कानूनी षड्यंत्र की कड़ी है :–

☞ **2016 :**- महंत विद्यानंद शास्त्री ने बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के प्रावधानों का खुला उल्लंघन करते हुए मात्र 500 रूपये के औपबंधिक स्टाम्प' पर चंदन सिंह को 8 कट्ठा भूमि व्यावसायिक प्रयोजन हेतु लीज पर दे दी। न बोर्ड की अनुमति, न उचित प्रक्रिया। एक धार्मिक मठ की संपत्ति और वह भी 500 रूपये में।

☞ **19 फरवरी 2021 :**- महंत विद्यानंद शास्त्री ने पुन: खाता संख्या–1817, जो बिहार सरकार यानी माननीय राज्यपाल के नाम दर्ज है, की 16 कट्ठा 6 धुर भूमि मात्र 70,000 रूपये वार्षिक किराये पर रजिस्टर्ड लीज पर दे दी। उस भूमि पर तुरंत अवैध 'अतिथि सत्कार होटल और विवाह भवन' खड़ा कर लिया गया।

☞ **2021 (फर्जी बीटी एक्ट) :**- जब अवैध निर्माण के विरुद्ध आवेदन हुआ और ध्वस्तीकरण की आशंका बनी, तो तत्कालीन अंचलाधिकारी 'नरेन्द्र कुमार सिंह' की मिलीभगत से 'फर्जी बीटी एक्ट' तैयार कराया गया। महादेव मठ और लीची बगीचा की लगभग '11 बीघा भूमि' के लिए एक काल्पनिक खाता संख्या–725 सृजित की गई, वर्तमान अंचलाधिकारी की मिलीभगत से रसीद कटवाई गई और बिना किसी वाद के ऑनलाइन कर दिया गया।

☞ **रजिस्टर-II में लिपापोती :**- तत्कालीन भूमि सुधार पदाधिकारी की जांच रिपोर्ट ने खुद खुलासा किया, रजिस्टर–II में मूल रूप से 'कैलू मिश्री' का नाम दर्ज था (जमाबंदी संख्या–1049/1078)। कलम से घिसकर उसे मिटाया गया और चंदन सिंह के दादा 'धीरज सिंह' का नाम अवैध रूप से अंकित कर दिया गया। यह भूमि रैयती है, मठ के नाम खतियान उपलब्ध है और रैयती भूमि का बंदोबस्त नहीं होता, फिर भी बंदोबस्त दिखाया गया। धीरज सिंह एक कर्मचारी था। बीटी एक्ट के दस्तावेज 2021 में बने हैं जबकि दावा 2008 का है। यदि वाद संख्या–566/08 एवं 567/08 वास्तव में दरभंगा में संचालित हुए थे, तो धीरज प्रसाद सिंह का वास्तविक हस्ताक्षर दरभंगा कोषागार और सेंट्रल बैंक के पेंशन अभिलेखों से मिलान कराने पर झूठ उजागर हो जाएगा।

**FSL और CFSL जांच की माँग इसीलिए है, क्योंकि यह संपूर्ण फर्जीवाड़ा 2021 में रचा गया।**

❖ **गिरोह के चेहरे, जो CDR बताएगा :**- पूर्व जिला सांसद प्रतिनिधि रविंद्रनाथ सिंह ने अपनी शिकायत में स्पष्ट लिखा है, यह गिरोह है और भू–माफिया चंदन सिंह के मोबाइल का CDR इसे साबित कर देगा।

☞ **गिरोह में शामिल हैं :**- तत्कालीन अंचलाधिकारी रोसरा 'श्री नरेन्द्र कुमार सिंह' (जो वर्तमान में भी अंचलाधिकारी हैं, यह अपने आप में प्रशासनिक संरक्षण का प्रमाण है), संविदा कर्मचारी 'श्रीमती बंदना कुमारी, अंचल कार्यालय के अन्य कर्मचारी–'सुनील सिंह', आर.ओ. रजिस्ट्री कार्यालय का 'रजिस्ट्रार', भू–माफिया 'चंदन सिंह' एवं 'शैलेन्द्र सिंह', उनके पिता 'अखिलेश्वर सिंह' (बंदोबस्त कार्यालय, दरभंगा), 'महंत बिद्यानंद शास्त्री', जिलाधिकारी 'रौशन कुमार' और बिहार सरकार का 'एक बड़ा नेता' जिसके प्रभाव में डी.एम. हैं।

❖ **न्यायालय की सुनवाई, पर माफिया बेखौफ :**- उच्च न्यायालय में सीडब्ल्यूजेसी संख्या–2291/2020 के तहत आदेश हुआ, रोसड़ा CO ने 20 जनवरी 2025 को होटल संचालक और भूमि लीजकर्ता को नोटिस जारी किया, वे आए ही नहीं।' दूसरा नोटिस जारी करना पड़ा। जमाबंदी रद्दीकरण वाद संख्या–40/2021–22 में अपर समाहर्ता न्यायालय ने जमाबंदी को यथावत रखने का आदेश दिया। महंत दीप नारायण दास वर्तमान में VLT में अपील वाद–1042/2025 लड़ रहे हैं। न्यायालय चल रहा है। नोटिस जा रहे हैं, लेकिन होटल आज भी चल रहा है। विवाह भवन आज

**प्रो० संजय कुमार सिंह, माननीय स०वि०प० से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना सं०–1/212/267**

क्या राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे : समस्तीपुर जिला अन्तर्गत रोसड़ा कबीर मठ की 13 एकड़ भूमि जी मठ के महंथों के नाम से कवाला एवं खतियान द्वारा प्राप्त है, जिसपर वर्षों से लीची बगान एवं पूर्व महंथ का समाधि स्थल मौजूद है। राजस्व अभिलेख के पंजी–2 में पूर्व में अंकित कैलू मिस्त्री का नाम कलम से घीस कर काट दिया गया और भू–माफिया चंदन सिंह, पे. अखिलेश्वर प्रसाद सिंह, सा. महथी, थाना– विभूतिपुर के वर्षों पूर्व मृत दादा श्री धीरज प्रसाद सिंह का नाम अंकित कर जमाबंदी कायम कर दिया गया है। इसकी जानकारी मिलने के बाद जमाबंदी रद्द करने हेतु अंचलाधिकारी को दिये गये आवेदन पर अंचलाधिकारी के द्वारा फर्जी माना गया है। धार्मिक न्यास परिषद्, बिहार, पटना के ज्ञापांक–776, दिनांक 27.05.2022 एवं अंचलाधिकारी, रोसड़ा के ज्ञापांक– 805, दिनांक 30.05.2022 द्वारा अपर समाहर्त्ता, समस्तीपुर ने भी भू–माफिया द्वारा दिये जा रहे दावे को फर्जी बताया है। उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, रोसड़ा ने भी अपने पत्रांक 535 दिनांक 23.06. 2022 द्वारा प्रस्तुत कागजात को फर्जी बताया है। इसके बावजूद, अभी तक जमाबंदी को निरस्त नहीं किया जा रहा है और भू–माफिया द्वारा जमीन बेचने का लगातार प्रयास किया जा रहा है।

अतः उक्त मठ की जमीन का भू–माफिया द्वारा फर्जी रूप से कायम किये गये जमाबंदी को निरस्त करने एवं इसमें संलिप्त व्यक्ति और दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई करने हेतु सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूँ।

**सरकार का वक्तव्य**

समाहर्त्ता, समस्तीपुर के प्रतिवेदनानुसार वस्तुस्थिति यह है कि विषयांकित मामले की जाँच अपर समाहर्त्ता, समस्तीपुर एवं प्रभारी पदाधिकारी, जिला राजस्व प्रशाखा, समस्तीपुर से संयुक्त रूप से कराई गई। अपर समाहर्त्ता, समस्तीपुर के पत्रांक 245/रा० दिनांक 14.01.2026 के द्वारा विषयांकित मामले का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि मठ को खतियान व निबंधित केबाला से प्राप्त है, जिसपर दशकों पूर्व से मठ का शांतिपूर्ण दखल कब्जा है। इसके विरूद्ध विपक्षी चंदन सिंह या उनके पूर्वज द्वारा सक्षम न्यायालय में कोई चुनौती नहीं दी गई है। जमाबंदी रद्दीकरण वाद संख्या 40/2021–22 में भी अपर समाहर्त्ता न्यायालय, समस्तीपुर के द्वारा जमाबंदी को यथावत रखने का आदेश दिया गया है। इससे संबंधित आवेदक महंथ दीप नारायण दास के द्वारा वर्तमान में दायर बी.एल.टी. में अपील वाद 1042/2025 लंबित है। आवेदक के द्वारा इस संबंध में आपत्ति देने के बावजूद प्रश्नगत जमाबंदी को बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के परिमार्जन कर ऑनलाईन कर दिया गया है, जो विधि संगत प्रतीत नहीं होता है। इस संबंध में विभागीय पत्रांक–383(9), दिनांक–16.02.2026 द्वारा अंचल अधिकारी, रोसड़ा, समस्तीपुर से स्पष्टीकरण से मांग की गई। स्पष्टीकरण प्राप्त कर नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।

महेश्वर हजारी
सदस्य
बिहार विधान सभा

पटना
दिनांक ________ 20

प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना।

**ध्यानाकर्षण सूचना**

बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 104 के तहत लोक महत्व के विषय पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना देता हूँ।

(महेश्वर हजारी)
131, कल्याणपुर विधान सभा क्षेत्र

समस्तीपुर जिला के रोसड़ा अंचल स्थित कबीर आचार्य गद्दी, लक्ष्मीपुर बगीचा, रोसड़ा और कबीर बाचवंशीय आचार्य गद्दी महादेव मठ की जमीन जिसका खाता सं०-1817, खेसरा-120, 121 एवं 142 (पुराना) 191, 192 एवं 193 (नया) है तथा रकबा 2 बीघा 11 कट्ठा है। उक्त जमीन को दिनांक 06.01.1984 ई० को ही माननीय राज्यपाल, बिहार के नाम कर दिया गया था जिसपर आयुर्वेदिक कॉलेज की स्थापना की गई थी। उक्त भूमि को वर्तमान महंत द्वारा वर्ष 2020 में डीड संख्या-1821, दिनांक 18.02.2020 द्वारा भू-माफिया से सांठगांठ कर किरायानामा बना लिया गया तथा उक्त जमीन पर अतिथि सत्कार होटल एवं विवाह भवन भी संचालित है जो पूर्ण रूप से अवैध है। इसी तरह संत कबीर आचार्य लीची बगीचा, लक्ष्मीपुर, रोसड़ा के 11 बीघा जमीन जो कबीर मठ का है, को स्थानीय अंचलाधिकारी द्वारा अवैध रूप से भू-माफिया के नाम संधारित कर दिया गया है।

अतएव उपरोक्त मामले की विसतृत जाँच कराकर उक्त जमीन को भू-माफिया के चंगुल से छुड़ाने हेतु तथा दोषियों पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराता हूँ।

(महेश्वर हजारी)
131, कल्याणपुर विधान सभा क्षेत्र

भी चल रहा है। माफिया के हाथ में जमीन आज भी है। यही इस प्रकरण की सबसे बड़ी विडंबना है।

❖ **विधायिका में शोर, पर जमीन पर खामोशी :-** बिहार विधानसभा में विधायक महेश्वर हजारी (131, कल्याणपुर) ने नियम 104 के तहत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया। सरकार के प्रतिनिधि ने स्वीकार किया कि जमाबंदी बिना न्यायालय के आदेश के परिमार्जन की गई, "जो विधि संगत प्रतीत नहीं होता।" फिर विभागीय पत्रांक-383(9) द्वारा 16 फरवरी 2026 को अंचल अधिकारी, रोसड़ा से स्पष्टीकरण माँगा गया। स्पष्टीकरण उसी अधिकारी से माँगा गया जो खुद संदेह के घेरे में हैं।

बिहार विधान परिषद' में प्रो. संजय कुमार सिंह के ध्यानाकर्षण सूचना 1/212/267 पर सरकार ने कहा,जाँच कराई गई, रिपोर्ट मिली, आगे कार्रवाई होगी।

उप मुख्यमंत्री के आप्त सचिव' सुनील कुमार तिवारी ने 19 जनवरी 2026 को डी.एम. समस्तीपुर को पत्र लिखा। 'आर्थिक अपराध इकाई' ने 20 फरवरी को जांच का आदेश दिया। बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग' ने भी पत्र भेजा। इतने पत्र, इतने आदेश, इतनी जांचें और फिर भी एक एफआईआर नहीं। यह संयोग नहीं, व्यवस्था है।

**रौशन कुशवाहा**
**जिलाधिकारी, समस्तीपुर**

❖ **जिलाधिकारी रौशन कुशवाहा : 4 करोड़ रूपये का सवाल :-** इस पूरे प्रकरण में सबसे गंभीर और विस्फोटक आरोप अब सामने आया है और यह आरोप सीधे जिले के सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी पर है। आवेदक रविंद्रनाथ सिंह का स्पष्ट आरोप है कि आर्थिक अपराध इकाई ने जांच का आदेश दिया, उप मुख्यमंत्री के कार्यालय ने पत्र भेजा, विधायिका ने प्रश्न उठाए, लेकिन समस्तीपुर के जिलाधिकारी रौशन कुशवाहा ने भू-माफिया चंदन सिंह से 4 करोड़ रूपये लेकर समस्त आदेशों और निर्देशों को दबा दिया और कोई कार्रवाई नहीं की।

यह आरोप यदि सच है, तो यह केवल भ्रष्टाचार नहीं, यह न्याय की हत्या है। यह उस व्यक्ति पर आरोप है जिसके हाथ में जिले की पूरी राजस्व और प्रशासनिक मशीनरी की बागडोर है। जिसके दस्तखत के बिना जांच आगे नहीं बढ़ सकती। जिसकी चुप्पी का मतलब है, माफिया को अभयदान।

❖ **कुछ तथ्य इस आरोप को और अधिक गंभीर बनाते हैं :-**

☞ रविंद्रनाथ सिंह की शिकायत में जिलाधिकारी रौशन कुमार का नाम पहले से उस गिरोह की सूची में है जो भू-माफिया की मदद कर रहा है।

☞ आर्थिक अपराध इकाई का आदेश आया, डी.एम. को पत्र मिला, और फिर कुछ नहीं। न एफआईआर, न गिरफ्तारी, न जमाबंदी निरस्त। जैसे आदेश किसी गहरे कुएँ में गिर गया।

☞ उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद होटल चल रहा है, माफिया बेखौफ है। इस बेखौफी का स्रोत कहाँ है? जब जिले का सबसे बड़ा अधिकारी ही निष्क्रिय हो या सक्रिय रूप से संरक्षण दे रहा हो, तो नीचे के अधिकारी कार्रवाई करने का साहस कहाँ से लाएँगे?

4 करोड़ का यह आरोप झूठ है या सच, यह जानने का एकमात्र तरीका है निष्पक्ष जांच। डी.एम. रौशन कुशवाहा के बैंक खातों, संपत्तियों और चंदन सिंह से मोबाइल संपर्क की जांच होनी चाहिए। यदि आरोप झूठा निकला तो डी.एम. का नाम साफ होगा। यदि सच निकला तो बिहार के प्रशासनिक तंत्र की जड़ें कितनी सड़ी हैं, यह देश के सामने आ जाएगा। सरकार से सीधा सवाल है- 'जब एक डी.एम. पर 4 करोड़ रूपये की रिश्वत लेकर माफिया को बचाने का आरोप हो, तो क्या उसे पद पर बने रहने का नैतिक अधिकार है?

❖ **धार्मिक न्यास परिषद : रक्षक ही भक्षक? :-**

☞ सबसे जलता हुआ सवाल यहाँ है। 'बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड' जो इन मठों का कानूनी संरक्षक है, इस पूरे प्रकरण में कहाँ था?

☞ 2016 में जब महंत ने 500 रूपये के स्टाम्प पर मठ की जमीन माफिया को दी, तो बोर्ड ने क्या किया? कुछ नहीं।

☞ 2021 में जब फर्जी बीटी एक्ट बना, तो बोर्ड ने क्या किया? कुछ नहीं।

धार्मिक न्यास परिषद के अध्यक्ष रणवीर नंदन के कार्यकाल में यह सब हुआ। उनकी जिम्मेदारी बनती है। या तो वे इससे अनजान थे, जो उनकी घोर अक्षमता है या वे जानते थे और चुप रहे, जो उनकी संलिप्तता

सेवा में,

माननीय मुख्यमंत्री महोदय बिहार पटना

विषय : समस्तीपुर जिलाधिकारी के संरक्षण में रोसरा अंचल में बिहार सरकार एवं कबीर मठ की लगभग 13 बीघा (अनुमानित बाजार मूल्य ₹500 करोड़) भूमि को अंचल पदाधिकारियों की मिलीभगत से रजिस्टर-II (पंजी) में छेड़छाड़ कर, फर्जी बीटी एक्ट एवं कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर भू-माफियाओं के नाम अवैध रूप से रसीद काटे जाने के संबंध में प्राथमिकी दर्ज कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि समस्तीपुर जिला के रोसरा अंचल अंतर्गत रोसरा नगर क्षेत्र में दो प्रमुख मठ स्थित हैं—(1) लीची बगीचा स्थित कबीर मठ जिसके महंत दीप नारायण दास तथा (2) महादेव मठजिसके महंत विद्यानंद शास्त्री है

रोसरा अंचल में जब से श्री नरेंद्र कुमार (तत्कालीन अंचलाधिकारी) की पदस्थापना हुई, उसी अवधि से भू-माफिया चंदन सिंह द्वारा कबीर मठ एवं बिहार सरकार (माननीय राज्यपाल) के नाम दर्ज भूमि पर फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से अवैध कब्जा एवं स्वामित्व स्थापित करने का निरंतर प्रयास किया गया। इस संबंध में तथ्य निम्नवत् हैं— जिलाधिकारी श्री योगेन्द्र कुमार सिंह के समय कोई भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़ा नहीं हुआ श्री योगेन्द्र कुमार के स्थानान्तरण के बाद श्री रौशन कुमार जिलाधिकारी समस्तीपुर और इनके संरक्षण में फर्जीवाड़ा हुआ —

1. सर्वप्रथम वर्ष 2016 में महंत विद्यानंद शास्त्री द्वारा बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए मात्र ₹500 के औपचारिक स्टाम्प पर भू-माफिया चंदन सिंह को 8 कट्ठा भूमि व्यवसायिक प्रयोजन हेतु लीज पर दी गई।

2. पुनः दिनांक 19.02.2021 को खाता संख्या 1817, खेसरा संख्या 120/121/142 (पुराना) तथा नया खेसरा 191/192/193 की भूमि, जो बिहार सरकार (माननीय राज्यपाल) के नाम दर्ज है, को महंत विद्यानंद शास्त्री द्वारा 16 कट्ठा 6 धुर क्षेत्रफल में ₹70,000 वार्षिक किराया पर रजिस्टर्ड लीज पर दे दिया गया, जिस पर अवैध रूप से अतिथि सत्कार होटल एवं विवाह भवन का निर्माण कर लिया गया।

3. उक्त भूमि, जो माननीय राज्यपाल, बिहार सरकार के नाम से निबंधन संख्या 218 दिनांक 06.01.1984 के तहत मौजा रोसरा, थाना संख्या 69 में अवस्थित है— खाता संख्या 105, खेसरा संख्या 102 एवं 120 (पुराना), रकबा 1 बीघा 11 कट्ठा खाता संख्या 235, खेसरा संख्या 142, रकबा 1 बीघा कुल रकबा 2 बीघा 11 कट्ठा 11 धुर है, जो आयुर्वेदिक फार्मेसी कॉलेज, बिहार सरकार के नाम दर्ज है एवं जिसकी सरकारी रसीद भी कटी हुई है।

जब अवैध होटल निर्माण के विरुद्ध आवेदन दिया गया और यह आशंका उत्पन्न हुई कि निर्माण ध्वस्त हो सकता है, तब वर्ष 2021 में तत्कालीन अंचलाधिकारी नरेंद्र कुमार सिंह की मिलीभगत से फर्जी बीटी एक्ट तैयार कराया गया। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर महादेव मठ की भूमि (खाता संख्या 120/121/140/142) तथा कबीर मठ लीची बगीचा की लगभग 11 बीघा भूमि (खेसरा संख्या 6243/6244/6245/6246/6247/1092/1519/1516) को एक काल्पनिक खाता संख्या 725 सृजित कर वर्तमान अंचलाधिकारी की मिलीभगत से रसीद कटवा दी गई तथा बिना किसी वाद संख्या के ऑनलाइन कर दिया गया। कागजात के अवलोकन से स्पष्ट है की पूर्व अंचलाधिकारी आम्रपाली यादव के दुआरा वाद संख्या 226/2021/22 को अस्वीकृत कर दिया गया था जिसका खाता संख्या 247 खेसरा 1512,1513,120,121,1519,1516,1092,6245,6244,6243,6246,6247,140,142, लिखा हुआ है ,और रसीद खाता संख्या -725 खेसरा 6247,120,121,6243,6244,1512,1513,1519,1092,1516, अंकित है।

5. रोसरा के तत्कालीन भूमि सुधार पदाधिकारी की जांच रिपोर्ट में यह स्पष्ट है कि रजिस्टर-II (पंजी) में मूल रूप से कैलू मिस्त्री का नाम दर्ज था (जमाबंदी संख्या 1049/1078), जिसे कलम से घिसकर भू-माफिया चंदन सिंह के दादा धीरज सिंह का नाम अवैध रूप से अंकित कर दिया गया।

6. धीरज सिंह एक कर्मचारी थे, जबकि बीटी एक्ट से संबंधित कथित दस्तावेज वर्ष 2021 में बनाए गए हैं। यदि वास्तव में बीटी एक्ट वाद संख्या 566/08 एवं 567/08 बंदोबस्त कार्यालय, दरभंगा में संचालित हुए थे, तो वहां दायर वाद आवेदन पर धीरज प्रसाद सिंह का वास्तविक हस्ताक्षर होना चाहिए, जिसका मिलान दरभंगा कोषागार एवं सेंट्रल बैंक, रोसरा में उपलब्ध पेंशन अभिलेखों से कराया जा सकता है। उक्त खाता खेसरा रैयती भूमि का है जिसका खतियान उपलब्ध है मठ के नाम से और रैयती भूमि का बंदोबस्त नहीं होता है।

7. रजिस्टर-II एवं बीटी एक्ट वाद संख्या 566/08 एवं 567/08 की FSL एवं CFSL जांच कराए जाने पर यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित हो जाएगा कि यह संपूर्ण फर्जीवाड़ा वर्ष 2021 में किया गया है।

8. यदि उक्त भूमि वास्तव में चंदन सिंह एवं शैलेन्द्र सिंह की थी, तो उन्होंने पहले महंत विद्यानंद शास्त्री से लीज क्यों ली? स्पष्ट है कि पहले अवैध लीज ली गई और बाद में फर्जी दस्तावेज तैयार कर बिहार सरकार एवं मठ की लगभग ₹500 करोड़ मूल्य की भूमि को अपने नाम कराने का षड्यंत्र रचा गया।

9. तौजी संख्या 6424, थाना संख्या 69, होल्डिंग संख्या 95, खेसरा संख्या 6243/6244/6245 (नया खेसरा 217/219) की भूमि भी दिनांक 19.12.1989 से संत कबीर चिल्ड्रेन एकेडमी, बिहार सरकार (माननीय राज्यपाल) के नाम दर्ज है। लोकसभा में दिनांक 9.02.2026 को माननीय सांसद मनोज राम जी के दुआरा प्रश्न भी किया गया है ,जिलाधिकारी समस्तीपुर के दुआरा सदन को गुमराह किये है जवाब दिया गया है की स्थानीय प्रशासन के दुआरा कोई भी जमीन किसी को हस्तांतरित नहीं किया गया है जबकि सभी दस्तावेज और साक्ष्य मेरे पास मौजूद है और जिलाधिकारी के पास भी जिसका लिखित कापी और वीडियो भी साक्ष्य के रूप में और न्यूज 18 का वीडियो जिलाधिकारी के साथ का वीडियो भी है जिसमें भू माफियाओं को अंचलाधिकारी के सहयोग से डीएम सरकारी और मठ का जमीन हस्तांतरित किये है।

उक्त संपूर्ण फर्जीवाड़े में निम्नलिखित व्यक्तियों/पदाधिकारियों की संलिप्तता स्पष्ट है—और यह गिरोह है जिसमें अन्य अपरोक्ष रूप से संलिप्त है जो भू माफिया चन्दन सिंह के मोबाइल के सीडीआर से स्पष्ट हो जाएगा — तत्कालीन अंचलाधिकारी, रोसरा – श्री नरेंद्र कुमार सिंह वर्तमान अंचलाधिकारी – श्रीमती वंदना कुमारी ,संविदा कर्मचारी – सुनील सिंह अंचल कार्यालय के अन्य कर्मचारी एवं राजस्व अधिकारी (RO) रजिस्ट्री कार्यालय के रजिस्ट्रार भू-माफिया चंदन सिंह, शैलेन्द्र सिंह, पिता – अखिलेश्वर सिंह बंदोबस्त कार्यालय, दरभंगा ,समस्तीपुर के कुछ कर्मी एवं महंत विद्यानंद शास्त्री और जिलाधिकारी रौशन कुमार एवं बिहार सरकार में एक बड़े नेता भी संलिप्त है जिससे डीएम प्रभावित है।

इस पूरे प्रकरण की पुष्टि दैनिक भास्कर के स्टिंग ऑपरेशन में भी हुई है। जिस स्थान पर बैठकर फर्जी बीटी एक्ट का दस्तावेज तैयार किया गया, उसका प्रमाण भी मेरे पास उपलब्ध है।

अतः श्रीमान से विनम्र आग्रह है कि उपर्युक्त सभी नामजद व्यक्तियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर, जनहित एवं राज्यहित में भू-माफिया गिरोह एवं उनके सहयोगियों के विरुद्ध कठोर विधिसम्मत कार्रवाई करने की कृपा की जाए जब रौशन कुमार भोजपुर जिलाधिकारी थे BPSC पेपर लिक हुआ था वहा से हटाकर बेगुसराय पोस्टिंग हुई थी

माननीय राज्यपाल के नाम से दस्तावेज एवं रसिद का कापी संलग्न , आयुर्वेदिक कालेज संचालित था उसका प्रमाण भी है ,चन्दन सिंह एवं शैलेन्द्र सिंह के दुआरा महंत विद्यानंद शास्त्री के दुआरा एग्रीमेंट किरायानामा का दस्तावेज संलग्न अनुसंधान के दौरान सभी साक्ष्य एवं दस्तावेज मेरे द्वारा उपलब्ध करा दिए जाएंगे।

भवदीय,

रविंद्रनाथ सिंह

पूर्व जिला सांसद प्रतिनिधि, समस्तीपुर

ग्राम – दुबौली, पोस्ट – ठाठोपुर , थाना – बहेरी, जिला – दरभंगा, पिन – 847105 मोबाइल : 7004238997

ई-मेल : ravindranathsingh24@gmail.com

Ravindra Nath Singh

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक, महोदय आर्थिक अपराध इकाई , बिहार पटना

विषय : समस्तीपुर जिलाधिकारी के संरक्षण में रोसरा अंचल में बिहार सरकार एवं कबीर मठ की लगभग 13 बीघा (अनुमानित बाजार मूल्य ₹500 करोड़) भूमि को अंचल पदाधिकारियों की मिलीभगत से रजिस्टर-II (पंजी) में छेड़छाड़ कर, फर्जी बीटी एक्ट एवं कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर भू-माफियाओं के नाम अवैध रूप से रसीद काटे जाने के संबंध में प्राथमिकी दर्ज कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि समस्तीपुर जिला के रोसरा अंचल अंतर्गत रोसरा नगर क्षेत्र में दो प्रमुख मठ स्थित हैं—(1) लीची बगीचा स्थित कबीर मठ जिसके महंत दीप नारायण दास तथा (2) महादेव मठजिसके महंत विद्यानंद शास्त्री है

रोसरा अंचल में जब से श्री नरेंद्र कुमार (तत्कालीन अंचलाधिकारी) की पदस्थापना हुई, उसी अवधि से भू-माफिया चंदन सिंह द्वारा कबीर मठ एवं बिहार सरकार (माननीय राज्यपाल) के नाम दर्ज भूमि पर फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से अवैध कब्जा एवं स्वामित्व स्थापित करने का निरंतर प्रयास किया गया। इस संबंध में तथ्य निम्नवत् हैं— जिलाधिकारी श्री योगेन्द्र कुमार सिंह के समय कोई भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़ा नहीं हुआ श्री योगेन्द्र कुमार के स्थानान्तरण के बाद श्री रौशन कुमार जिलाधिकारी समस्तीपुर और इनके संरक्षण में फर्जीवाड़ा हुआ —

1. सर्वप्रथम वर्ष 2016 में महंत विद्यानंद शास्त्री द्वारा बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए मात्र ₹500 के औपचारिक स्टाम्प पर भू-माफिया चंदन सिंह को 8 कट्ठा भूमि व्यवसायिक प्रयोजन हेतु लीज पर दी गई।

2. पुनः दिनांक 19.02.2021 को खाता संख्या 1817, खेसरा संख्या 120/121/142 (पुराना) तथा नया खेसरा 191/192/193 की भूमि, जो बिहार सरकार (माननीय राज्यपाल) के नाम दर्ज है, को महंत विद्यानंद शास्त्री द्वारा 16 कट्ठा 6 धुर क्षेत्रफल में ₹70,000 वार्षिक किराया पर रजिस्टर्ड लीज पर दे दिया गया, जिस पर अवैध रूप से अतिथि सत्कार होटल एवं विवाह भवन का निर्माण कर लिया गया।

3. उक्त भूमि, जो माननीय राज्यपाल, बिहार सरकार के नाम से निबंधन संख्या 218 दिनांक 06.01.1984 के तहत मौजा रोसरा, थाना संख्या 69 में अवस्थित है— खाता संख्या 105, खेसरा संख्या 102 एवं 120 (पुराना), रकबा 1 बीघा 11 कट्ठा खाता संख्या 235, खेसरा संख्या 142, रकबा 1 बीघा कुल रकबा 2 बीघा 11 कट्ठा 11 धुर है, जो आयुर्वेदिक फार्मेसी कॉलेज, बिहार सरकार के नाम दर्ज है एवं जिसकी सरकारी रसीद भी कटी हुई है।

जब अवैध होटल निर्माण के विरुद्ध आवेदन दिया गया और यह आशंका उत्पन्न हुई कि निर्माण ध्वस्त हो सकता है, तब वर्ष 2021 में तत्कालीन अंचलाधिकारी नरेंद्र कुमार सिंह की मिलीभगत से फर्जी बीटी एक्ट तैयार कराया गया। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर महादेव मठ की भूमि (खाता संख्या 120/121/140/142) तथा कबीर मठ लीची बगीचा की लगभग 11 बीघा भूमि (खेसरा संख्या 6243/6244/6245/6246/6247/1092/1519/1516) को एक काल्पनिक खाता संख्या 725 सृजित कर वर्तमान अंचलाधिकारी की मिलीभगत से रसीद कटवा दी गई तथा बिना किसी वाद संख्या के ऑनलाइन कर दिया गया। कागजात के अवलोकन से स्पष्ट है की पूर्व अंचलाधिकारी आम्रपाली यादव के दुआरा वाद संख्या 226/2021/22 को अस्वीकृत कर दिया गया था जिसका खाता संख्या 247 खेसरा 1512,1513,120,121,1519,1516,1092,6245,6244,6243,6246,6247,140,142, लिखा हुआ है ,और रसीद खाता संख्या -725 खेसरा 6247,120,121,6243,6244,1512,1513,1519,1092,1516, अंकित है।

5. रोसरा के तत्कालीन भूमि सुधार पदाधिकारी की जांच रिपोर्ट में यह स्पष्ट है कि रजिस्टर-II (पंजी) में मूल रूप से कैलू मिस्त्री का नाम दर्ज था (जमाबंदी संख्या 1049/1078), जिसे कलम से घिसकर भू-माफिया चंदन सिंह के दादा धीरज सिंह का नाम अवैध रूप से अंकित कर दिया गया।

6. धीरज सिंह एक कर्मचारी थे, जबकि बीटी एक्ट से संबंधित कथित दस्तावेज वर्ष 2021 में बनाए गए हैं। यदि वास्तव में बीटी एक्ट वाद संख्या 566/08 एवं 567/08 बंदोबस्त कार्यालय, दरभंगा में संचालित हुए थे, तो वहां दायर वाद आवेदन पर धीरज प्रसाद सिंह का वास्तविक हस्ताक्षर होना चाहिए, जिसका मिलान दरभंगा कोषागार एवं सेंट्रल बैंक, रोसरा में उपलब्ध पेंशन अभिलेखों से कराया जा सकता है। उक्त खाता खेसरा रैयती भूमि का है जिसका खतियान उपलब्ध है मठ के नाम से और रैयती भूमि का बंदोबस्त नहीं होता है।

7. रजिस्टर-II एवं बीटी एक्ट वाद संख्या 566/08 एवं 567/08 की FSL एवं CFSL जांच कराए जाने पर यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित हो जाएगा कि यह संपूर्ण फर्जीवाड़ा वर्ष 2021 में किया गया है।

8. यदि उक्त भूमि वास्तव में चंदन सिंह एवं शैलेन्द्र सिंह की थी, तो उन्होंने पहले महंत विद्यानंद शास्त्री से लीज क्यों ली? स्पष्ट है कि पहले अवैध लीज ली गई और बाद में फर्जी दस्तावेज तैयार कर बिहार सरकार एवं मठ की लगभग ₹500 करोड़ मूल्य की भूमि को अपने नाम कराने का षड्यंत्र रचा गया।

9. तौजी संख्या 6424, थाना संख्या 69, होल्डिंग संख्या 95, खेसरा संख्या 6243/6244/6245 (नया खेसरा 217/219) की भूमि भी दिनांक 19.12.1989 से संत कबीर चिल्ड्रेन एकेडमी, बिहार सरकार (माननीय राज्यपाल) के नाम दर्ज है। लोकसभा में दिनांक 9.02.2026 को माननीय सांसद मनोज राम जी के दुआरा प्रश्न भी किया गया है ,जिलाधिकारी समस्तीपुर के दुआरा सदन को गुमराह किये है जवाब दिया गया है की स्थानीय प्रशासन के दुआरा कोई भी जमीन किसी को हस्तांतरित नहीं किया गया है जबकि सभी दस्तावेज और साक्ष्य मेरे पास मौजूद है और जिलाधिकारी के पास भी जिसका लिखित कापी और वीडियो भी साक्ष्य के रूप में और न्यूज 18 का वीडियो जिलाधिकारी के साथ का वीडियो भी है जिसमें भू माफियाओं को अंचलाधिकारी के सहयोग से डीएम सरकारी और मठ का जमीन हस्तांतरित किये है।

उक्त संपूर्ण फर्जीवाड़े में निम्नलिखित व्यक्तियों/पदाधिकारियों की संलिप्तता स्पष्ट है—और यह गिरोह है जिसमें अन्य अपरोक्ष रूप से संलिप्त है जो भू माफिया चन्दन सिंह के मोबाइल के सीडीआर से स्पष्ट हो जाएगा — तत्कालीन अंचलाधिकारी, रोसरा – श्री नरेंद्र कुमार सिंह वर्तमान अंचलाधिकारी – श्रीमती वंदना कुमारी ,संविदा कर्मचारी – सुनील सिंह अंचल कार्यालय के अन्य कर्मचारी एवं राजस्व अधिकारी (RO) रजिस्ट्री कार्यालय के रजिस्ट्रार भू-माफिया चंदन सिंह, शैलेन्द्र सिंह, पिता – अखिलेश्वर सिंह बंदोबस्त कार्यालय, दरभंगा ,समस्तीपुर के कुछ कर्मी एवं महंत विद्यानंद शास्त्री और जिलाधिकारी रौशन कुमार एवं बिहार सरकार में एक बड़े नेता भी संलिप्त है जिससे डीएम प्रभावित है।

इस पूरे प्रकरण की पुष्टि दैनिक भास्कर के स्टिंग ऑपरेशन में भी हुई है। जिस स्थान पर बैठकर फर्जी बीटी एक्ट का दस्तावेज तैयार किया गया, उसका प्रमाण भी मेरे पास उपलब्ध है।

अतः श्रीमान से विनम्र आग्रह है कि उपर्युक्त सभी नामजद व्यक्तियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर, जनहित एवं राज्यहित में भू-माफिया गिरोह एवं उनके सहयोगियों के विरुद्ध कठोर विधिसम्मत कार्रवाई करने की कृपा की जाए जब रौशन कुमार भोजपुर जिलाधिकारी थे BPSC पेपर लिक हुआ था वहा से हटाकर बेगुसराय पोस्टिंग हुई थी

माननीय राज्यपाल के नाम से दस्तावेज एवं रसिद का कापी संलग्न , आयुर्वेदिक कालेज संचालित था उसका प्रमाण भी है ,चन्दन सिंह एवं शैलेन्द्र सिंह के दुआरा महंत विद्यानंद शास्त्री के दुआरा एग्रीमेंट किरायानामा का दस्तावेज संलग्न अनुसंधान के दौरान सभी साक्ष्य एवं दस्तावेज मेरे द्वारा उपलब्ध करा दिए जाएंगे।

भवदीय,

रविंद्रनाथ सिंह

पूर्व जिला सांसद प्रतिनिधि, समस्तीपुर

ग्राम – दुबौली, पोस्ट – ठाठोपुर , थाना – बहेरी, जिला – दरभंगा, पिन – 847105 मोबाइल : 7004238997

ई-मेल : ravindranathsingh24@gmail.com

RavindraNathSu

पत्रांक 5 ... /परिवाद शाखा
आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना
(डॉ॰ श्रीकृष्ण सिंह पथ, बेली रोड, पटना-800001)
(eoupo-pat-bih@nic.in)

पटना, दिनांक- 20.02.26

प्रेषक,
पुलिस अधीक्षक,
आर्थिक अपराध इकाई,
बिहार, पटना।

सेवा में,
जिला पदाधिकारी,
समस्तीपुर।

विषय :- आवेदक रविंद्रनाथ सिंह के परिवाद पत्र के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि आवेदक रविंद्रनाथ सिंह का परिवाद पत्र इकाई को प्राप्त हुआ है, जिसे मूल में संलग्न कर भेजा जा रहा है।

प्राप्त परिवाद पत्र में उल्लेखित है कि अंचलाधिकारी, रोसड़ा (समस्तीपुर जिला) श्रीमती वंदना कुमारी एवं संविदा कर्मचारी सुनील सिंह के द्वारा भू-माफिया के मिलीभगत से बिहार सरकार को दान में दी गई भूमि का फर्जी दाखिल खारिज करने, रसिद निर्गत करने, छेड़छाड़ करने, फर्जी बीटी एक्ट एवं कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर भू-माफियाओं के नाम अवैध रूप से रसीद काटे जाने, न्यायालय के आदेश का अवहेलना कर अवैध निर्माण करने के आरोप से संबंधित है। आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना द्वारा उक्त आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

अतः अनुरोध है कि आवेदन की प्रति में वर्णित तथ्यों की जाँच कराकर आवश्यक कारवाई करने की कृपा की जाय। इस संबंध में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

अनुलग्नक :- यथोपरि।

विश्वासभाजन,
20/2/26
पुलिस अधीक्षक,
आर्थिक अपराध इकाई,
बिहार, पटना।

प्रतिलिपि– परिवादी रविंद्रनाथ सिंह ग्राम-दुबौली, पोस्ट-ठाठोपुर, थाना-बहेरी जिला-दरभंगा पिन-847105 मो0-7004238997 को सूचनार्थ।

20/2/26
पुलिस अधीक्षक,
आर्थिक अपराध इकाई,
बिहार, पटना।

है। बोर्ड का दायित्व है पंजीकृत मठों की संपत्ति की निगरानी करना। वह संपत्ति आँखों के सामने लुट रही थी और बोर्ड की आँखें मूंदी रहीं। एक निष्पक्ष जांच यह भी पूछे कि क्या धार्मिक न्यास परिषद को इस षड्यंत्र से कोई लाभ मिला? क्या बोर्ड के किसी पदाधिकारी और चंदन सिंह के बीच कोई सम्पर्क था?

❖ **अंत में :- कबीर की जमीन, लोकतंत्र की परीक्षा :-** एक महान संत की विरासत, जिन्होंने जाति, धर्म और पाखंड के विरुद्ध जीवन भर लड़े। उनके मठ की जमीन पर आज वही पाखंड हावी है, जिसके विरुद्ध वे बोले थे। फर्क सिर्फ इतना है कि आज पाखंडी सरकारी कागजों की आड़ में छुपे हैं। लोकसभा में झूठा जवाब दिया जाता है। विधानसभा में सच माना जाता है पर कार्रवाई टाली जाती है। न्यायालय नोटिस भेजता है, माफिया आता नहीं। अधिकारी जांच करते हैं, पर जिससे पूछना है वही संदिग्ध है। यह सिर्फ एक जमीन का मामला नहीं है। यह इस बात का मामला है कि बिहार में धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा करने वाली संस्थाएं खुद माफिया के साथ मिलकर उसे लूटने में लगी हैं। माँग सीधी है-FSL/CFSL जांच, नामजद व्यक्तियों पर तत्काल एफआईआर, फर्जी जमाबंदी निरस्त, मठ की भूमि वापस और धार्मिक न्यास परिषद की स्वतंत्र जांच। अगर यह नहीं हुआ तो मान लीजिए कि बिहार में धर्म, कानून और लोकतंत्र तीनों की जमीन माफिया के हाथ में है।●

# दिवंगत संजय यादव के ब्रह्मभोज में पहुंचे तेस्जवी, बंधाया ढ़ाढ़स

● श्रीकांत कुमार श्रीवास्तव

धनरूआ प्रखंड अध्यक्ष संजय यादव के ब्रह्मोज में मसौढ़ी श्रीनगर में राजद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहुँचे। तेजस्वी यादव ने उनके तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दिया और शोकाकुल परिवार का ढाढस बंधाया। उक्त कार्यक्रम में तेजस्वी यादव समेत प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल, सांसद अभय कुशवाहा, पूर्व विधायक रेखा देवी, पूर्व विधायक जहानाबाद, सुजय यादव, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी, सैकड़ो जनप्रतिनिधियों, कार्यकर्त्ताओं और समर्थको का जनसैलाब उमड़ पड़ा। दिवंगत संजय यादव धनरूआ प्रखंड के दुभारा पंचायत अंतर्गत चंदाचक निवासी स्व० रामउग्रह प्रसाद यादव के पुत्र थे। वे लंबे समय से राजद से जुड़े रहे। उनके समर्थन और सक्रियता को देखते हुए 27 दिसंबर 2015 को उन्हें पहली बार प्रखंड अध्यक्ष बनाया गया था। इसके बाद 2019 और 2025 फिर से उन्हें यह जिम्मेवारी दिया गया। हाल ही में लगातार चौथी बार प्रखंड अध्यक्ष धनरूआ चुने गए थे।

राजद नेता प्रतिपक्ष ने बताया कि संजय यादव पार्टी के मजबूत स्तम्भ थे। यह राजद पार्टी के लिए अपूरणीय क्षति है। शोक संतप्त पत्नी और उनके पुत्र सन्नी कुमार से मिलकर तेजस्वी यादव भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि उनका पंचायत से लेकर बूथ स्तर को मजबूती प्रदान करने में अहम योगदान रहा। उनका असमय जाना पार्टी के लिए अपूरणीय क्षति हैं। लालू जी और पूरा राजद परिवार इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ खड़ा है। पूर्व विधायक रेखा देवी ने कहा कि संजय भाई ने 2005 से राजद का झंडा बुलंद किया। वे जमीन से जुड़े नेता थे। उन्होंने कहा कि वे हमेशा सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी। शोक सभा में उपस्थित सभी लोगों ने दो मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। इस दौरान जिलाध्यक्ष देवमुनि सिंह यादव समेत सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे।●

# बिहार के पाँच खिलाड़ी वर्ल्ड योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में चयनित

● श्रीकांत कुमार श्रीवास्तव

अहमदाबाद के ट्रांस स्टेडियम में 4 जून से 8 जून तक होने वाली पहली वर्ल्ड योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में बिहार के पांच खिलाड़ी चयनित हुए हैं। इसमें सुधांशु शेखर (बैकवर्ड बेंड), दिलीप कुमार (फॉरवर्ड बेंड) मसौढ़ी पटना, सारांश कुमार (रिधिक पेयर), सोनी कुमारी (लेग बैलेंस) और साक्षी कुमारी (बैकवर्ड बेंड) शामिल हैं। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रवींद्रण शंकरण ने बताया कि बिहार के ये पाँच खिलाड़ी योगासन

सोनी कुमारी – लेग बैलेंस

सारांश कुमार – रिदमिक पेयर

दिलीप कुमार – फॉरवर्ड बेंड

सुधांशु शेखर – बैकवर्ड बेंड

की अलग-अलग स्पर्धाओं में भारतीय टीम के लिए चयनित हुए हैं। ये सभी खिलाड़ी प्रथम वर्ल्ड योगासन स्पोर्ट्स चौंपियनशिप में हिस्सा लेंगे। इन चयनित खिलाड़ियों का इंडियन नेशनल टीम के लिए नेशनल कोचिंग कैंप 10 मई से 2 जून तक नारंगपुरा स्पोटर्स कॉम्प्लेक्स अहमदाबाद, गुजरात में होने वाला है। सभी चुने हुए एथलीट को 9 मई को शाम 5 बजे तक कैंप की जगह पर रिपोर्ट करना अनिवार्य है। आज आधुनिक युग के 21वीं शताब्दी में योग को अपनाकर अपने जीवन शैली में करोड़ो लोग आमूल चूल परिवर्तन कर रहे हैं। सात्विक आहार और योग के सहारे आध्यात्मिकता की ओर बढ़ा है।●

# जातियों के बंधन में जकड़ा लोकतंत्र

● डॉ० लक्ष्मीनारायण सिंह

भाजपा नेत्री ममता पटेल ने कहा कि सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि देश में चुनाव हो रहे हैं या नहीं, बल्कि यह है कि क्या सच में लोकतंत्र बचा है, या वह जातियों के ठेकेदारों के हाथों गिरवी रख दिया गया है? कागजों पर बराबरी, संविधान में समानता और मंचों पर बड़े-बड़े भाषण, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि राजनीति आज भी जाति, धर्म और वोट बैंक के दलदल में धंसी हुई है। देश को आजाद हुए दशकों बीत गए, लेकिन लोकतंत्र की आत्मा आज भी कराह रही है। नेता जनता के प्रतिनिधि नहीं, बल्कि जातीय समीकरणों के व्यापारी बन चुके हैं। हर चुनाव में वही पुराना खेल, किस जाति के कितने वोट, किस धर्म का कितना ध्रुवीकरण, किस वर्ग को कैसे बांटना है। विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य सब पीछे छूट जाते हैं और आगे रहता है सिर्फ एक गणित, वोट का गणित! सबसे बड़ा विडंबना यह है कि जो संविधान हर नागरिक को समान अधिकार देता है, उसी के नाम पर समाज को टुकड़ों में बांटने की राजनीति की जा रही है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब अब

निष्पक्षता नहीं, बल्कि तुष्टिकरण की राजनीति बन गया है। सत्ता की कुर्सी पाने के लिए नेताओं ने समाज को इस कदर विभाजित कर दिया है कि आज नागरिक पहले अपनी जाति और धर्म से पहचाना जाता है, इंसान बाद में होता है। और सवाल उठता है, क्या यही लोकतंत्र है? जहाँ चुनाव जीतने के लिए समाज को बांटना जरूरी हो, जहाँ विकास की बात करने वाला नेता हाशिए पर हो, जहाँ सच्चाई बोलने वाला देशद्रोही और झूठ फैलाने वाला नायक बन जाए! आरक्षण और सामाजिक न्याय जैसे संवेदनशील मुद्दों को भी वोट की राजनीति का हथियार बना दिया गया है। जिनके उत्थान के लिए नीतियां बनीं, आज वही नीतियां सत्ता की सीढ़ी बन चुकी हैं। सच्चा न्याय कहीं खो गया है, और दिखावा हावी हो गया है। आज जरूरत है इस कड़वी सच्चाई को स्वीकार करने की लोकतंत्र का ढांचा खड़ा है, लेकिन उसकी आत्मा घायल है। जब तक राजनीति जाति और धर्म के चश्मे से बाहर नहीं निकलेगी, तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता। जनता को भी अब जागना होगा। वोट की ताकत को पहचानना होगा। जाति और धर्म के नाम पर बंटने से इनकार करना होगा। वरना वो दिन दूर नहीं जब लोकतंत्र सिर्फ किताबों में रह जाएगा, और हकीकत में देश जातीय ठेकेदारों और राजनीतिक व्यापारियों का अखाड़ा बनकर रह जाएगा। यह वक्त है सवाल पूछने का, यह वक्त है बदलाव का है, वरना इतिहास हमें माफ नहीं करेगा।●

# भाजपा का दो दिवसीय प्रशिक्षण शुरू

● डॉ० लक्ष्मीनारायण सिंह

भाजपा मीडिया प्रभारी डॉ. लक्ष्मी नारायण सिंह पटेल प्रशिक्षकों से कहा है कि प्रशिक्षण एक चिंतन का विषय है। पहले से अभी तक अप्रशिक्षित लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए भेज दी जाती है। अप्रशिक्षित होने के कारण चार ही कार्य होते हैं। नारा लगवाना, माला पहनना, फोटो खिंचवाना तथा अंतिम शिक्षा कार्यकर्ता सगंठन की रीढ़ होती है। अब विस्तार से जाने? कार्यकर्ताओं को विचारधारा, संगठन और चुनावी रणनीति का कार्यकर्ताओं को दिया जाता है प्रशिक्षण भाजपा द्वारा आयोजित जिला स्तरीय प्रशिक्षण शिविर केवल एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि संगठन को वैचारिक रूप से मजबूत बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम माना जाता है। इस प्रकार के शिविरों में पार्टी के बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर तक के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को संगठन की नीति, विचारधारा, अनुशासन, चुनाव प्रबंधन तथा जनसंपर्क की विस्तृत जानकारी दी जाती है। भाजपा का मानना है कि मजबूत संगठन ही चुनावी सफलता और जनविश्वास का सबसे बड़ा आधार होता है। इसी उद्देश्य से समय-समय पर प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाते हैं।

प्रशिक्षण शिविर में कार्यकर्ताओं को पार्टी के इतिहास और वैचारिक पृष्ठभूमि से अवगत कराया जाता है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दिनदयाल तथा अन्य विचारकों के योगदान और "एकात्म मानववाद" की अवधारणा पर विस्तार से चर्चा की जाती है। कार्यकर्ताओं को बताया जाता है कि भाजपा केवल चुनाव जीतने वाली पार्टी नहीं, बल्कि राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक मूल्यों और अंत्योदय की विचारधारा पर चलने वाला संगठन है। शिविर में संगठनात्मक ढांचे की भी गहन जानकारी दी जाती है। बूथ समिति, शक्ति केंद्र, मंडल, जिला और प्रदेश स्तर तक संगठन किस प्रकार कार्य करता है, इसकी पूरी प्रक्रिया समझाई जाती है। प्रत्येक पदाधिकारी की जिम्मेदारी, कार्यशैली और अनुशासन पर विशेष जोर दिया जाता है। पार्टी नेतृत्व कार्यकर्ताओं को यह संदेश देता है कि संगठन में छोटा या बड़ा कोई कार्यकर्ता नहीं होता, बल्कि सभी की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। चुनावी रणनीति प्रशिक्षण शिविर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। कार्यकर्ताओं को बूथ प्रबंधन, मतदाता सूची सत्यापन, घर-घर संपर्क अभियान, मतदान प्रतिशत बढ़ाने तथा सोशल मीडिया के प्रभावी उपयोग की जानकारी दी जाती है। वर्तमान समय में डिजिटल प्रचार की बढ़ती भूमिका को देखते हुए फेसबुक, व्हाट्सऐप, एक्स और अन्य सोशल मीडिया मंचों के उपयोग पर भी प्रशिक्षण दिया जाता है। फर्जी खबरों से बचाव और तथ्य आधारित प्रचार पर भी जोर रहता है।

प्रशिक्षण शिविर में केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी जाती है ताकि कार्यकर्ता जनता तक योजनाओं का लाभ और संदेश पहुंचा सकें। लाभार्थी संपर्क अभियान, जनसमस्याओं के समाधान और जनता के बीच सकारात्मक संवाद स्थापित करने की रणनीति भी सिखाई जाती है। मीडिया प्रबंधन और सार्वजनिक जीवन में व्यवहार पर भी विशेष सत्र आयोजित किए जाते हैं। प्रेस विज्ञप्ति कैसे लिखी जाए, मीडिया से किस प्रकार संवाद किया जाए तथा विपक्ष के आरोपों का संयमित जवाब कैसे दिया जाए, इसकी जानकारी वरिष्ठ नेताओं द्वारा दी जाती है। कार्यकर्ताओं को यह भी बताया जाता है कि सार्वजनिक जीवन में भाषा और व्यवहार की मर्यादा बनाए रखना संगठन की छवि के लिए आवश्यक है। जिला स्तरीय प्रशिक्षण शिविरों में प्रायः वरिष्ठ नेता, सांसद, विधायक और संगठन पदाधिकारी शामिल होकर कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करते हैं। प्रश्नोत्तर सत्र और समूह चर्चा के माध्यम से कार्यकर्ताओं की जिज्ञासाओं का समाधान किया जाता है। शिविर में अनुशासन, समय प्रबंधन और सामूहिक कार्यशैली पर विशेष बल दिया जाता है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि भाजपा की संगठनात्मक मजबूती के पीछे नियमित प्रशिक्षण शिविरों की बड़ी भूमिका रही है। यही कारण है कि पार्टी गांव स्तर तक सक्रिय कार्यकर्ता तैयार करने में सफल रही है। प्रशिक्षण शिविर कार्यकर्ताओं में ऊर्जा, आत्मविश्वास और संगठन के प्रति समर्पण की भावना को मजबूत करने का कार्य करते हैं। भाजपा भाग्य विधाता प्रशिक्षण देन वाले से प्रशिक्षण लेने वाले माग करे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जनहित में चलाई जा रही योजनाओं की सुची तथा योजना से लाभार्थियों की सूची के साथ मुद्रा योजना के सूची प्राप्त करे।●